हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02 00.बजे अपराह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

16.3.2015/1400/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 1393.

श्री सुरेश भारद्वाज़ - अनुपस्थित ।

16.3.2015/1400/negi/ag/2

प्रश्न संख्याः 1532.

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हम जो प्रश्न लिख करके देते हैं उसमें बदलाव हो जाता है, मैंने यह प्रश्न इस ढ़ंग से दिया था कि "क्या यह सत्य है कि 2 वर्षों में जिला बिलासपुर के ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में कुछ उद्योग बन्द हुए, यदि हां तो कितने और इसके क्या कारण रहे" ?"ख" भाग में पूछा था कि "सरकार इन बन्द उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है" ?लेकिन क्वैश्चन की सैंस ही बदल गई है, इसलिए मैं थोड़ा सप्लीमेन्टरी क्वैश्चन करना चाहूंगा । एक तो उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में दो उद्योग बन्द हुए हैं। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उद्योग 2 नहीं 3 बन्द हो गए हैं। दो तो जो सरिया/स्टील की फैक्टरीज़ थी वे बन्द हुए हैं और एक दवाई की भी बहुत बड़ी फैक्टरी थी, वह भी बन्द हुई है । जैसे मैंने पूछा भी था कि तो इन उद्योगों को बन्द करने के कारण क्या रहे ,ज़रा उद्योग मंत्री जी यह स्पष्ट करें । क्योंकि सरिया की और दवाई की फैक्टरी थी इनमें बिजली की खपत ज्यादा होती है ,इस सरकार के बनने के बाद जो बिजली महंगी हुई, इलैक्ट्रिसिटी डियुटि टैक्स महंगे हुए, आई.डी.सी. चार्जिज़ महंगे हुए, तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या यही कारण रहे कि ये उद्योग बन्द हुए और अगर मंत्री जी मानते हैं कि ये कारण रहे तो क्या सरकार बिजली के इन बढ़े हुए रेट्स को कम करने का विचार करती है?
अध्यक्षः माननीय मंत्री जी सूचना दीजिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से तो सहमत हूं कि इनके क्षेत्र में 2 बड़े उद्योग स्थायी तौर से बन्द हुए हैं। इनमें से एक सूरज फैबरिक्स इंडस्ट्रीयल लिमिटिड और एक एस.टी.एस. स्पिन रोलिंग मिल्ज़ लि0 ,ये 2 बड़े कारखाने बन्द हुए हैं । इनके बन्द होने का जो कारण है वह भी मैं आपको बता देता

हूं कि इन्होंने अपना केस बाईफर(BIFR) में डाला है । BIFR का जो फुल फॉर्म है , वह Board for Industrial and Financial Reconstruction है. इन्होंने केस वहां पर डाला है क्योंकि कारखाना घाटे में चला गया और घाटे से ये बाहर आ नहीं पा रहे हैं।

16.3.2015/1400/negi/ag/3

इन्होंने घाटे का कारण जो बताया है उसको भी मैं पढ़ देता हूं। इन दोनों उद्योगों ने जब BIFR में केस डाला तो लिख...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

16/03.2015.1405/यूके/एजी/1
प्रश्न संख्या--1532--जारी----
उद्योग मंत्री --जारी----

तो लिख कर दिया है कि adverse operating and financial leverage resulted into huge loses, sharp fluctuations in raw-material prices, higher financial cost, low yield realization, skewed margins and depressed economic conditions had adverse bearing. तो उन्हानें यह खुद माना है कि कारखाना इतना ज्यादा घाटे में चला गया है कि हम उसको उबार नहीं सकते और जब कारखाना उबार नहीं सकते हैं तो इनसे कर्जे की वसूली न हो इसके लिए इन्होंने यह केस "बाइफर" में डाला हुआ है ताकि इनके लोन को दोबार से कोई रिस्ट्रक्चर कर सके, बैंक इन्स्टीट्यूशन को कह दें कि इनसे पैसा वसूल न किया जाए । तो इन्होंने खुद माना है कि इतने ज्यादा कर्जे हमने उठा लिए हैं और हम यह कर्जा वापिस नहीं कर सकते हैं । तो वे प्राईवेट कारखानेदार हैं । मसला तो लोन वापिस करने का है, अब इनके कारखाने को चलाने से कहीं ज्यादा बड़ा मसला लोन वापिस न करने से जुड़ा हुआ है । दूसरा आपने बिजली की दरों के बारे मे कहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो कारखाना बन्द हुआ है, बिजली की दरें वर्ष 2011-12 में बढ़ी हैं । उस समय आपकी सरकार थी, मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता । लेकिन जब आपने मसला उठाया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 में बिजली की दरें बढ़ीं और इनकी वर्ष 2012-13 की बैलेंस शीट के आधार पर ये "बाइफर" में गये हैं । तो हमारी सरकार के आने से पहले ही ये घाटे मे जा चुके थे । प्राईवेट फर्म घाटे

में जाए उसमें न तो कांग्रेस का दोष है और न ही बी0जे0पी0 का दोष है । वह तो चलाने वालों का दोष है । इसलिए मैं समझता हूं कि जो ये दोनों कारखानें घाटे में गए हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि हम इसको चला नहीं पा रहे हैं । बिजली बोर्ड ने जो इनके ऊपर प्रति किलोवाट से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवेलपमैंट चार्जिज़ लगाए हैं, उसको देने की स्थिति में नहीं हैं । अभी भी इनको बिजली बोर्ड का लगभग एक कारखाने को 1.7 0करोड़ रुपया और दूसरे कारखाने को भी लगभग इतनी ही राशि 1,04, 46,000 रुपए बिजली बोर्ड का देना है । तो जब इनकी वित्तीय स्थिति अलाऊ नहीं कर रही है, हम तो फैसिलिटेटर हैं इंडस्ट्री डिपार्टमैंट के, कि आप कारखाना चलाएं । लेकिन जो लोग घाटे में चले गए, उनको कारखाना कैसे चलाना है, यह उस पार्टी को देखना है ।

16/03.2015.1405/यूके/एजी/2

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्योग घाटे में चले गए हैं । उद्योग मंत्री जी भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार औद्योगिक पैकेज दे रही थी । जब तक उस पैकेज का लाभ मिलता रहा ये उद्योग लाभ में चलते रहे और चलते भी रहे । परन्तु जैसे ही पैकेज खत्म हुआ और सरकार बदल गयी । तो ये उद्योग बन्द कर के चले गए । आज उसके कारण उस क्षेत्र में लगभग ढाई हजार परिवारों का रोजगार कम हो गया । दो हजार लोगों को डायरैक्ट रोजगार प्राप्त था और बाकियों को ट्रोसपोर्टेशन और बाकी कामों के रुप में रोजगार मिला हुआ था और मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा रोल सिफ फैसिलिटेटर का है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई उद्योग सरकार से लाभ या इन्सैंटिव लेकर, जब तक इन्सैंटिव मिल रहे हैं तब तक चलाता रहे और जैसे ही इन्सैंटिव मिलना बन्द हो जाए तो फिर वे उद्योग बन्द करके चले जाएं और सरकार चुपचाप देखती रहे । क्या यह ठीक है? क्या सरकार यह देखती रहे और इतने परिवारों के रोगजार की चिंता सरकार नहीं करेगी ? दूसरे जो बिजली की बात ये कर रहे हैं, IDC चार्जिज़ इस सरकार के समय बढ़े और उनकी जो इन्होंने राशि बतायी है, वह बकाया राशि वर्ष 2003 से मांग रहे हैं, जब से वह यूनिट बनना शुरु हुआ । इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जिज़ तो तभी लगे । वे बैक डेट से मांग रहे हैं । इसलिए जो भी ढाई-तीन करोड़ दोनो यूनिट्स का बनता है ,वह भी पिछली डेट से उनसे मांगा गया । इसलिए हम जब एज़ एम0एल0ए0 उनसे हमने बात की तो वे हमें तो यही कहते हैं कि ये IDC चार्जिज़

हमारे ऊपर इतने करोड़ों रूपए का लगा दिया है। मैने मंत्री जी से मिल कर भी बात की थी इसको आप विदड्रॉ करवाओ। वह विदड्रॉ नहीं हुए। हमारे पास तो यह कहते हैं। इनके पास ये कहते हैं कि हम घाटे में चले गए और इसलिए हमें बैंकों का ऋण नहीं देना। परन्तु मेरा मंत्री जी से यह पूछना है कि इस तरह जो उद्योग इन्सैंटिव ले कर, बाद में घाटा शो कर के बैंकों का ऋण भी खाएंगे, फाईनैशियल कारपोरेशन का ऋण भी खांएंगे। क्या सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी ?

दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जी ने कहा कि सरकार फैसीलिटेट करती है, ये जब से उद्योग मंत्री बने हैं, औद्योगिक निवेश के

16/03.2015.1405/यूके/एजी/3

लिए मुम्बई तक भी घूमे और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी ले गए, वहां से आने के बाद इनकी स्टेटमेंट्स आए दिन रही हैं। करोड़ों रुपए इनवैस्टमैंट

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1410/sls-jt-1

प्रश्न संख्या : 1532... जारी

श्री रणधीर शर्मा ... जारी

वहां से आने के बाद इनकी स्टेटमैंट्स आई कि यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों रुपये इनवैस्ट करने के लिए आ रहे हैं।... (व्यवधान)...

अध्यक्ष : इसका संबंध इस प्रश्न से नहीं है। इसके लिए आप सैपेरेट प्रश्न कीजिए। This is a different question. This is not connected with it.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, संबंध है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वह उद्योग बंद हो गए; उद्योगों के मालिक उनको नहीं चला सकते, तो उद्योग मंत्री जो नया निवेश ला रहे हैं, वह उद्योग ऊना और हरोली में ही क्यों खुल रहे हैं? ऐसे उद्योग क्षेत्र, जहां पर उद्योग बंद होने से बेरोज़गारी बढ़ गई, लोगों का काम-धंधा बंद हो

गया, क्या उन नए उद्योगों को ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में खुलवाने के लिए मंत्री महोदय प्रयास करेंगे?

अध्यक्ष : पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि उद्योग संबंधित उद्योगपतियों ने स्वयं बंद किए हैं, इन्होंने बंद नहीं किए हैं। मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दे दिया है और अब दोबारा उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मूल प्रश्न का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उन उद्योगपतियों पर क्या कार्रवाई की गई। उद्योग BIFR में चला गया और उद्योगपति ने वहां पर जाकर घुटने टेक दिए कि हम यह कारखाना नहीं चला सकते, हमारा लोन माफ़ करवाया जाए, हम नहीं दे सकते। इंडस्ट्रियलिस्ट BIFR में कब जाता है? जब उसको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं और अब मैं इससे निकल नहीं सकता। उनका सारा प्रयास यह है कि जो उन दो उद्योगों के ऊपर 86 करोड़ रुपये का कर्ज़ा है; वह प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों या फाईनैंशियल इंस्टिच्यूशन्ज का यह कर्ज़ा हमें वापिस न देना पड़े। इसलिए ही वह BIFR में गए हैं। वह बता कर गए हैं कि हम देने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा

16.03.2015/1410/sls-jt-2

प्रदेश में जो 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होना है ,वह कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। आपके ही औद्योगिक क्षेत्र में 9 नए औद्योगिक यूनिट आ रहे हैं and are expected to commence production. इनके नाम मेरे पास हैं और मैं आपको बता भी सकता हूं। लेकिन स्टील इंडस्ट्री में सारे देश में रिशैसन या ग्लट का दौर चल रहा है; उनको प्राब्लम है, इसलिए वह पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं। ये प्राईवेट कंपनीज हैं। हमें भी मालूम है कि इन कारखानों में हिमाचली मूल के 315 लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड के चार्जिज हैं, इन्हें आप समाप्त नहीं करवा सके। इसके बारे में बिजली बोर्ड को विचार करना है। उद्योग विभाग अपने तौर पर लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन जहां तक आपका यह कहना है कि हम देश के विभिन्न राज्यों में गए; उसमें हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्री प्रदेश में आए, इसलिए ही हम महाराष्ट्र में गए ,गुजरात में गए, कर्नाटक में भी गए और पूंजीनिवेश आ रहा है। लेकिन स्टील के कारखानों का ऐसा दौर चल रहा है

जिस वजह से वह इसको आगे रन करने की स्थिति में नहीं हैं। यह नहीं है कि ऊना में ही कारखाने आ रहे हैं।9 कारखाने तो आपके यहां आ रहे हैं। आपके वहां तो हम और एरिया भी इंडस्ट्री के लिए अधिकृत कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह कहना चाहूंगा कि इन कारखानों की पूर्ण स्थिति आपके ज़हन में है। आप जानते हैं कि ये कारखाने घाटे में गए हैं। आप यह जानते हैं कि ये कारखाने चलाए नहीं जा सकते। आप यह भी जानते हैं कि ये BIFR में जा चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि ये कर्ज़ा वापिस करने की स्थिति में नहीं हैं। जो वार्षिक योजना की चर्चा का समय था, उस समय भी आपने यह सवाल किया था और उस समय भी हमने विस्तृत उत्तर दिया था। ये कारखानेदार आपको भी जानते हैं और विभाग में हमारे पास भी इन्होंने रिप्रजैंट किया था। लेकिन ये अब वह चलाने की स्थिति में नहीं हैं। BIFR में कोई भी उसी स्थिति में जाता है जब उसके हाथ पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा था कि आपके प्रश्न बदल दिए जाते हैं। आपकी सूचना के लिए मैंने अभी सचिवालय से आपका सवाल मंगवाया था। आपका सवाल

16.03.2015/1410/sls-jt-3

वही है जो यहां पर आया है और यही आपने लिखकर दिया है। You can verify it. कोई भी चीज इसमें बदली नहीं गई है। आपको कैसे लगा कि यह बदल दिया गया है?

समाप्त

16/03/2015/1415/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1533

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न में जो जानना चाहा था वह जवाब नहीं आया। वर्दियां खरीदने के लिए सैम्पल्ज लिए जाते हैं और सैम्पल मेरे पास यहां है। सैम्पल में कॉटन और पौलिस्टर की रेशो क्या थी? जो सप्लाई ऑर्डर्ज हुए उनके मुताबिक क्या ये वर्दियां आईं? मैंने पहले भी पूछा था कि उन वर्दियों में क्या आपने यह सुनिश्चित किया कि पॉलिस्टर और कॉटन की रेशो कितनी है? आदेश हुए और वर्दियां आ गईं। क्या आपने उनकी ऐट रैनडम चैकिंग नहीं करवाई कि are they according to the sample? सारे प्रदेश में वर्दियां बंट गईं। जब रैनडम चैकिंग के रिज़ल्ट्ज आए, तो वे सैम्पल्ज के मुताबिक नहीं थे। बच्चों को घटिया वर्दियां मिलीं जो दो साल से मिल रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले साल भी मैंने यह प्रश्न किया था। ऐट रैनडम चैकिंग नहीं करके आपने उन वर्दियों का वितरण कैसे कर दिया, आपको कैसे पता लगा कि सप्लाई सैम्पल्ज के मुताबिक है? अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये सैम्पल्ज कब पास हुए और जो वर्दियां वहां से सप्लाई हुईं उसके लिए किसने आदेश किया ,निगम ने किया होगा और आदेश अगर किया, तो रिजल्ट आने से पहले उनका वितरण क्यों हुआ और सारे प्रदेश में बच्चों को जो घटिया वर्दियां मिलीं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय ,ये वर्दियां का कपड़ा नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा खरीदा जाता है ,शिक्षा विभाग द्वारा नहीं। मगर मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 193 में से 27 सैम्पल्ज ठीक नहीं पाए गए और इस संदर्भ में जिन लोगों के सैम्पल्ज फेल हुए हैं उन कम्पनियों को तीन करोड़ 88 ,लाख रुपये की पैनल्टी लगाई गई है। भविष्य में जो श्री ईश्वर दास धीमान का सुझाव है कि सैम्पल्ज की रैनडम चैकिंग होनी चाहिए। मैं नागरिक आपूर्ति निगम को यह कहूंगा कि माननीय विधायक का सुझाव बिल्कुल ठीक है कि जब कपड़ा आता है, इससे पहले कि उसका वितरण वर्दियां बनाने के लिए करें, उससे पहले उसकी चैकिंग होनी चाहिए।

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि इतने में से इतने सैम्पल्ज फेल हो गए। प्रश्न यह है कि जो घटिया वर्दी बच्चो को मिलीं और यह

16/03/2015/1415/RG/JT/2

पिछले दो वर्षों से मिल रही हैं। अब तो मैंने इस बारे में प्रश्न कर दिया, पहले भी प्रश्न किया था, लेकिन वह किसी और तरह का प्रश्न था। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यदि इस प्रक्रिया को बदला है, तो किसने बदला है? वर्दियां बांटने से पहले ऐट रैनडम चैकिंग क्यों नहीं की गई और जो प्रक्रिया बांटने की बदल दी, क्यों बदल दी और जो बच्चो को घटिया वर्दी मिल रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है?

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी मुख्य मंत्री शुरू

16/3/2015/1420/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1533क्रमागत----

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि 193 सैम्पल्ज की चैकिंग हुई है और उनमें से 27ठीक नहीं पाए गए हैं। बाकी सैम्पल ठीक थे और इस संदर्भ में जैसे हमने कहा कि कारपोरेशन ने उन लोगों के ऊपर जिनके सैम्पल्ज ठीक नहीं पाए गए 3 , करोड़ 88 लाख रूपये की पैनल्टी लगाई है। आप यह कह रहे हैं कि डिफैक्टिव कपड़े से जो वर्दी बन गई है ,उसका क्या होगा ?मेरा यह कहना है कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि इस किस्म की गलती न हो।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री महोदय को देना चाहिए था। प्रश्न है कि दो वर्षों में जितनी वर्दियां दी गईं, उनमें रैन्डम चैक थोड़ा सा किया गया और उस थोड़े से रैन्डम चैक में ही अगर इतनी अनियमितता पाई गई है तो जो बल्क में दो वर्षों में वर्दियां खरीदी गई हैं, उनमें कितना बड़ा घोटाला होगा? जो इस प्रदेश के नन्हें-मुन्हें

बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके लिए क्या कोई अधिकारी जिम्मेवार है या मंत्री महोदय जिम्मेवार है या अन्य कोई कमेटी उसके लिए जिम्मेवार है? यही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

Chief Minister: This question actually pertains to his department. It is wrongly referred Education Department.

अध्यक्षः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: Sometime it is shocking. The Hon'ble Member has a habit of scandalizing everything. This is a Committee which was same Committee in the BJP rule and same Committee is today. और माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री तक तो यह फाइल आती भी नहीं है। नीचे इनकी कमेटी है जिसमें शिक्षा विभाग के लोग व

16/3/2015/1420/MS/AG/2

सिविल सप्लाइज कारपोरेशन के एम0डी0 हैं। जो ये सैम्पल लिए गए ,सैम्पल उन्हीं के लिए जाते हैं जो उस वक्त माल वे हमें देते हैं। उस सैम्पल को टैस्ट के लिए भेजते हैं और टैस्ट रिपोर्ट आती हैं। ये 193 सैम्पल लिए गए हैं। इसमें 50.5परसेंट सैम्पल्ज लेना अनिवार्य है। टैण्डर कण्डीशन्ज के मुताबिक उतने सेम(same) सैम्पल्ज लिए गए। उसमें से जो सैम्पल्ज गलत हुए, उसके लिए 3 करोड़ 99 लाख रूपये की उनको पैनल्टी लगा दी है। अब उसको सेंसेटाइज करना और यह कहना कि उससे पिछले वर्ष भी ऐसा ही था। मेरा यह कहना है कि इसको रूटीन में चैक करते हैं और आप से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों ने जो किया वह लोगों के सामने आएगा।

अध्यक्षः धूमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लेस करने से पहले सैम्पल इसीलिए लिए जाते हैं कि जब बाद में बल्क में सप्लाई हो तो उसमें हेराफेरी न हो। जो सैम्पल्ज लेकर रखे जाते हैं, उसके साथ सप्लाई को कम्पेयर किया जाता है। एक पहलू इसका यह है कि क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी? दूसरा, अध्यक्ष जी जिस बच्चे को साल के लिए वर्दी मिल गई और घटिया वर्दी मिल गई, क्या उसको कम्पनसेट करेंगे? आप यह कह रहे हैं कि 3 करोड़ 88 लाख रूपये की पैनल्टी लगा दी। वह तो सरकार के खजाने में आएगा लेकिन जिस बच्चे को घटिया वर्दी मिली क्या उसको नई वर्दी उस घटिया वर्दी के बदले में सप्लाई की जाएगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, अगर ऐसा कोई क्लेम बच्चे की ओर से पर्सनली आता है कि मुझे घटिया वर्दी मिली है तो हम इन पैसों से उसको नई वर्दी लेकर के देंगे। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। If any claim comes then we will ensure that this money can be spent for compensating that child. I have given the reply to the Hon'ble Leader of the Opposition that अगर किसी बच्चे की ओर से क्लेम आता है कि जो वर्दी मुझे मिली वह घटिया थी और फट गई, उसको हम इस पैसे में से ही कम्पनसेट कर देंगे।

16/3/2015/1420/MS/AG/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार विभाग से कहकर हर स्कूल से रिपोर्ट ले कि किस बच्चे को गलत वर्दी मिली है। उसको कम्पनसेट करे। पहला प्वांयट यह है। दूसरा प्वायंट मैंने यह कहा था कि ,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

16.3.2015/1425/जेके/एजी1/
प्रश्न संख्याः----------1533जारी------
प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः---- जारी----
दूसरे, मैंने कहा था कि मंत्री तक तो फाईल आती ही नहीं। मंत्री जांच के दायरे से बाहर हो जाए। क्या बाकियों की जांच होगी जिन्होंने फाईल तैयार की थी? क्या उन पर कार्रवाई होगी?

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय महेन्द्र सिंह जी आप बैठे-बैठे मत बोला करें। माननीय अध्यक्ष महोदय Member should know, इनको भी मंत्री बनने का काफी एक्सपीरियंस हो गया है। बैठे-बैठे बोलने का सदन में मतलब नहीं बनता है।

Speaker: Please keep quiet.

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानते हुए कि इसमें कमी आई है और यह कमी पहली बार नहीं हुई कि सैम्पल्ज़ एक ही बार फेल हुए हैं। मैं माननीय सदन को विश्वास देना चाहता हूं कि जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और श्री ईश्वर दास धीमान जी ने कहा कि हम उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जो इनका सुझाव है उसमें आगे यह भी करेंगे कि जब वर्दियों का लॉट आएगा तो फिर उस लॉट में से हम कितने सैम्पल्ज कर सकते हैं और जो परसेंटेज रखी है उसमें से उतने सैम्पल्ज लिये और डिपार्टमैंट ने चैक करवाए अगर कोई पर्दा डालने की बात होती तो हम उस वक्त पर्दा डालते। हमने उन पर 3 करोड़ 90 लाख रूपये तक की पैनल्टी लगाई है। कौन सप्लायर है, वह वही सप्लायर है जो आपके समय में भी वर्दी देता था? माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस हाऊस को एन्श्योर करता हूं कि जो भी प्रोक्योरमैंट कमेटी के चेयरमैन है उनको हम आदेश देंगे कि यह सुनिश्चित करें कि अगर यह सप्लायर हैबिचुअल ऑफैंडर है, इनके 4-3 सालों के सैम्पल्ज देख लो और उसकी रिपोर्ट पूरी की पूरी मेरे पास है। इनके ऊपर पक्का कार्रवाई की जाएगी ,ऐक्शन लिया जायगा ,यह मैं सदन को आश्वासन देता हूं।

16.3.2015/1425/जेके/एजी2/

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि अगर इसमें गड़बड़ हुई है और वह habitual offender as per Minister's statement है तो फिर आपने उसको ऑर्डर क्यों दिया? फिर ऑर्डर क्यों प्लेस किया गया? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसकी जांच करेंगे जो हुआ है? जो तीन साल पहले गलत हुआ है और अब गलत हुआ है उसकी जांच करेंगे?

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि हम उसकी जांच करवाएंगे। जो अधिकारी जांच करेंगे आप उन पर विश्वास रखिये और पूरी जांच करवा कर देंगे। इसी सत्र में जांच का जवाब दूंगा। लेकिन मैं इससे पहले हाऊस के सामने सत्य बात करना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में सिर्फ 12 लाख से लेकर 16 लाख रूपये तक पैनल्टी लगी। वर्ष 2013-14 में यह सरकार आई और ट्रांसपेरैंसी सामने आई 4 करोड़ 56 लाख रूपये पैनल्टी लगाई गई। वर्ष 2014-15 में 3 करोड़ 88 लाख रूपये की पैनल्टी लगी जहां-जहां सैम्पल्ज़ फेल पाए गए और किसी ने कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं की है । जैसे कि मैंने यहां पर कहा है कि मैं इसी सदन में इस जांच की रिपोर्ट लेकर आऊंगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय मंत्री जी ने बड़ी उपलब्धि बताई है कि इन्होंने बड़ी पैनल्टी लगाई है। यह ट्रांसपेरैंसी नहीं सबसे ज्यादा हेराफेरी हो रही है। वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस करके ज्यादा भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। अगर 12-13 लाख की गलत पैनल्टी लगी थी तो उसके बाद आपने ऑर्डर क्यों दिया? फिर उसके बाद 4 करोड़ 56 लाख की पैनल्टी भी आपने उसी फर्म को लगाई फिर भी ऑर्डर उसी को दिया और अब 3 करोड़ 88 लाख की लगाई है। इसमें तो काफी घाला-माला है।

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: Even during the BJP period post supply sample जो सप्लाई सैम्पल्ज लिए जाते थे अब नहीं होते हैं।

16.3.2015/1425/जेके/एजी3/

अब आपको हर चीज में घाला-माला नज़र आ रहा है। इधर कुछ नहीं है और उधर ही है काला-काला। अब महेन्द्र सिंह जी मैं गुस्से में आ रहा हूं और मैंने आपको यह कह दिया है। आज तक मैं आपको सहन ही कर रहा था। अब मैं अपने मूढ़ में आ गया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय enough is enough. यह मैंने बता दिया कि पहले भी सैम्पल्ज होते थे और अब भी लिये जाएंगे। They want to delay. ये सरकार के अच्छे प्रोजैक्टस को चलने नहीं देना चाहते हैं। किसी काम को होने नहीं देना चाहते। यह इनकी मंशा है कि अच्छे काम न हो। । charge you. यह मैंने कह दिया है कि मैं इसकी जांच करूंगा और इस बजट सत्र में ही इसकी रिपोर्ट लाई जाएगी।

Speaker: You choose a good supplier who is not dishonest.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, ज्यादा जोर से बोल कर बात सत्य नहीं होती।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---------

16.03.2015/1430/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 1533 क्रमागत

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

माननीय मंत्री रिकॉर्ड निकालें, इन्होंने खुद कहा कि यही कम्पनी सप्लाई करती थी और पहले से गलत होता था। फिर आपने दो साल ऑर्डर उस कम्पनी को क्यों दिया? अब आपको कष्ट हो रहा है कि घालामाला है, काला है, तुम ज्यादा गोरे हो और इधर काले हैं तो अब गोरे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो 12-13 लाख की पैनल्टी लगती थी, वह 4 करोड़ 56 लाख और 3 करोड़ 88 लाख रुपये की लग रही है। इसका मतलब ज्यादा गलतियां पकड़ी जा रही हैं तो फिर उसी कम्पनी को बार-बार सप्लाई ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन उत्तेजित हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये जो 12-16 लाख है उसको दूसरी तरफ देख लें। मेरा यह कहना है कि 4 करोड़ 45 लाख रुपये से ज्यादा पैनल्टी लगनी चाहिए थी, इन्होंने सिर्फ 12-16 लाख रुपये लगाई। बाकी घपला किया। अब आप उसका जवाब दे दो। उस वक्त आपने ज्यादा सैम्पल क्यों नहीं पकड़े? उस टाइम आपने हेराफेरी क्यों नहीं पकड़ी? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इसका टैंडर होता है और टैंडर का पूरा प्रोसैस होने के बाद आगे कार्रवाई होती है। अगर यह एस्टैब्लिश हुआ कि ये हैबिचुअल ऑफैंडर हैं तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इनको बैन करने से भी सरकार नहीं चूकेगी, आपने जितना मर्जी लिहाज़ किया हो।

Speaker: He is enquiring into the matter. इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि कोई घपला निकलेगा तो कार्रवाई करेंगे।

प्रश्न समाप्त

16.03.2015/1430/SS-JT/2

प्रश्न संख्याः 1534

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्रित करने में कितना समय लगेगा? यह बड़ा मुख्य प्रश्न है।
अध्यक्षः अगर आपके पास सूचना है तो दे दीजिए। मंत्री जी के पास तो सूचना नहीं है।

श्री राम कुमारः हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं उनके लिए Corporate Social Responsibility कानून बना है। उसके तहत उन उद्योगों को पैसा देना होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इसका फार्मूला क्या है और इसकी समय-सीमा तय करें कि कितने समय में इसकी इंफोरमेशन आ जायेगी?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, वैसे तो हमने यह कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इन्होंने फार्मूले की बात की है। मोटे तौर पर जो फार्मूला तय है उसमें जिस कारखाने का टर्नऑवर 1 हजार करोड़ रुपया है वह इसके दायरे में आता है। जिस कारखाने की नैट वर्थ 500 करोड़ रुपया है वह इसके दायरे में आता है या जिन कारखानों का प्रॉफिट 5 करोड़ के आस-पास है तो इनमें से either of the conditions जो भी मीट करते हैं वे इसके दायरे में आते हैं। यह राशि किसी सरकार को उपलब्ध नहीं करवाई जानी है। सरकार का इसमें कोई सरोकार नहीं है और प्रदेश सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं है और कोई अगर कार्रवाई इनके खिलाफ हो भी सकती होगी तो या तो केन्द्र सरकार कर सकती होगी या रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी कर सकते होंगे। यह बात हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यह जो 2 परसैंट कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी पॉलिसी के तहत हर कम्पनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करता है कि उनको यह पैसा देना है या किस काम के लिए पैसा देना है। इसमें कुछ चीज़ें निर्धारित की गई हैं कि इन-इन चीज़ों पर खर्च

किया जा सकता है और अगर कारखानों को नहीं देना है तो वे लॉजिक के साथ जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों नहीं यह पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा है वह बहुत लैंथी है। 1897 उद्योगों में से कितने उद्योगों ने यह राशि नहीं दी है। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि उसके दायरे में कितने आते हैं।

16.03.2015/1430/SS-JT/3

अध्यक्षः माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जो 2परसैंट कारपोरेट सोशल सैस है क्या उन्हें कुछ इंडस्ट्री नहीं दे रही हैं और उसको कहां इस्तेमाल किया जा रहा है?
उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह किसी को नहीं देना है। उनको खुद ही खर्च करना है। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि जो ये 1897 कारखानों की बात कर रहे हैं इसके दायरे में कितने आते हैं..

जारी श्रीमती के0एस0

/1435/16.03.2015केएस/जेटी/1
प्रश्न संख्या- 1534 जारी---
उद्योग मंत्री जारी---

पहले तो यह देखना पड़ेगा कि जो 1897 कारखानों की ये बात कर रहे हैं, इनमें से इसके दायरे में कितने आते हैं? इन्होंने कहा कि इस पर ऐक्शन क्या लेंगें, हमारे दायरे में कोई ऐक्शन नहीं है। कार्पोरेट मिनिस्ट्री, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ही कुछ कर सकती है । हम यह आंकड़ा जरूर पता लगवा सकते हैं हालांकि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कब तक करवा सकते हैं ,मुझे नहीं लगता कि इस सत्र के दौरान हम इस जानकारी को दे पाएंगें।

Speaker: Hon. Minister, this fund is not under the control of the Government?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ज्यादा खर्च है । सरकार को यह पैसा आना नहीं है, यह कारखानों को खुद खर्च करना होता है । हम मोटिवेशन का अभियान चलाएंगें कि जो लोग देने के दायरे में हैं उनको कहेंगे कि

आप दें और राम कुमार जी बद्दी-बरोटीवाला के माननीय एम.एल.ए. हैं इनको भी मालूम है कि किन कारखानों की पांच करोड़ से ज्यादा इन्कम है।

अध्यक्षः इस फंड पर आपका क्या कंट्रोल है?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती और कानून में भी यह प्रावधान नहीं है।

/1435/16.03.2015केएस/जेटी/2

Speaker: This fund is not under the control of the Government.

उद्योग मंत्री :जी, सर।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारे यहां पर उद्योग लगे हैं।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो कारखाने इस राशि के दायरे में आते हैं, उनको मोटिवेट करेंगें कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोकल एम.एल.ए. हैं, उनके साथ बातचीत करें और अगर वे कुछ पैसा दे सकते हैं तो वे जरूर कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी पर लगाएं अदरवाईज़ अभी तक कानून के दायरे में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। कार्पोरेट मिनिस्ट्री या रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ जो हैं, वे इनके बारे में क्या ऐक्शन ले सकते हैं, उनसे इस बारे में बात की जाएगी।

अध्यक्षः श्री राम कुमार जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, यह हमें समझ नहीं आ रहा है?

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं सजा देने के हक में नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार सुनिश्चित करें, सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। उद्योग हिमाचल में लगे हैं सरकार यह सुनिश्चित करें कि वहां लोकल एरिया की ड्वैल्पमैंट में उनका सहयोग हो । सरकार इसको सुनिश्चित करें या इस बारे में बिल लाए।

/1435/16.03.2015केएस/जेटी/3

अध्यक्षः इनका यह कहना है कि Corporate Social Responsibility Policy फंड को ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने इस बारे में कोई कानून बनाया है तो साथ में कोई ऐसी बांइडिंग नहीं लगाई है कि उनको काई सजा का प्रावधान किया जा सके, उनको प्रताड़ित किया जा सके। यह जो मुनाफा आ रहा है उसका दो प्रतिशत, जिनका पांच करोड़ से ज्यादा मुनाफा साल के अंदर है वे दो प्रतिशत लगा सकते हैं। हम उनको मोटिवेट करेंगें और जो इस दायरे में आते होंगें उनको हम जरूर कहेंगें कि आप लोकल एरिया की डवैल्पमैंट में भागीदार बनें।

प्रश्न समाप्त

/1435/16.03.2015केएस/जेटी/4

प्रश्न संख्या 1535

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें कुछ भी नहीं है और हरेक बार जब हम प्रश्न लगाते हैं, भाई राम कुमार जी ठीक कह रहे हैं, या उसमें लिखा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, या जो हमारे स्टार्ड क्वैश्चन होते हैं, उनको अनस्टार्ड किया जाता है । अब यह जो प्रश्न मैंने लगाया है, इसके जवाब में कहा गया है कि सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। विधान सभा क्षेत्र में उस ठेकेदार का नाम दिया है जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में बैठा हुआ है। उस एक ठेकेदार का नाम दिया है बाकी किसी ठेकेदार के नाम नहीं दिए है। जो वर्ल्ड बैंक फंडिड और स्टेट रोड़ प्रोजैक्ट फंडिड हैं ,उसमें बहुत से काम लगे हुए हैं और एक सड़क का नाम दिया है जिसका ठेकेदार मर चुका है। कृपया मेरे प्रश्न का जवाब पूरा नहीं है तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे प्रश्न का पूर्णतया उत्तर दें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कुछ ठेकों के बारे में पूछा था जो कि 1 जनवरी, 2012 से 15 फरवरी, 2015 तक के हैं, उसके बारे में हमने सूचना दे दी है। बाकी ये और क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं?
श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट फंडिड रोड़्ज़ हैं, उनमें अभी भी काम लगे हुए हैं। उसके लिए हर साल बजट आता है । मैं

/1435/16.03.2015केएस/जेटी/5

माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ककीरा- तलारा रोड़ है, सिंहुता-छसकर रोड़ है, बसोल्दा-

श्रीमती अ0व0 द्वारा----

16.3.2015/1440/ag/av/1
प्रश्न संख्या : 1535 ----------क्रमागत
श्री बिक्रम सिंह जरयाल--------जारी

बसौलदा-नाणा रोड है, जोला-बठेड़ रोड है; ऐसे बहुत रोड हैं जो स्टेट फण्डिंग में हैं। उनके बारे में कोई भी ब्योरा नहीं दिया गया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि मुझे इस प्रश्न का पूरा उत्तर दिया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दिनांक 1.1.2012 से 15 2.2015.तक दिए गए ठेकों के बारे में प्रश्न पूछा था। उसके बारे में पूरी सूचना दे दी गई है। अगर आप और सूचना चाहते हैं तो आप मुझे पत्र लिखिए, मैं आपको उस बारे में पूरी सूचना भेज दूंगा।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, स्पोट पर जाकर लोक निर्माण विभाग के लोगों से पूछा जाता है कि यह काम किस हैड के तहत लगा हुआ है? मुझे लगता है कि वहीं से उत्तर दे दिया जाता है। इस प्रश्न को लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ककीरा-तलारा रोड वाया बड़ींगी सब-डिविजन च्वाड़ी के अंतर्गत आता है। सिंयुता-छछकड़ रोड सब डिविजन सिंयुता के तहत आता है। बसौलदा-

नाणा रोड सब डिविजन सिंयुता के अण्डर आता है। जोला-बठैड़ रोड इत्यादि इन सभी रोड्ज का काम अभी भी लगा हुआ है। ये रोड हर साल बजट में पड़ते हैं। इनका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं दिया जाता, कृपया मुझे इसका कारण बताया जाए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्य ने उन ठेकों के बारे में प्रश्न पूछा है जो दिनांक 1.1.2012 से 15 2.2015.तक दिए हैं। अब आप दूसरे ठेकों की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई और सूचना चाहते हैं तो मुझे पत्र लिखिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि ये काम टाइम बाउंड हो रहे हैं या नहीं?

16.3.2015/1440/ag/av/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब मैं उनके बारे में कुछ कैसे कह दूं जब माननीय सदस्य ने उनके बारे में प्रश्न ही नहीं किया। आप जिस भी सड़क की सूचना चाहते हैं आप मुझे उसके बारे में पत्र लिखिए, आपको उसकी विस्तृत सूचना भेज दी जायेगी।

समाप्त

16.3.2015/1440/ag/av/3

प्रश्न संख्या : 1536

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संस्थान की नोटिफिकेशन कब हुई थी? पहले इसकी नोटिफिकेशन मेरे कुटलैहड़ क्षेत्र के अंतर्गत लमलेहड़ी नामक स्थान के लिए हुई थी और वहां इसके लिए भूमि का चयन भी कर लिया था। वहां पर एक हजार कैनाल से अधिक जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। मगर सरकार बदलते ही इसका स्थान बदल दिया गया और वहां पर जमीन भी कम है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर विभाग ने वहां वर्षों से एक नर्सरी चलाई हुई थी। मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर तीन हजार से ज्यादा पौधे आज भी हैं। उन पौधों को अब काटा जा रहा है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस

संस्थान को अब लमलैहड़ी की बजाय सलोह में किया जा रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसको पी.पी.पी. मोड में बनाया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन से लोग, उद्योगपति या बड़े लोग हैं; जो इसको बनाने में आगे आए हैं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वर्ष 2011 में 20 इनस्टिच्यूट खोलने की बात गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने की थी और यह गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का प्रोजैक्ट था—

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

16.3.2015/1445/negi/ag/1
प्रश्न संख्याः ..1536जारी..

मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री.. जारी..
गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया का प्रोजेक्ट था और उस वक्त की सरकार ने ये 20, IIIT पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खोलने थे । इसमें 50:35:15 की रेशो थी, जो सेन्टर गवर्नमैन्ट, स्टेट गवर्नमैन्ट और प्राइवेट पार्टीज़ ने खोलना था। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र से टीम आई और उस टीम ने 2-3 जगह देखी, फाइनली उन्होंने गांव सलोह, ऊना में उसका चयन किया । सेन्टर की टीम ने वहां पर 635 कनाल ज़मीन चयन किया और उसके मुताबिक वहां पर यह इंस्टीट्युट खुल रहा है। इसकी क्लासिज़ भी स्टार्ट हो गई हैं जो NIT, हमीरपुर में चल रही हैं और उस इंस्टीट्युट को बनाने का काम भी चल रहा है ।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मांगी थी लेकिन वह नहीं मिली, इसको सभापटल पर रखा जाए कि नोटिफिकेशन क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैसे उसकी शुरूआत हो रही है और कहां के लिए इसकी शुरूआत हो रही है ? पहले यह ज़मीन लम्लहड़ी के लिए चयनित थी तो दोबारा इसको कैसे बदला गया?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका अब फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है । गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया के आदेशानुसार इसकी क्लासिज़ NIT, हमीरपुर में चल रही है । जो साईट मैंने बताई वहां पर

कंस्ट्रक्शन चल रही है और फैक्ल्टी को रखने की प्रोसैस चल रहा है । तो ये तीनों चीज़ें हो रही है ।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर मांग रहा हूं लेकिन मंत्री जी दे नही रहे हैं ।

16.3.2015/1445/negi/ag/2

अध्यक्षः काम शुरू हो गया है ।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष जी, मैं जगह की बात कर रहा हूं। वहां पर 3 हजार से ज्यादा पौधे काटे जा रहे हैं। ऐसी क्या सरकार की मज़बूरी है कि उन 3 हजार पौधों को काटा जा रहा है जो वर्षों से हार्टिकल्चर विभाग ने उस नर्सरी को तैयार किया है। क्या जिला ऊना में और जगह सरकार को उपलब्ध नहीं हुई ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि IIIT की जो नोटिफिकेशन हुई है उसकी कॉपी सभापटल पर रखा जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जो कॉपी है वह भी सभापटल पर रख दूंगा । 8 मार्च, 2013 को सिलेक्शन कमेटी आई और उन्होंने अप्रूव किया है।...(व्यवधान) ...मैं कह रहा हूं कि 2011 को यू.पी.ए. सरकार ने, गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया ने 20, IIIT बनाने का प्रस्ताव किया। आप रिकार्ड चैक कर सकते हैं। वर्ष 2013 में सिलेक्शन हुई है । ...(व्यवधान)..

श्री वीरेन्द्र कंवरः मुझे वर्ष 2011 की नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए कि यह कैसे हो गई? माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर के मंत्री ने उसका शिलान्यास कैसे कर दिया ? जब केन्द्र सरकार ने उसको दिया और कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तो हमारे जिला के मंत्री ने, मैं तो जिला का मंत्री ही कहूंगा, जिला का नहीं बल्कि कॉंस्टिच्युएंसी का मंत्री कहूंगा, जो ऊना जिला में खुल रही थी उसको अपनी विधान सभा कांस्टिच्युएंसी में ले करके चले गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कोड ऑफ कंडक्ट में उसका शिलान्यास कर सकते थे? क्या

केन्द्र सरकार से इसकी कोई परमिशन ली गई? मैं उस नोटिफिकेशन की कापी चाहता हूं।

अध्यक्षः शिलान्यास हो गया है।

मा0 मंत्री श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

16/03.2015.14/50यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या--1536 :जारी----

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री--जारी----

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोनों की पुष्टि कर देता हूं । भाई वीरेन्द्र जी, मैं कॉपी भी देता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, जो जमीन की सलैक्शन हुई है, (व्यवधान) जो भारत सरकार की नोटिफिकेशन हुई है, उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी हमने कहां से दे देनी? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कंवरः जो मंत्री हैं, जिन्होंने उसका शिलान्यास किया था । मैं कहना चाहता हूं कि 3 हजार से ज्यादा पौधे हार्टिकल्चर डिपार्टमैंट ने बड़ी मेहनत से वहां पर तैयार किए थे । तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि उनको काटा जा रहा है ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री :माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से पढ़ देता हूं । उस वक्त केन्द्र में कौन सी सरकार थी, आपको पता है, हमारी सरकार थी दिल्ली में । वर्ष 2011 में 20 ट्रिपल आई0टी0 खोलने की बात हुई । यहां पर भी बात हुई थी कि खोलेंगे । सलैक्शन जगह की हुई नहीं, 20 करोड़ रुपया आपने देना था, जो प्राईवेट पार्टनर ने देना था । इंडस्ट्रियल कंट्रिब्यूशन थी, वह नहीं आई । उसमें से एक पैसा नहीं आया । उसके बाद 20 करोड़ रूपये के लिए प्राईवेट पार्टनर ने तो कमिटमैंट कर दी, उसके पैसे आने शुरु हो गए, उसी के बाद हमने वहां काम शुरु करवाया है । जहां तक ये कह रहे हैं कि पेड़ कटे हैं, वहां पर पेड़ आदि के बारे में भी सारा कुछ क्लियर हो कर हमें जमीन मिली है । उसके बाद हमने उस पर काम शुरू किया है ।

अध्यक्षः नैक्स्ट क्वेशचन श्री किशोरी लाल, (व्यवधान) हो गया, अब काफी हो गया। मंत्री जी कह रहे हैं कि कटे हुए दरख्तों के बाद जमीन मिली है हमें। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वर्ष 2011 में नोटिफिकेशन हुई थी। तो वर्ष 2011 की नोटिफिकेशन की कॉपी सभा पटल पर रखी जाए। दूसरे सरकार

16/03.2015.14/50यूके/जेटी/2

की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसी जगह वहां पर वह संस्थान खोला जा रहा है ? जिसमें 3 हजार से ज्यादा पौधे काटे जा रहे हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता ममले मंत्रीः उन्होंने सलैक्ट ही वह साईट की , जो दूसरी साईट थी वह नाले में जा कर थी। यह भारत सरकार की कमेटी है और आलोक मिश्रा, उसके डायरैक्टर हैं। मैं उसकी कॉपी माननीय सदस्य आपको दे देता हूं। आलोक मिश्रा डायरैक्टर साहब जी की चिट्ठी है, उसकी कॉपी मैं इनको दे देता हूं। यह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है। हमारी नहीं है। भारत सरकार ने अपनी कमेटी भेजी, उन्होंने चैक किया है।

अध्यक्षः श्री प्रेम कुमार धूमल जी।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बार-बार पूछ रहे हैं, प्रश्न यह है कि वर्ष 2011 में जब भारत सरकार ने कहा कि 20 ट्रिपल आई0टी0 खोले जाएंगे और वह पब्लिक प्राईवेट पार्टिसिपेशन पर होंगे। क्या उस समय की सरकार ने उसके लिए स्वीकृति दी थी कि हम यह खोलना चाहते हैं ? भूमि की ऑफर की गयी लमलैहड़ी के पास। क्या वह टीम, बाद में आपके सत्ता में आने के बाद वर्ष 2013 में आयी तो उसको लमलैहड़ी और दोनों जगह दिखायी गयी और यह बताया गया कि यहां पर इतने हार्टिकल्चर विभाग के वृक्ष लगे हुए हैं ? तीसरे, केन्द्र सरकार के जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनका शिलान्यास, उद्घाटन या तो केन्द्रीय मंत्री करते हैं। क्या कारण था कि जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उस दिन ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज, नेर चौक का भी उद्घाटन हुआ। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगना था उसी दिन, जो आप कह रहे कि शिलान्यास हो गया इस कर के हो गया। जहां तक आप कह रहे हैं कि आपके टाईम में पैसे नहीं आए, आपको भी कमिटमैंट ही मिली है, इंडस्ट्रियलिस्टों से, जब क्लासिज़ स्टार्ट हुई तो पैसे तभी आएंगे, उस कारण से। तो हमें भी इंडस्ट्रियलिस्टों से कमिटमैंट थी कि वे पार्टिसिपेट करेंगे

16/03.2015.14/50यूके/जेटी/3

पब्लिक पार्टिसिपेशन में । स्टेट गवर्नमैंट का शेयर था, सैंट्रल गवर्नमैंट का शेयर था और इंडस्टियलिस्ट का शेयर था तो क्वेश्चन यह है कि सडनली यह क्यों किया गया ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1455/sls-jt-1

प्रश्न संख्या :... 1536 जारी

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धमूल ... जारी

अम्बोटा की पोली-टैक्नीक की क्लासिज पहले हमीरपुर में लगती रही, सुन्दरनगर की भी लगती रही। वह चाहे लमलैहड़ी में लगाओ चाहे सनोग में लगाओ, उसी जिले में हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से चेंज क्यों किया गया है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : जैसे मैंने पहले कहा, यह साइट गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की टीम ने रिजैक्ट की। हमने तीनों साइट्स दिखाई थीं। जो साइट आप वाली थी...(व्यवधान) ...अब यह जो चिट्ठी आई है ,मैं तो टीम में जाता नहीं। मैं कह रहा हूं कि यह चिट्ठी मैं आपको दे दूंगा। I will give you a copy of this letter.... (व्यवधान)... आपकी बात भी मान ली। मगर मैं यह कह रहा हूं कि मैं तो टीम में साथ नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की टीम गई। अब उन्होंने जो साइट देखी वह within ऊना जिला लग रही है ,यह नहीं कि उसको वहां से शिफ्ट किया गया हो। जो साइट उनको वैटर लगी और जो मुझे ब्रीफ किया गया है, वह यह था कि उधर को खड्ड है, इसलिए वहां पर नहीं लग सकती, यह उन्होंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रोफ़ेसर साहब ने बात कही, जो कंपनी आपने दी थी, उनके साथ मैंने दो बार परसनली बात की। अपने उस समय के सैक्रेटरी केo संजयमूर्ति को मैंने मुम्बई भेजा। उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मैं इस बात को यहां लाना नहीं चाहता था। जब यह बात कैबिनेट में उठी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट की कि जब तक कमिटमैंट नहीं होगी, तब तक हमें दिक्कत रहेगी। जो गवर्नमैंट की हमारी अपनी अंडरटेकिंग्ज हैं एचo पीo पॉवर कार्पोरेशन और एचo पीo पॉवर ट्रांसमीशन कार्पोरेशन ,उन्होंने भी पैसे दिए, अपनी सीo एसo आरo और बाकी चीजों में से उन्होंने भी कंट्रिब्यूट किया है। इसलिए यह प्रोजैक्ट लग रहा है। अब जो यह प्रोजैक्ट

लग रहा है ,वह अच्छी तरह से लगे, इसके लिए आप जो सुझाव देंगे, उनका हम स्वागत करेंगे।... (व्यवधान)...

16.03.2015/1455/sls-jt-2

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं जगलरी ऑफ वड्र्ज में नहीं जाना चाहता। आपने ठीक कहा कि चाहे इधर लगे या उधर लगे, ऊना जिला एक ही है। सवाल यह है कि आपने स्वयं माना कि हमारे समय में कंपनियों ने पैसा नहीं दिया और गवर्नमैंट सैक्टर की जो दोनों कंपनियां थी वहां से पैसा आया। गवर्नमैंट ने कहा कि उन्होंने दे दिया। जब आपके उद्योग मंत्री या सरकार का इंट्रस्ट हो कि इस स्पॉट के लिए आए, उस स्पॉट के लिए नहीं आना चाहिए तो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो पैसा इनवैस्ट कर देगा और यह कहे कि इधर नहीं दूंगा उधर दूंगा। मेरे कहने का भाव सिर्फ़ यह था कि जैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, हम यह चाहते हैं कि 2011 में जो ॥I की नोटिफिकेशन हुई ,उसकी कॉपी रखें। इंस्पैक्शन जब हुई तो अगर सनोग उन्होंने अप्रूव किया तो क्या लमलैहड़ी उन्होंने विजिट किया? लमलैहड़ी की भूमि ऐसी थी जो खाली पड़ी थी ,बंजर थी और जहां गवर्नमैंट का कोई नुकसान नहीं होना था और यह इंस्ट्रीच्यूट भी बन जाता। जिसका अरगुमैंट आप दे रहे हैं। ॥M आपने सिरमौर रखा, हमने स्वागत किया। इसी तरह ॥॥I ऊना में देने की बात थी और ऐसी जगह पर जहां कोई दरख्त काटा नहीं जाना था। आपने हार्टिकल्चर का बढ़िया डवलपड एरिया उसके लिए दे दिया। तीसरी बात, जो शिलान्यास हुआ, उसकी परमीशन कहां मिली? 5 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा ,इसलिए बिना परमीशन के हुआ है जो इलीगल है और वैसे ही गलत है। कल को कोई इस बात को उठाएगा कि आपका शिलान्यास इस तरह से हो गया ,आपके पास इसका पत्र कहां है? मेरे कहने का भाव यह है कि आप इसको ठंडे दिमाग से सोचकर सही उत्तर दीजिए ताकि जो संदेह पैदा हो रहे हैं वह खत्म हों।

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।...(व्यवधान) ...मंत्री जी आपको ऑफिशियली लिखित जवाब दे देंगे।

Prof. Prem Kumar Dhumal : On a Point of Order, Sir.

अध्यक्ष महोदय, जब भी हम आम दिन 11.00 बजे कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं , आप उस पीठ से आदेश देते हैं कि प्रश्न काल चलना चाहिए, प्रश्न काल का बड़ा

16.03.2015/1455/sls-jt-3

महत्व है। हमें यह भी सलाह दी जाती है कि करोड़ों रुपये खर्च करके प्रश्नों के उत्तर तैयार होते हैं। अब उत्तर क्यों नहीं सुनना चाहते? लगता है कि आज आप प्रश्न काल को खत्म करने के मूड़ में हैं।... (व्यवधान)...

जारी .. गर्ग जी

16/03/2015/1500/RG/AG/1

--------(**व्यवधान**)------

प्रो. प्रेम कुमार धूमल-----**क्रमागत**

हमें यह भी सलाह दी जाती है कि करोड़ों रुपये खर्च करके प्रश्नों के उत्तर तैयार होते हैं ,आप क्यों नहीं सुनना चाहते? लेकिन आज ऐसा लगता है कि आप प्रश्नकाल को खत्म करने के मूड में हैं। अगर यही ऐटीटियुड रहेगा।

अध्यक्ष : धूमल साहब, जब प्रश्नकाल खत्म होगा, तभी खत्म करेंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : कैसे खत्म होगा? देखिए, अभी-भी प्रश्नकाल खत्म नहीं हुआ, अभी-भी खत्म नहीं हुआ है। यदि आप इस तरह की रूलिंग देंगे, तो उस रूलिंग का सम्मान नहीं होगा।

Speaker: This is very unfortunate. ऐसा है कि प्रश्नकाल में---(व्यवधान)--यदि प्रश्न कॉन्टीन्यु भी हो रहा है उसमें उत्तर तो दे सकते हैं, लेकिन यह है कि we cannot indefinitely linger on the Question Hour. आप प्रश्नकाल को एक घण्टा और ज्यादा थोड़े ही कर सकते हैं। प्रश्नकाल का समय है उसके बाद यदि कोई सूचना लेनी है, तो आप उसके लिए अलग से ले सकते हैं।-------(व्यवधान)-----

श्री रविन्द्र सिंह : यदि कोई प्रश्न होता है, तो उसका उत्तर भी तो मंत्री जी को देना होता है। यदि आपकी मन्शा यही है कि सदन जल्दी समाप्त हो जाए, तो हम चले जाते हैं ,आप सदन जल्दी खत्म कर दें।

अध्यक्ष : क्या मन्शा हुई? क्या आप मंत्री जी का जवाब सुनेंगे, फिर प्रश्नकाल समाप्त कर देंगे।-------(व्यवधान)---

श्री रिखी राम कौंडल :इस माननीय सदन में हर माननीय सदस्य का अधिकार है प्रश्न पूछने का और यदि उसका उत्तर मंत्री जी सही न दें ,तो पीठासीन अधिकारी आप हैं, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि इस सरकार को आप डायरैक्शन दीजिए कि सही उत्तर दे।' सूचना एकत्रित की जा रही है ,'कभी जो सदस्य प्रश्न पूछता है उसका उल्टा जवाब दिया जाता है तो we seek your protection कि इस सरकार को आदेश दिया जाए कि सदन में प्रश्न का सही उत्तर दिया जाए ताकि माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन न हो।

अध्यक्ष : एक बार पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि I can ask the Hon'ble Minister to reply but I can't force him to reply what he is not going to reply. यदि कोई उत्तर नहीं देना चाहता है, तो मैं इनसे कैसे ऐक्ट्रैक्ट कर सकता

16/03/2015/1500/RG/AG/2

हूं।-----(व्यवधान)-----Mr. Kaundal, this question has consumed fifteen minutes. इस प्रश्न में 15 मिनट हो गए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब तो आने दें, यदि हम प्रश्न पूछें, तो जवाब तो आ जाए।

अध्यक्ष : तो क्या डण्डा मारा जाए।-------(व्यवधान)------ ठीक है, मैं इनके दिमाग से जवाब कैसे निकलवाऊं? क्या इलाज किया जाए?-------(व्यवधान)-माननीय मंत्री जी यदि आप प्रश्न का और जवाब दे सकते हैं, तो दे दीजिए। Okay, I allow him to reply.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, the Committee recommended the site at Sloh in District Una for establishment of IIIT on account of the following reasons: अब मैं बोलना नहीं

चाह रहा था, अब आप पूरा डिटेल में रिप्लाई ले लो। The land is already in possession of Government. The site is located in plain terrain. The approach road is well established with 15 meter wider. The site is in proximity with railway station such as Una from H.P. side and Hoshiarpur from Punjab side. माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं जवाब दे रहा हूं, तो ये सुन नहीं रहे हैं। This is the Government paper. There are no clearances related issue with the Forest Department. There is ample availability of water and reliable power supply. अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर इस साईट को चुन लिया और मैं यह पत्र सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। तो उसके बावजूद क्या चाहते हैं ,जो आपने कहा, भारत सरकार की वर्ष 2011 की नोटिफिकेशन रिकॉर्ड में से लेकर मैं आपको अलग से दे दूंगा। जहां तक शिलान्यास का सवाल है।

अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट आप बैठिए।---------(व्यवधान)-----मिस्टर सत्ती जी, एक मिनट आप बैठिए। मैं आपको यह क्लीयर कर देता हूं कि प्रश्नकाल अपने समय का होता है जहां निर्धारित होता है ,यह कोई बात नहीं कि कोई मंत्री उत्तर दे रहे हैं, तो उसके लिए 10-15 सैकण्ड और भी लग जाएं ,लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करुंगा कि यदि आपके किसी प्रश्न का कोई उत्तर ठीक नहीं आता है, तो there are other rules under which you can ask for the discussion. लेकिन प्रश्नकाल

का समय बढ़ाने का कोई ओचित्य नहीं होता कि आप उसको डेढ़ या दो घण्टे कर दो। This is not proper. मैं यह कह रहा हूं कि यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर में कोई संदेह कि उत्तर ठीक नहीं आ रहा है ,तो आप किसी और नियम के अंदर उस पर चर्चा मांग लीजिए।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।
अध्यक्षः आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

एम.एस. द्वारा शुरू प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी

व्यवस्था का प्रश्न

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री सिस्टम में एक इडियम है कि मैं स्पीकर का नाक और आंख अपनी तरफ चाहूंगा। एक बात जो आई, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक सिस्टम प्रारंभ हो गया है कि उद्घाटन/शिलान्यास हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी या किसी और मंत्री का नाम फाउंडेशन स्टोन पर लिखा होता है और उद्घाटन कोई और कर रहा होता है। ऐसे स्टोन्ज भी लग गए जिसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री या मंत्री का नाम आ जाएगा, कि उनके आदेश से उद्घाटन फलां कर रहा है।)व्यवधान(

श्री नीरज भारती) मुख्य संसदीय सचिवः(आपकी सरकार थी, जब ज्वाली में ऐसा हुआ कि फाउंडेशन स्टोन पर मुख्य मंत्री जी आपका नाम था और रविन्द्र जी वहां उद्घाटन करने के लिए आए थे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपने अच्छी बात की है अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो उस पत्थर को भी हटा दो। कांगड़ा सेंट्रल कोपरेटिव बैंक में भी हमारे नाम का पत्थर हटा दिया गया। देहरा में माननीय मुख्य मंत्री जी अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे, आपके ही स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह जी का वहां नाम लगा था, तब भी इस पर आपत्ति हुई थी। अगर सलोह में शिलान्यास हुआ, माननीय मुख्य मंत्री का भी नाम है, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री का भी नाम है और वे दोनों नहीं थे तो यह कैसे हो गया? उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और वह उद्घाटन कोड ऑफ कंडक्ट में हुआ।) व्यवधान(

श्री मुकेश अग्निहोत्री (संसदीय कार्यमंत्री)ः अगर ऐसा हुआ होता तो आपने उस समय चुनाव आयोग से शिकायतें की थी, तो इसकी भी शिकायत कर देनी थी। आपने चुनाव आयोग से उस दिन की सारी शिकायतें की। उसकी प्रति को निकाल देते हैं अगर आपने इसकी शिकायत की होगी? अगर यह उद्घाटन कोड ऑफ

16/3/2015/1505/MS/AG/2

कंडक्ट में हुआ होता तो आपने इसकी शिकायत जरूर की होती।) व्यवधान(आप अपने साथ के साथी से पूछो कि सलोह का सेंटर स्कूल गलोह कैसे गया था? सलोह का सेंट्रल स्कूल जो सारा मंजूर हो गया था, उसमें 'G' बदला और गलोह हो गया।

अध्यक्षः इस समस्या को आप लोग विधान सभा से बाहर निपटा लें। अभी सदन के काम को कन्टीन्यु करने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र कंवरः जो बंगाणा के लिए सेंट्रल स्कूल मिला था वह सलोह के लिए कैसे किया?) व्यवधान)

मुकेश अग्निहोत्री (संसदीय कार्यमंत्री) :इन्होंने तो एप्लाई भी नहीं किया था। सारे दस्तावेज सलोह के लिए बने थे।)व्यवधान)

(Question Hour concluded.)

16/3/2015/1505/MS/AG/3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है :-

1. सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2015	शासकीय/ विधायी कार्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा ।
2. मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2015	शासकीय/विधायी कार्य, राज्यपाल

	महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा।
3. बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-2016-प्रस्तुतीकरण,
4. वीरवार, दिनांक 19 मार्च, 2015	शासकीय/विधायी कार्य, गैर-सरकारी सदस्य कार्य
5. शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015	शासकीय/विधायी कार्य।

कागजात श्री जे0के0 द्वारा----------

16.3.2015/1510/जेके/एजी1/

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगेः-
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःका0(नि-4)-ए(3) 2012/1-दिनांक 31.0 1.2015द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.02.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (टवेन्टि नाईन्थ अॅमेंडमेंट) रेगुलेशनज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(3) 25-2014/2-दिनांक 10.02.2015द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2015को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे:-

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

16.3.2015/1510/जेके/एजी/2

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014 15), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

(i) समिति का 86वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का87 वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

16.3.2015/1510/जेके/एजी/3

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्षः मैं इस माननीय सदन से आग्रह करूंगा कि महामहिम् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी एवं चर्चा के उपरान्त आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यहां पर बोलने वाले विपक्ष के पांच सदस्य हैं और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इसका ज़वाब देंगे और उसके बाद हम इस सभा को स्थगित कर देंगे।
श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय ,माननीय मुख्य मंत्री का उत्तर भी आज ही होगा लेकिन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कार्यसूची पढ़ी उसमें तो यह कल के लिए बताया गया है। यह स्पष्ट करो कि पारण कल होगा या आज। मुख्य मंत्री जी कल के लिए कह रहे हैं और आप आज के लिए कह रहे हैं।

Speaker: You should understand. जब मैंने रूलिंग दे दी है तो I have preponed it. That's all.

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह देते कि पारण आज होगा। जब हफ्ते की कार्यसूची सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी एनाऊंस करते हैं तो उसके मुताबिक सदन की कार्यवाही पीठासीन अध्यक्ष को चलानी पड़ती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी , प्रीपोन कर दिया है।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, जो सदन का नेता एक हफ्ते की कार्यवाही की घोषणा करता है उसमें अध्यक्ष महोदय को उसके मुताबिक ऐक्ट करना पड़ता है या मुख्य मंत्री जी इस बात को अमैंड करें।

अध्यक्षः मैंने उसको रिलेक्स करके प्रीपोन कर दिया है। It is within my powers.

16.3.2015/1510/जेके/एजी/4

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह तो वक्ताओं के ऊपर निर्भर करता है कि जितने वक्ताओं ने यहां पर चर्चा में भाग लेने के लिए नाम दिया है वह आज ही समाप्त हो सकती है। अगर उसके अलावा और बोलना चाहे तो चर्चा आगे बढ़ सकती है।
श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने हमें गैलरी में बुलाया और इन्होंने हमसे निवेदन किया कि अपने वक्ताओं को आप कम करिये क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही उत्तर देंगे। हमने उस हिसाब से अपने पांच ही वक्ता बोलने के लिए रखे हैं। अब कार्यसूची माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल के लिए पढ़ी है। इसको ठीक करें कि आज ही उत्तर होगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं कि इसको प्रीपोन करके करैक्ट कर रहा हूं।
संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पीच में जो कल की तारीख आई है माननीय मुख्य मंत्री जी उसको अभी रैक्टिफाई करेंगे कि आज ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का ज़वाब होगा।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी इस डेट को ठीक कर लें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

सोमवार 16 मार्च, 2015	(1) शासकीय/विधायी कार्य। (2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवादप्रस्ताव-चर्चा एवं पारण।
मंगलवार 17 मार्च, 2015	(1)शासकीय/विधायी कार्य।

16.3.2015/1510/जेके/एजी/5

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने 11 मार्च, 2015 को जो अभिभाषण इस माननीय सदन में पढ़ करके और पढ़ा हुआ समझा जाए और इस पूरे अभिभाषण में सरकार की जो कारगुज़ारी के बारे कहा है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

16.03.2015/1515/SS-JT/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

इस पूरे अभिभाषण में सरकार की जो कारगुजारी है, चाहिए तो यह था कि एक वर्ष की कारगुजारी की इसमें व्याख्या करते लेकिन इसमें दो वर्षों का ज़िक्र किया गया है। बहुत ऐसी मदें हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई हैं। चाहिए तो यह था कि प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है। उसका ज़िक्र होता। चाहिए तो यह था कि इस अभिभाषण के अंदर इस वित्तीय वर्ष में जो भारी बारिश हुई है, भारी बर्फबारी हो रही है उससे जो पूरे प्रदेश के अंदर किसानों, बागवानों और सभी समुदायों का नुकसान हो रहा है उसका भी ज़िक्र इस अभिभाषण के बीच में आता।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

लेकिन इस अभिभाषण में न तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई है। न तो भारी बारिश और बर्फबारी का जिक्र किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले वर्ष 8 अगस्त से 16-17 अगस्त तक प्रदेश के अंदर भारी बारिश हुई है। इस कलैण्डर ईयर में 13-14 जनवरी से आज तक लगातार जो भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है उसके कारण प्रदेश के जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है। किसानों के मकान बह गए हैं। गौशालाएं बह गई हैं। कई जानें बह गई हैं। माल मवेशी के रूप में जो पशुधन हमारे इस प्रदेश के किसानों का सबसे बड़ा धन है बह गया है। महिला वर्ग व्यवसाय के रूप में उसके माध्यम से अपनी आजीविका कमाती है उसका नुकसान हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान 13, 14 और 15तारीख को जो भारी बारिश और बादल फटने की घटना हुई की ओर दिलाना चाहता हूं। विशेषकर उस घटना के बीच में मेरा विधान सभा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष जी, उस भारी वर्षा के कारण मेरा लगभग पूरा विधान सभा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उसमें भी जो त्रासदी भरा क्षेत्र है उसमें लगभग 6 पंचायतें आती हैं। उन 6 पंचायतें में 120 के लगभग घर बह गए। लगभग 300 से ज्यादा माल मवेशी बह गये, दब गये, मर गये।

उसमें किसानों की जमीनें चली गईं। सड़कें टूट गईं। सिंचाई की योजनाएं टूट गईं। पीने के पानी की पेयजल परियोजनाएं टूट गईं। हमारी खेतीबाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि 13, 14 और 15 अगस्त को जो बारिश हुई, एक महीने तक कोई भी सरकार का मंत्री उस त्रासदी का संज्ञान लेने के लिए हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंचा। मैं विपक्ष के नेता आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे ही इनको पता चला, 15 तारीख

16.03.2015/1515/SS-JT/2

को त्रासदी हुई, लगभग 10 किलोमीटर सफ़र पैदल चलने के उपरांत वहां पहुंचे। वहां ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि वहां न बिजली थी और न पानी था और न ही आने-जाने की व्यवस्था थी। धूमल साहब वहां पर पैदल पहुंचे। उसके उपरांत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उस सारी त्रासदी का संज्ञान लेने के लिए वहां पर पहुंचे। माननीय मुख्य मंत्री जी एक महीने के उपरांत 13 सितम्बर को मेरे उस क्षेत्र में पहुंचे और जब 13 सितम्बर को मुख्य मंत्री जी पहुंचे तो उनके साथ दूसरे मंत्री भी आए।

जारी श्रीमती के0एस0

1/16.03.2015520/केएस/जेटी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

माननीय मुख्य मंत्री जी एक महीने के उपरांत 13 सितम्बर को मेरे उस क्षेत्र में पहुंचे और 13 सितम्बर को जब मुख्य मंत्री जी पहुंचे तो उनके साथ उनके मंत्री भी आए, मण्डी जिला से तीन-तीन मंत्री होने के बावजूद उससे पहले कोई भी मंत्री वहां पर नहीं आए।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रश्न केवल धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र का ही नहीं है, प्रश्न पूरे हिमाचल प्रदेश का है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और बर्फबारी हुई है, लगातार हो रही है और लगातार नुकसान हो रहे हैं। आज हम सड़कों की हालत देखते हैं, अगस्त महीने से ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि बरसात शुरू होने से, जुलाई से लेकर आज तक ऐसी अनेकों सड़कें इस प्रदेश के अंदर है जिन पर पहले बसें चलती थी, वाहन चलते थे लेकिन आज उनमें से बहुत सी सड़कें बन्द पड़ी है। आज इस प्रदेश के अंदर

सड़कों की ऐसी हालत हो चुकी है कि सड़कों पर गड्ढे नहीं गड्ढों वाली सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर हो चुकी है। उन गड्ढों में जो पक्की सड़कें हैं, उनमें या तो गटका डाल देते लेकिन गटके की जगह मिट्टी डाली जा रही है। बारीश हो रही है तो वह मिट्टी बाहर निकल रही है। जब धूप लगती है तो धूल उड़ती है, पर्यावरण को नुकसान होता है । मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा आज प्रदेश के अंदर है। आज प्रदेश का नागरिक इस बात को महसूस कर रहा है कि सड़कों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चाहे राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड़ हों, चाहे रूरल रोड़ हों, सारी की सारी सड़कों की

1/16.03.2015520/केएस/जेटी/2

हालत बहुत खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि लोक निर्माण विभाग गहरी निद्रा में सोया हुआ है। उन सड़कों को दुरूस्त करने के लिए या तो उनके पास पैसा नहीं है अगर है तो उसको गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, धर्मपुर में जो सड़कों का और पेयजल परियोजनाओं का तथा दूसरा नुकसान हुआ है उसके लिए भले ही आपने पैसा दिया होगा लेकिन बड़े दुख से कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो सड़कें खुलनी चाहिए थी, वे आज तक भी नहीं खुल पा रही है। पीछे मण्डी में ग्रीवेंसिज़ कमेटी की मीटिंग हुई थी मैंने उसमें भी कहा था कि सड़के नहीं खुल रही है और अधिकारी कह रहे हैं कि एक-दो सड़कें ही बंद है लेकिन मैंने उनको 15-14सड़कें जो मेरी जानकारी में भी है ,उनके बारे में बताया।

उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हमने 26 जे.सी.बी. धर्मपुर में लगा दी। लेकिन मुख्य मंत्री जी, धर्मपुर में उन सड़कों को खोलने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ है तो जे.सी.बी. स्कैंडल है। वहां पर ऐसी जे.सी.बी. लगा दी, वह दूसरी जगह काम कर रही है लेकिन उनके घण्टे धर्मपुर में सड़कों को खोलने के नाम पर उनको वर्कऑर्डर दिए जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो स्कैंडल हो रहे हैं, इनकी जांच करवाई जाए। कांग्रेस पार्टी के नाते-रिश्तेदारों के घरों के आगे जो नुकसान हुआ है, उनके घरों के पास डंगे लग रहे हैं। जो हमारा राहत मैनुअल है, उसके मुताबिक जिसका ज्यादा नुकसान होता है उसको ज्यादा मुआवज़ा राशि मिलनी चाहिए और जिसका कम नुकसान होता है,

1/16.03.2015520/केएस/जेटी/3

उसको कम मिलनी चाहिए थी लेकिन मुख्य मंत्री जी, जिनका कम नुकसान हुआ है उनको ज्यादा धनराशि मिली और ज्यादा नुक्सान वाले को कम धनराशि मिली। यह चिन्ता का और चर्चा का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो राहत मैनुअल के अंतर्गत आपने मुआवजा राशि का पैसा दिया है, उसका भी वहां पर दुरुपयोग हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैंने प्लानिंग की बैठक में भी कहा था कि एम.एल.ए. फंड से जो हमने पैसा दिया हमने कहा कि स्वॉयल कंजर्वेशन वालों को पैसा देते हैं और स्वॉयल कंजर्वेशन वालों ने कहा कि हम इस एम.एल.ए. फंड के पैसे का काम नहीं कर पाएंगें। आपने बीच में इंटरवीन किया, आपने कृषि विभाग को आदेश किए उसके बाद उन्होंने कहा कि हां हम काम करेंगें लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि 27 जनवरी का आदेश डायरैक्टर, एग्रीकल्चर ने किया हुआ है स्वॉयल कंजर्वेशन ऑफिस, सरकाघाट को लेकिन आज तक भी वहां पर जो एम.एल.ए. फंड का पैसा दिया गया है, उस पैसे का वहां पर काम नहीं किया जा रहा है! इससे लगता है कि सरकार के प्रति सरकारी अधिकारी कितने गम्भीर हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि जितनी भी त्रास्दी हुई है, धर्मपुर में, नाहन में, सिरमौर में या दूसरी जगह पर हुई है उसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि-

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

16.3.2015/1525/ag/av/1
श्री महेन्द्र सिंह--------जारी

दूसरी जगह में हुई है। उसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि भारत सरकार को हमारे यहां से उसकी भरपाई की जो रिपोर्ट जानी चाहिए थी; हम बार-बार चिल्लाते रहे। वहां जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई। बाढ़ आने के तीसरे दिन हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी वहां पहुंचे। चौथे दिन हमारे प्रधान मंत्री जी वहां पहुंचे। जम्मू-कश्मीर जैसी स्टेट को एक हजार करोड़ रुपये मिले। हमें दुख से कहना पड़ रहा है। हमने बार-बार निवेदन किया। एस.डी.एम., सरकाघाट से निवेदन किया। जिलाधीश, मण्डी से निवेदन किया। सरकार के अधिकारियों से निवेदन किया कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और यह पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है। आप इस बारे में ऐस्टिमेट बनाइए। ऐस्टिमेट बनाकर भारत सरकार को प्रेषित कीजिए ताकि भारत सरकार से हमें इसकी भरपाई हेतु पैसे मिले। हमारे यहां पिछले वर्ष भी त्रासदी हुई थी और मेरे वहां 5-6 मकान दब

गए थे। मगर उसके लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई फुटी कौड़ी नहीं आई है। इस बार तो 120 से भी अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तो अगली बरसात भी शुरु होने वाली है। अगर अगली बरसात भी इसी तरह से हुई तो मुझे लगता है कि उसमें पूरे-का-पूरा क्षेत्र बह जायेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके दस्तावेजों की कॉपी यहां सदन के पटल पर रखी जाये ताकि हमें भी पता चल सके कि वह कब भेजी गई और किस-किस क्षेत्र के लिए आपने कितनी-कितनी राशि की रिपोर्ट बनाकर भेजी है?

उपाध्यक्ष जी, जहां तक आई.पी.एच. विभाग का प्रश्न है तो मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने इस बार एक नया फैसला ले लिया है। आपने इस बार सी.वी.सी. की गाइड लाइन्ज को चेंज कर दिया है। आपने इस प्रदेश के अंदर पहले से चली आर रही पारदर्शी टैंडर प्रक्रिया को चेंज कर दिया। आपने उसमें कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं; उन बड़ी-बड़ी योजनाओं में उठाऊ पेयजल योजना हमीरपुर, उठाऊ पेयजल योजना बड़सर तथा तीसरी उठाऊ पेयजल योजना आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र

16.3.2015/1525/ag/av/2

की एक लगभग 68 करोड़ रुपये, एक 20-21 करोड़ रुपये की और एक 80-85 करोड़ रुपये की है। हिमाचल प्रदेश का ए-क्लास कॉंट्रेक्टर किसी भी सीमा तक काम ले सकता है लेकिन एक पत्र आया। उस पत्र के माध्यम से आपने कहा कि सी.वी.सी. की गाइड लाइन्ज को चेंज कर दिया गया है। इसमें ज्वाईंट वैंचर को खत्म कर दिया गया है। आज तक जितने भी टैंडर होते रहें वे सारे-के-सारे ज्वाईंट वैंचर में होते रहे हैं। सी.वी.सी. गाइड लाइन्ज में कहां लिखा है कि ज्वाईंट वैंचर होगा या नहीं होगा; ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। मेरे पास सी.वी.सी. गाइड लाइन्ज की कॉपी है। हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र दो फर्में काम ले रही हैं। वे दोनों-की-दोनों फर्में बाहर की है। उसमें भी उनको मिलीभगती से रेट दिए जा रहे हैं। उनके रेट इस प्रकार से हैं कि जो 97-98 करोड़ रुपये का कोई टैंडर होता है तो वे उस टैंडर को 128 करोड़ रुपये में भरते हैं। जब 128 करोड़ रुपये में भरते हैं और हिमाचल प्रदेश की कॉंट्रैक्टर यूनियन द्वारा विरोध करने पर उस ठेकेदार से दोबारा नेगोसियेशन की जाती है और उसको 106 करोड़ रुपये पर लाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को हम अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो

कम-से-कम उसको हिमाचल प्रदेश में आई.पी.एच. विभाग के टैंडर लेने से तो वंचित न करें। आई.पी.एच. विभाग की दूसरी दूदर्शा क्या हो रही है? हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया है कि वहां पाइपें रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। पूछा जाता है कि ये पाइपें कहां जा रही हैं तो बताया जाता है कि ये 20 पाइपें फलानें के यहां जा रही हैं। उनको चिट मिला होता है और उनका उत्तर होता है कि फलानें के घर के पास नलका लगना है। अरे, सरकार तो सबकी होती है। सरकार सूर्य की किरणों के समान होती है। सूर्य की किरणें इस पृथ्वी / इस ब्रम्हाण्ड के ऊपर पड़ती है तो वह सबके ऊपर पड़ती है। इसी तरह सरकार का दायित्व बनता है कि वह चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी से

16.3.2015/1525/ag/av/3

सम्बद्ध रखता हो; सरकार को उन सबको एक बराबर नजर से देखना चाहिए। सबको एक बराबर लाभ मिलना चाहिए। आज ऐसी स्थिति है, अगर आई.पी.एच. में इस स्थिति को रोकेंगे नहीं तो ----------

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

16.3.2015/1530/negi/jt/1

श्री महेन्द्र सिंह . .जारी...

और एक ऐसा वर्क-आर्डर सिस्टम शुरू किया गया है कि चिट लिए जाते हैं , स्पिलिट ऑफ सैंक्शन की जाती है। बड़े-बड़े कामों को तोड़ मरोड़ करके एक लाख से नीचे लाया जाता है और फिर उनके वर्क आर्डर दिए जाते हैं। किसको वर्क आर्डर दिए जाते हैं और कितनी खुदाई उन पाइपों की होती है, मुझे पता है। हमारे पास पूरे दस्तावेज़ हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात जरूर लाना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, लगता है कि जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है इसका माली वारिस कोई नहीं है, अभी आपने देख लिया हेागा जब स्कूलों की वर्दियां खरीदी गई । अगर स्कूल वर्दियों के खरीद में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है तो आई.पी.एच. की पाइपें जो करोड़ों में ही नहीं बल्कि अरबों रूपये में खरीदी जाती है तो उसमें क्या हुआ होगा। हम आई.पी.एच. विभाग की पाइपों की गुणवत्ता देख रहे हैं कि जब उनको बेंड करना चाहें तो पहले पाइपें यू शैप में बेंड हो जाती थी अब अगर थोड़ा सा भी बेंड करते हैं तो पाइपें क्लिक करके चिपक जाती हैं। हिमाचल प्रदेश आई.पी.एच. विभाग के अन्दर घटिया किस्म की पाइपें सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के द्वारा

खरीदी जा रही है, यह चिन्ता का विषय है। इस विषय की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी आपका विभाग बहुत बड़ा विभाग है। क्या कारण है कि 2 साल से जो हाइडल प्रोजेक्ट चलाने वाली इंट्रस्टिड पार्टिज़ थी वे हिमाचल प्रदेश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं? यह चिन्ता का विषय है । इसपर चिन्तन करो। दूसरा, मुझे आपसे यह जानना है, हमने इस मान्य सदन में भी जानना चाहा था कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जिलों के अन्दर आपने बिजली के मीटर बदलने का काम किया है । आपने सर्विस वॉयर बदलने का काम किया है । आपने दूसरा सामान परचेज किया है। आपने ट्रांसमिशन लाइन्ज़ की वायर है उसकी परचेजिंग की हैं। आपने ट्रांसमिशन लाइन्ज़ की चैनल्ज़ परचेज़ किए हुए हैं। ट्रांसमिशन लाइन्ज़ में सिविल वर्क हुआ है, आपने उसका काम

16.3.2015/1530/negi/jt/2

किया है । आज क्या वजह है कि जो मीटर आपने बदले हैं वे हजारों में नहीं बल्कि वे लाखों की संख्या में हैं। पुराना मीटर क्यों बदला गया ? क्या वह मीटर खराब था? अगर वह मीटर खराब था तो पहले के अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कारवाई की ? अगर वह मीटर ठीक था और जो दूसरा मीटर लगाया गया है उसकी जरूरी क्यों पड़ी ? दूसरा मीटर 150 की स्पीड़ में दौड़ रहा है । अगर हम अपना मोबाइल भी चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज करने पर भी मीटर ऐसा दौड़ता है जैसे 150 की स्पीड़ पर घोड़ा दौड़ता है । यह एक चिन्ता का विषय है । जो रेट्स आज से 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ता देते थे, जिनको 400-500 का बिल आता था, लेकिन आज उनको500-400 रूपये की जगह 4-5 हजार रूपये के बिल आ रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री जी इसपर ध्यान दीजिए। हमारा आरोप है कि मीटरों की जो परचेजिंग हुई हैं, सर्विस वॉयर्ज़ की जो परचेजिज़ हुई है इसपर पूरे प्रदेश का हर उपभोक्ता उंगली उठा रहा है । जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं ,ये भी ठीक नहीं है। स्टील पोल्ज़ की गुणवत्ता मापा जाता था लेकिन आज इस बर्फबारी में आप पूरे प्रदेश के अन्दर जा करके देखिए, आपके जो स्टील के पोल्ज़ थे और आर.सी.सी. के पोल्ज़ थे वह ऐसे ढह गए जैसे रेत के पहाड़ जब बारिश होती है तो ढह जाता है, उस प्रकार से ढह गए। यह चिन्ता का विषय है ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं । हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । लेकिन दुःख इस बात का है कि आज भी हमारे चौपाल के क्षेत्र में बिजली नहीं है। आज भी चच्योट के क्षेत्र में बिजली नहीं है। आज भी हमारा बन्जार का क्षेत्र बन्द पड़ा है क्योंकि वहां बिजली नहीं है । आज भी हमारा कुल्लू का बहुत सारा क्षेत्र, आज भी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं है। आज भी चम्बा के क्षेत्र बिजली से वंचित हैं। क्या वजह है? सतलुज बेसिन बिजली पैदा करता है, ब्यास बेसिन बिजली पैदा करता है, चिनाव बेसिन बिजली पैदा करता है, जो प्रदेश बिजली पैदा करता हो, उस प्रदेश के दूर दराज़ के जो किसान हैं ,बागवान हैं, वे आज बिजली से वंचित हैं।

16.3.2015/1530/negi/jt/3

वहां पर बिजली की लाईन नहीं है। पिछली बार जब 13-14 जनवरी को बर्फ पड़ी तो किन्हीं कारणों से मैं भी उस समय मनाली में था । ...(घंटी)..

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ वाइन्ड-अप करें।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, किन्नौर का क्षेत्र आज बन्द पड़ा हुआ है ।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

16/03.2015.1535/यूके/जेटी/1
श्री महेन्द्र सिंह---जारी----

किन्नौर का क्षेत्र पूरा बन्द पड़ा हुआ है ।

उपाध्यक्षः मेरे किन्नौर के पूरे क्षेत्र में 75% क्षेत्रों में बिजली पहुंच गयी है। आप चिंता न करें ।

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका क्षेत्र भी बिजली से वंचित है । इसलिए भी चिंता करने की आवश्यकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन

करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी, जब हम किसी के साथ एम0ओ0यू0 करें तो उस एम0ओ0यू0 में यह प्रावधान रखें कि एलाईन दुहांगन का प्रोजेक्ट अगर मनाली में लग रहा है तो एलाईन दुहांगन प्रोजेक्ट से अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जब बर्फवारी हो जाए तो वहां पर एलाईन दुहांगन की बजली चली हुई थी लेकिन मनाली अंधेरे में डूबा हुआ था। तो उनका पहला कर्तव्य बनता था कि एलाईन दुहांगन की बिजली पहले मनाली के क्षेत्र को दें। अगर हमारा NJPC प्रोजेक्ट है और यदि रामपुर में बिजली नहीं है और वहां की बिजली हमारे पंजाब, दिल्ली, राजस्थान को जाती है तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए एम0ओ0यू0 में ऐसी क्लासिज को इनकोरपोरेट किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों को बिजली देनी कम्पलसरी की जाए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इस कर के मैं चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्था के ऊपर भी चिंतन करें।

एक आपने प्याज का बीज लाया, पता नहीं यह हॉर्टिकल्चर वालों ने लाया या एग्रीकल्चर वालों ने लाया है, उस बीज को आपने मुफ्त में बांटा है। उस बीज की एक छोटी सी क्यारी मैने भी घर में लगा दी। मैने सोचा चलो देखते हैं इटली का बीज आया हुआ है, इटली का बीज कितना अच्छा होगा। मैं चाहूंगा इस हाऊस के बीच में (व्यवधान) इटली का है, हां, उस लिफाफे के ऊपर इटली लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं या तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर या फिर ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय से, जिन्होंने वह बीज बांटा है, जहां से वह बीज लाया गया है। वह बीज पूर्ण रूप से

16/03.2015.1535/यूके/जेटी/2

फेल हो गया है। वह बीज उगा ही नहीं। जो थोड़ा बहुत उगा वह बना ही नहीं। यह चिंता का विषय है कि जो इटली का माल इटली का प्याज यहां पर लाया गया है, वह सारे का सारा यहां पर फेल हो गया है। यह एक चिंता का विषय है।

जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आदरणीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनस्टिर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां हर रोज कत्लेआम हो रहे हैं। यहां पर रोहड़ू, जुब्बल-कोटखाई के क्षेत्र में, और पिछले दिन अखबार में आया था कि गोरखों ने इतने लोगों को कत्ल कर दिया। (घंटी)

Deputy Speaker: Now, please wind up. Next speaker Shri Maheshwar Singhji.

श्री महेन्द्र सिंहः इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हिमाचल प्रदेश की बहुत दयनीय हो चुकी है। इस पर भी विशेष चिंता करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ वाईंड अप करें। अब नैक्स्ट स्पीकर, श्री महेश्वर सिंह जी।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय मुख्य मंत्री जी ,जहां तक कौशल विकास भत्ते की बात है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी फर्जी कम्पनियां बनी हुई है, उसका जीता-जागता उदाहरण करसोग का है। करसोग के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी, यहां पर बैठे हुए हैं, करसोग के क्षेत्र में कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आपने बहुत बोल लिया। अब आपने बजट में बोल लेना। Not to be recorded. श्री महेश्वर सिंह जी आप बोलिए। It is not being recorded now. हो गया आपको 25 मिनट हो गए बोलते हुए। अभी आपको बजट

16/03.2015.1535/यूके/जेटी/3

में मौका मिलेगा बोलने का तब आप बोल सकते हैं। अभी आपके बाद 6 सदस्यों ने और बोलना है।

श्री महेन्द्र सिंहः सर, यदि हम यहां पर नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे ? हमने पहले ही अपने सदस्य कम कर दिए हुए हैं। फिर भी आपको आपत्ति है।

उपाध्यक्षः नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं। 25 मिनट का समय बहुत होता है।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। हाऊस के समय को बढ़ाया जा सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसके बहुत बुरे हाल है। इस बुरे हाल का नतीजा बहुत बुरा होगा। सामने वाले मित्रों, इस बुरे नतीजे के लिए आप तैयार रहो। अब समय बहुत नज़दीक आ रहा है। मैं फिर भी कह रहा हूं आपको कि या तो सुधर जाओ। यदि नहीं सुधरेंगे तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है, जहां भ्रष्टाचार की बात आती है। अब करप्शन और कांग्रेस एक जैसी हो गई है। इसलिए जो भ्रष्टाचार की बात है। भ्रष्टाचार में माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आरोप है, मंडी जिला में एक यूनिवर्सिटी खुली।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1540/sls-ag-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

मण्डी जिला में एक युनिवर्सिटी खुली है। इस युनिवर्सिटी को खोलने से मण्डी में बहुत प्रचार हो रहा है कि बहुत बड़ा लेन-देन हुआ है। लेन-देन किसने किया? लेन-देन कैसे हुआ है? एक युनिवर्सिटी को खोलने के लिए किसी मंत्री को आँसू बहाने पड़ें। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ़ चार्जशीट भी तैयार कर रहे हैं और उस चार्जशीट को दस्तावेजों के साथ हम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी भेजेंगे। इसलिए जहां भ्रष्टाचार की बात आती है... (व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : आप जो भ्रष्टाचार पर चार्जशीट की बात कर रहे हैं, यह काम आप जल्दी से कर दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने कहा कि जल्दी कर दो, हम जल्दी करेंगे, आप निश्चिंत रहें ,इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो कमेटी बनी है वह उन्हीं बातों को उठाएगी जिन्होंने गलत किया है। आज हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जो कांग्रेस पार्टी के छुटभइया नेता भी हैं ,वह भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए हैं। उस भ्रष्टाचार को अगर हम उजागर नहीं करेंगे ,विपक्ष अगर उजागर नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज मंदिरों में चोरी हो रही है। सीता माता का अपहरण तो हुआ था लेकिन यहां तो भगवान राम को भी साथ ले गए। यह बड़ी चिंता का विषय है कि भगवान राम भी गए। अब एक ऐसी चर्चा चली हुई है कि जो मूर्तियां मिली हैं, महेश्वर सिंह जी ,एक बात समझ में नहीं आती कि चोर पकड़ा नहीं गया। कहते हैं कि चोर नेपाल में है। किसको पता है कि नेपाल में है? किसने देखा कि नेपाल में है? चोर नेपाल में है और मूर्तियां कुल्लू में बरामद हुई। कैसे वह मूर्तियां कुल्लू में बरामद हो गई? ...(व्यवधान)... नैट से यह कैसी टैक्नोलोजी विकसित हो गई? अगर इतनी टैक्नोलोजी विकसित हो गई, तब तो आपकी सरकार का रब ही राखा है। वहां पर चर्चा है कि जो मूर्तियां मिली हैं, कहते हैं कि वह ऑरिजीनल नहीं हैं। अब हम क्या समझें कि वह

ऑरिजीनल हैं या डुप्लीकेट हैं? मैं महेश्वर सिंह जी से नहीं कह रहा हूं बल्कि सरकार से कह रहा हूं। इसी प्रकार से मंदिरों में चारियों हुई हैं। शिमला का कौन-सा ऐसा मंदिर हैं जिसमें चोरी नहीं हुई है। पुजारियों की हत्याएं करके वहां पर चोरियां की गई हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति है।

जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है ,बाली जी आप बताएं कि कौन-सा ऐसा दिन है जिस दिन 3, 4 या 5 व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के अंतर्गत जो सख्ती बरतनी चाहिए ,वह सख्ती कहां चली गई? बाली जी, आप बुरा न मानें। आपके पास जो भी विभाग होगा, आप भेड़ के ऊपर ऊन नहीं छोड़ते हैं। आप कहते हैं कि जो भी विभाग मेरे पास आएगा, मैं उसके ऊपर ऊन नहीं छोड़ूंगा। अरे, भगवान के लिए, हमने भी तो कल को ईश्वर के पास जान देनी है। कितना माल इकट्ठा कर लेंगे और उस माल को कहां डालेंगे? वह माल किसी के साथ नहीं जाएगा। वह माल यहीं रह जाएगा। जब माल यहां रह जाएगा और जो हमारे पीछे होंगे ,वह कहें कि (***) चोरी का माल है, मरने दो। ... (व्यवधान)...

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह असंसदीय शब्द आए हैं इनको एक्सपंज करें।... (व्यवधान)... It is unparliamentary word which the Hon'ble Member is using.

उपाध्यक्ष : जो असंसदीय शब्द अभी कहे गए हैं, इनको कार्यवाही से निकाला जाता है। माननीय सदस्य, आप अपनी जुबान को लगाम दें।

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई शब्द अगर असंसदीय कहा गया है तो उसे निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष : असंसदीय शब्द निकाल दिए गए हैं। अब आप कनक्लूड करिए।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

16.03.2015/1540/sls-ag-3

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भारी बर्फबारी हुई है और अभी तक भी, जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए उसे करने में सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है। आप इस ओर विशेष ध्यान दें।

उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है। अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय का समय बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

अगले वक्ता ..श्री गर्ग जी

16/03/1545/RG/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह-----क्रमागत

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय बढ़ाने के लिए धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बैठ जाइए।

उद्योग मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कौशल विकास भत्ते का रैफ्रेंस दिया और यही रैफ्रेंस माननीय श्री धूमल जी के भाषण में भी आया था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो कौशल विकास भत्ता है ,इसका पैसा बैनीफिशरी के अकॉउन्ट में डायरैक्ट जाता है इसलिए इसमें कोई गड़बड़ की संभावना नहीं है। क्योंकि पैसा सीधे बैनीफिशरी के अकॉउन्ट में जाता है। जहां इन्होंने इन्स्टीटियुशन्ज की बात कही ,हमने उपायुक्तों को डायरैक्शन्ज दी थीं कि जो भी ऐसे इन्स्टीटियुशन्ज लगें जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको हटा दिया जाए। पूरे प्रदेश में ऐसे इन्स्टीटियुशन्ज की रैकिंग हुई और उन सबको लिस्ट से हटा दिया गया है। अब जो इन्स्टीटियुशन्ज सही हैं वे नैट पर डाल दिए गए हैं और जिले में भी उपायुक्त के कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां गड़बड़झाला था ,जिन्होंने गड़बड़ की ,ठीक है, आगे के लिए तो आपने यह सब दुरूस्त कर दिया , लेकिन जिन्होंने पीछे हेराफेरी कर दी ,उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे?

उद्योग मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमने यह कह दिया है कि जिन-जिन भी इन्स्टीटियुशन्ज ने ऐसे ऐक्सप्लॉट करने की कोशिश की है ,जैसा मैंने कहा कि पैसा तो बैनीफिशरी के अकॉउन्ट में जाता है ,लेकिन अगर किसी ने गलत ऐड

देकर उनको अपने साथ जोड़ा था और वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं निकला है, हम ऐसे संस्थानों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।

उपाध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मान्यवर राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन में 11 मार्च, 2015 को अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया ,मैं उसके सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 38 वर्ष के इस राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर था कि जब राज्यपाल महोदय के अस्वस्थ्य होने के कारण यहां उस अभिभाषण को पढ़ा हुआ समझा गया।------(व्यवधान)-----अरे, मुझे जो बोलना है, बोलने दें ,

16/03/1545/RG/AG/2

आप इतना बोले क्या हम बीच में बोलते हैं? अब "गुचगुच" आपकी तरफ है या कहां है? आप रुकिए, आपको काफी समय मिल चुका है ,आप मुझे बोलने दीजिए। तो मैं कह रहा था कि यदि अस्वस्थता के कारण वे अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ पाए , तो सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में उनके स्वास्थ्य लाभ की शीघ्र कामना करता हूं।

उपाध्यक्ष : कृपया कोई भी सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। Let him speak. आप बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेंगे। If there is point of order then he can stand and ask.
श्री महेश्वर सिंह : वर्तमान सरकार ने इन दो वर्षों में कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को लाने का प्रयास भी किया है ,उनका शिलान्यास भी हो गया और उनका बजट भी उपलब्ध है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम सरकार को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक डारकर साइड भी होती है। मैं उस बात का प्रयास करुंगा कि जो इस प्रकार की चीजें हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का क्षेत्र है ,सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई है। फलस्वरूप सैंकड़ों स्कूल अपग्रेड हुए ,सैंकड़ों प्राथमिक स्कूल खोले गए और जो शिक्षकों की कमी थी उसमें भी सरकार ने भरसक प्रयास किया। लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 6,000 इस प्रकार के प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं जो दो

अध्यापकों के रहमोकरम पर चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह पिछला बैक लॉग है इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार इस प्रकार के प्रयास करेगी कि जितने ये खाली पद हैं, चाहे वे हाई स्कूल की बात है, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल की बात है ,उनको भरा जाए। मैं मानता हूं कि दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी है ,सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इन पदों को भरेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों में सुविधाओं का सवाल है ,मैंने एक प्रश्न में पूछा था कि कुल कितने स्कूल हैं और कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन हैं और कितने ऐसे हैं जो आज वन भूमि पर बने हैं। उसका उत्तर बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ बातें कही गई हैं उनका भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। क्योंकि मंदिर को

16/03/1545/RG/AG/3

लेकर इन्होंने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं ,मैं उस पर बोलना चाहूंगा। मेरे पास सारी डिटेल है कि कितने आज इस प्रकार के संस्थान हैं-------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

16/3/2015/1550/MS/AG/1
श्री महेश्वर सिंह जारी---------

उस पर बोलना चाहूंगा। मेरे पास सारी डिटेल है कि कितने आज इस प्रकार के संस्थान हैं। इस तरह के लगभग 685 स्कूल हैं जो आज भी वन भूमि पर हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि जो वर्ष 1980के एक्ट बनने से पूर्व वन भूमि में स्कूल बने हैं, उनको स्वतः ही रेगुलर कर दिया जाएगा। उसके लिए एफ0आर0ए0 के अन्तर्गत केस बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि बाकी विभागों में भी इसका अनुसरण होना चाहिए।

इसी तरह से आज एक प्रश्न सब्जी मण्डी के बारे में था। यह बात सर्वविदित है कि सब्जी मण्डियों का निर्माण या खोलना सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह के ज़माने में

हुआ था। उस वक्त भुंतर की सब्जी मण्डी स्वीकृत हुई थी लेकिन मंत्री जी के जवाब में आया कि इसकी शुरूआत वर्ष 1992 में हुई और उसके बाद वर्ष 1995 में बाढ़ आई, इसलिए वह बह गई। फिर वर्ष 1998 में शुरू हुई। यह जवाब तथ्य पर आधारित नहीं है। अगर वर्ष 1992में इसकी शुरूआत हुई तो फिर वन विभाग कहां सोया था? इतने बड़े टुकड़े पर कैसे कब्जा करने की अनुमति दी गई ? सत्यता यह है कि यह वर्ष 1977-78 की यह बात है। वर्ष 1978 में जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी , उस वक्त यह सब्जी मण्डी खुले मैदान में शुरू हो गई थी। निश्चित रूप से बाढ़ आई लेकिन वह जगह बाढ़ में नहीं गई। वहां पानी भर गया था और जैसे ही पानी उतरा फिर उसके बाद वह सब्जी मण्डी चलती रही। यह वर्ष 1998 की बात भी गलत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं कि कृपया इस बात की छानबीन करे कि अगर यह सब्जी मण्डी वर्ष 1980से पूर्व वहां पर स्थापित हो चुकी थी, भले ही खुले मैदान में स्थापित हो चुकी थी, तो भी इसी नियम के अनुसार जो केबिनेट ने निर्णय लिया है, उसको रेगुलराइज करने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

16/3/2015/1550/MS/AG/2

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षण संस्थानों का संबंध है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी कुछ बातें करने की हैं। जैसे अधिकांश विद्यालयों में शौचालय नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने सारे आंकड़े निकाले हैं कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां शौचालय नहीं है। तो इनकी संख्या 1129 बनती है और जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वे 1810 स्कूल हैं। उपाध्यक्ष जी, वर्तमान प्रधान मंत्री ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्वच्छता और सफाई के लिए दी है और करोड़ों रूपये इस पर आज खर्च हो रहे हैं। सफाई के प्रचार पर भी काफी खर्चा हो रहा है। इसलिए मैंने शिक्षा विभाग के तीसरे विंग को लिखित रूप में निवेदन किया कि सर्वप्रथम इन शौचालयों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए, उनको पानी की सुविधा देने के लिए आप रमसा के अन्तगर्त क्यों नहीं भारत सरकार से निवेदन करते? तो उन्होंने मुझे ऐसा रूखा जवाब दिया, कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान करवाने पड़ते हैं, होने का कोई सवाल नहीं है। पहले शिक्षा विभाग में दो विंग थे। एक एलिमेंट्री और दूसरा हायर शिक्षा। ये तीसरे विंग का और सूत्रपात हुआ क्योंकि केन्द्र से पैसा आया। मुझे कभी-कभी लगता है कि इस विभाग के तीसरे विंग की कोई

प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि जब ये इस प्रकार के मामलों में पैसे नहीं दिला सकते, और न ही लिख नहीं सकते हैं। हैरानी की बात है कि एक तरफ सफाई के लिए इतनी प्राथमिकता और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी का कोई प्रबंध नहीं है। मैंने इस बारे में एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर मेरे पास है। आप लोग नाराज न हों। मुझे बताया गया कि वर्ष 2011 में यह निर्णय लिया गया कि अब सफाई कर्मचारियों का डाइंग कॉडर घोषित कर दिया जाए क्योंकि सफाई कर्मचारियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जितने भी रिटायर हुए, सबके पद डाइंग कॉडर के तहत समाप्त कर दिए। तो फिर बिना सफाई कर्मचारी के शौचालय बनाने का क्या औचित्य है? इसलिए उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन रहेगा कि इस बात को केन्द्र की सरकार से उठाएं ताकि सबसे पहले स्कूल की सफाई और स्वच्छता की ओर कोई ध्यान दिया जाए। उसके बाद अन्य चीजों को करने की आवश्यकता है। अब तीसरा विंग है। आज स्कूल बिल्डिंग्ज के लिए पैसे देने वाले बहुत हैं। सांसद निधि है, विधायक निधि है और कभी मंत्रीगण जाकर घोषणा करते हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

16.3.2015/1555/जेके/जेटी/1

श्री महेश्वर सिंह जारीः---------

कभी मंत्रिगण जा करके घोषणा करते हैं कि दो कमरे का निर्माण हो जाए। एस.एम.सी है वह भी जिलाधीश से पैसा लाते हैं लेकिन टेक्निकल स्टाफ कहां पर है? वह केवल और केवल डायरैक्टर प्रोजैक्ट के पास है। सब इकट्ठा कर दिया है। जब एस.एम.सी. वाले पैसा ले जा रहे हैं वे मनमाने ढंग से काम कर देते हैं। वे बी0डी0ओ0 के वहां से जे.ई. बुला देते हैं । फिर विभाग का तीसरा विंग कहां पर है? मैंने देखा है कि अध्यापकों की मीटिंग्ज भी होती है। अच्छी बात है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वह कब ट्रेनिंग होती है, एक तो शिक्षकों का अभाव और ये स्कूल जिन दिनों फंक्शनल होते है उन्हीं दिनों इनको यहां पर ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। क्या ये लोग नहीं जा सकते फील्ड में ट्रेनिंग देने? दूसरे जब छुट्टियों में स्कूल बन्द होते हैं और अध्यापकों को छुट्टी होती है उस वक्त ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? मैंने देखा है उस मीटिंग का परिणाम कहीं पर नज़र नहीं आता है। मीटिंग ईटिंग-सीटिंग के साथ समाप्त हो जाती है और स्कूलों में शिक्षा का नुकसान होता है। इस ओर सरकार ध्यान दें। इतना मुझे कहना है।

महोदय, जहां तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग का संबंध है। ये जो एक राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कार्रवाई हो रही है तो उसमें हिमाचल में अभी तक परिवार का छांटने का जो लक्ष्य था वह बहुत अधिक था। 32.98 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है ,जबकि लक्ष्य 36 लाख का था। कौन सा कारण है इस सस्ते राशन को लेने के लिए पात्र व्यक्ति आगे नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं जिनका चयन हुआ उनको केवल चावल और गेहूं मिलता है और दालों से छुट्टी हो गई। अगर ऐसा है कि उनको दाल नहीं मिलती, उनको नमक नहीं मिलता तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका संज्ञान मंत्री जी लें और यह व्यवस्था करें कि उनको भी सस्ती तीन दालें और नमक मिले ताकि वे

16.3.2015/1555/जेके/जेटी/2

इस कार्यक्रम का अनुसरण करें अन्यथा 15 किलो चावल के लिए और 20 किलो गेहूं के लिए इस कार्यक्रम के लिए लोग आगे नहीं आएंगे ,ऐसा मेरा मानना है।

जहां तक गैस वितरण का संबंध है। आज भी ऐसी स्थिति है कि न तो हम गैस सिलेंडर को गाड़ी में ले जा सकते हैं क्योंकि वह गाड़ी में अलाऊड नहीं है। लोग गाड़ी करके ले जाए या जीप में ले जाए इसका खर्चा कौन देगा? पिछली बार भी मैंने इस बात को यहां पर उठाया था। मंत्री जी ने कहा कि इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो दुर्गम क्षेत्र है या निगम अपने आप दुकानें निकालेगा अन्यथा किसी प्राईवेट क्षेत्र में खोलेंगे। एक भी दुकान मेरे क्षेत्र में नहीं खुली है। मेरे क्षेत्र में मणिकर्ण है वहां पर कोई दुकान नहीं खुली है। उनको भुन्तर से गैस ले जानी पड़ती है। बंजार क्षेत्र में गड़छा है उसमें भी कोई दुकान नहीं है, लव वैली में नहीं है, बुशेहर में नहीं है। ऐसे अनेकों स्थान है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर वहां पर गैस एजैंसी दी जाए। ऐसा मेरा मानना है। जो भी सिविल सप्लाई सामान देती है और जो डिपू होल्डर्ज हैं उनको गांव का केरैज मिलता है और गैस सिलेंडर जिसको ले जाना है वह अपने खर्चे पर ले जाता है। उसके लिए भी यह सुविधा होनी चाहिए कि वह सिलेंडर ग्रामीण क्षेत्र तक कैसे पहुंचे? कैसे आदमी पीठ पर ले जा रहा है, कितनी मंहगी उसको गैस पड़ी रही है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

यहां पर मैं पंचायती राज की बात करूंगा। मैंने मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहा था कि क्या नई पंचायतें क्रिएट होंगी? उसके लिए प्रावधान है। वर्ष 1994 का एक्ट है जो कहता है कि हर 5 साल के बाद उन्हीं मापदण्डों के अनुसार नई

पंचायतों का सृजन होगा, बाईफरकेशन होगी। ब्लॉक समिति, जिला परिषद और यहां तक कि जिला परिषद के जो वॉर्ड बनते हैं, मंत्री जी पहले इस पक्ष में नहीं थे। हमने प्लानिंग मीटिंग में यह बाता उठाई । उसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा भी कि इसका प्रबन्ध होना चाहिए। वे इस चीज में सफल हो गए। मंत्रि-मण्डल की बैठक में जा करके प्रतिबन्ध लगा दिया कि नई क्रिएशन नहीं होनी चाहिए। अर्थात्

16.3.2015/1555/जेके/जेटी/3

आप थोड़े से पैसों के लिए लोगों को उसके प्रजातांत्रिक अधिकार से वंचित रख रहे हैं ताकि 5 साल तक जैसी व्यवस्था है उसी पर चलो। मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस बात पर पुनर्विचार करें और जो लोगों का अधिकार है उसको लोगों को दें ताकि नई पंचायतें मापदण्डों के अनुसार बना सकें और जो उसमें प्रावधान है उस प्रावधान अनुसार कार्रवाई हो। यह परम आवश्यक है। महोदय ग्राम सभा का होना---

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1600/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

महोदय, ग्राम सभा का होना, मुझे याद है विपक्ष के नेता ,धूमल जी ने भी इस बात का समर्थन किया था कि समय आ गया है कि कलैण्डर बनाया जाए ताकि एक दिन में एक ब्लॉक में एक या नज़दीकी दो पंचायतों में यह ग्राम सभा हो। पूरे महीने का कलैण्डर बनाया जाए ताकि ये ग्राम सभाएं और आकर्षक हो सकें। वहां पर अधिकारी जा सकें और जो विधायक जाना चाहता है वह भी जायेगा अगर ग्राम सभाएं अलग डेटों में होंगी। मंत्री जी ने इस संदर्भ में यहां पर एक विधेयक लाने का आश्वासन दिया था। मुझे विश्वास है कि वे इसी सत्र में ऐसा विधेयक लायेंगे।

महोदय, जहां तक परिवहन की बात है आज ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है कि लोगों को समझ नहीं आता कि किस गाड़ी में चढ़ें और किसमें न चढ़ें। मुख्य मंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की कि स्कूल के बच्चों के लिए भी निःशुल्क बस यात्रा उपलब्ध होगी। इसका यत्र, तत्र, सर्वत्र जगह लोगों ने स्वागत किया। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में एक भी अतिरिक्त बस उन बच्चों के लिए लगाने में असफल रहे। जब भी हम बस की बात करते हैं तो मंत्री जी एक जवाब देते हैं कि मैंने अगले महीने शुरू कर देनी। राम जाने कि वह अगला

महीना कब आना। पहले कहा कि स्टाफ की कमी है। हम स्टाफ का इंतजार करते रहे। फिर एक साक्षात्कार हुआ। उसमें एक ही क्षेत्र के 60-60 बच्चे आगे आ गए क्योंकि ज्यादा बुद्धिजीवी वहीं रहते हैं। फिर एक विवाद प्रश्न पत्र पर भी हुआ। वह हाई कोर्ट में स्टे हो गया। फिर एक दूसरी व्यवस्था कर दी। उसमें आश्वासन तो दिया है कि स्थानीय लोग लगेंगे, अब देखिये कि होता क्या है। इस प्रकार की व्यवस्था है। जो लॉ फ्लोर बसिज़ आईं, वे बसिज़ ऐसी हैं कि शिमला में ही मुड़ नहीं पा रहीं और घंटों यहां ट्रैफिक जाम रहता है। पता नहीं, वे कहां सफल हुईं? एक विचित्र बात हो गई कि एक प्रदेश में उसी रूट पर दो किस्म के किराये हो गए। वह बस सस्ती कर दी और जो प्राइवेट बसें चलती हैं या एच0आर0टी0सी0 की अपनी बसें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लेकर आती हैं या उस रूट पर जाती हैं उसका किराया ज्यादा और आपकी लॉ फ्लोर बस का किराया कम है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि एक ही सड़क पर दो प्रकार के किराये हैं। बेचारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टज़ तो बुरी तरह परेशान हैं। इसलिए इस बात पर विचार करें कि कब ड्राईवर और कंडक्टर आयेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल की 71 प्रतिशत आबादी रहती है। उसकी अनदेखी

16.03.2015/1600/SS-AG/2

करके केवल 29 या 30 प्रतिशत का विचार करना, इसको छोड़ें। यह सबको सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, जहां तक समाज कल्याण विभाग का संबंध है। मंत्री जी, अभी यहां नहीं बैठे हैं। परिवार की क्या परिभाषा है, मैंने उनसे जानना चाहा था। आज स्थिति ऐसी है कि अगर दादा जीवित है और उसके पोते भी हो गए, परिवार अलग कर दिए, चूल्हा टैक्स अलग है लेकिन जो पैंशन लेने का प्रॅफोर्मा है उसमें लिखा है कि जो अलग भी हुए हैं उनको इकट्ठे कर दो। मतलब यह कि आय की दृष्टि से सबको क्लब कर दो। यह व्यावहारिक बात नहीं है। क्या कभी पोता भी दादा तक साथ रहेगा? यहां तो एक रिवाज़ है कि विवाह के बाद बेटा भी बाप के साथ नहीं रहता तो पोते की आय कहां जोड़ोगे? जब से मनरेगा आया है पटवारी पूछता है कि कितने बच्चे हैं जो 18 साल से बड़े हैं। उन सब को मनरेगा की दिहाड़ी लगा देता है चाहे उनके पास जॉब कार्ड है या नहीं है। वे बूढ़े बेचारे पैंशन से वंचित हो जाते हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो चूल्हा टैक्स अलग देते हैं उस परिवार को अलग माना जायेगा। जो पटवारी सर्टिफिकेट देता है वह केवल जमीन वालों का देता है। अगर

कोई व्यापारी है इन्कम कितनी भी हो, वह केवल उसकी आय लिखता है। पटवारी का लिखा धर्म सत्य माना जाता है। इसलिए पटवारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि कौन-कौन से मापदंड के अनुसार वे इस काम को करें।

स्वास्थ्य विभाग की बात है। मैं सरकार का आभारी हूं कि कुछ नये होस्पिटल खोले। कुछ सी0एच0सीज़0 बड़ी संख्या में बनी हैं और सब-सैंटर भी खोले हैं और मेरे यहां भी त्रिगुवेड़ में एक होस्पिटल का शिलान्यास हुआ। उसके लिए पैसे का प्रावधान भी है। भूट्ठी में पी0एच0सी0 के लिए पैसा है लेकिन लोक निर्माण विभाग न जाने क्यों इन स्वास्थ्य संस्थाओं की जो बिल्डिंग हैं उसमें बहुत कम स्पीड से चलता है।

जारी श्रीमती के0एस0

/1605/16.03.2015केएस/एजी1/

श्री महेश्वर सिंह जारी---

उसमें बहुत कम स्पीड से चलता है। धीमी गति से काम हो रहा है इसलिए मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन कामों में तेजी लाए और जहां तक संस्थान खोलने की बात है। अच्छी बात है, बड़ी संख्या में संस्थान खुले। खराल का क्षेत्र बिल्कुल कुल्लू के सामने हैं। उसमें पांच पंचायतें हैं। इस वक्त वहां की आबादी 11 हजार के करीब है और वह एक सब-सैंटर किंजा के रहमो-करम् पर है । मैंने उसके लिए प्रस्ताव दिया था कि यहां पर पी.एच.सी. खोली जाए और मैं फिर इसके लिए आग्रह करूंगा। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बाहर हैं ,उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह हैं कि वहां पर पी.एच.सी. खोलने पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्याओं के बारे में काफी चर्चा है। मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैंने सब्जी मण्डी की बात कह दी लेकिन जो बीज की बात आई, यह सत्यता है कि इसको सर्टिफाई करने का दायित्व कृषि विभाग का है और अगर कोई बीज जर्मिनेट नहीं करता तो उसकी सजा किसान को क्यों? यह तो वहां असैस होना चाहिए कि कितनी फसल हो सकती थी, उसकी भरपाई सम्बन्धित विभाग करें और जो सर्टिफाई करने वाले हैं, उनको सजा होनी चाहिए कि गलत बीज क्यों सर्टिफाई किया? कई घटिया बीजों की वजह से बीमारी लग जाती है। गेहूं में पीला रोग लगता है, ऐसे बीज किसने सर्टिफाई किए जो किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाते हैं? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

/1605/16.03.2015केएस/एजी/2

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राकृतिक आपदा का सम्बन्ध है। क्षति होती है लेकिन राजस्व मैनुअल में क्या है कि अगर प्राण चले जाए तो पैसे मिलेंगें ताकि उसकी आत्मा को शांति हो जाए लेकिन सर्वस्व चला जाए, जीता रहे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। रेन डैमेजिज़ में जो पैसा आता है, जिनके घर टूटे उनको नहीं मिलता है ।उसके बदले में सामग्री आ जाती है, कहते हैं कि काम करो। अब घर वाला कैसे वहां बैठे और क्या होगा कि अगर समय पर उसके घर के आगे प्रोटैक्शन वॉल नहीं लगी तो अगली बरसात में उसका घर ही गिर जाएगा । जब उसके प्राणा जाएंगें तो सरकार की ओर से एक लाख रुपये दिए जाएंगें कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। अब घर चला गया उसके बाद देना, कहां तक न्याय संगत है? इसलिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि उन लोगों को जिनके घर खतरे में होते हैं, पटवारी की रिपोर्ट पर और नहीं होता तो विकास कार्य में जनसहयोग स्कीम के अंतर्गत पैसा दे दीजिए। 10 प्रतिशत वह खर्चेगा बाकी पैसा सरकार दें ताकि वह अपना घर बचा सके, ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी ऑफ टैम्पल के बारे में यहां पर बात आई और एक माननीय सदस्य ने तो मूर्तियों पर ही शंका जाहिर कर दी कि वही मूर्तियां है या कोई और है। अगर आपको शंका है तो आप आकर देखिए। आज के युग में विधायक महोदय ,(महेन्द्र सिंह जी) गूगल से सब कुछ पकड़ा जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। कहां तो आपको, जिस प्रकार से पुलिस ने उसके लिए मेहनत की, सरकार ने उसमें इंट्रस्ट लिया, जिसके बारे में मैंने

/1605/16.03.2015केएस/एजी/3

माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद किया और आप लोगों का भी आभार व्यक्त किया, ऐसी धार्मिक स्थिति में आप मूर्ति को लेकर अगर शंका पैदा करते हैं तो (***) है आपको। कम से कम you must have verified. ये हमारी भावनाएं हैं। आपको पता होना चाहिए। आप शंका जाहिर करने से पहले पुष्टि कर लेते। इतना बड़ा काम हुआ है, कितनी मेहनत इसमें हुई है? यह धार्मिक भावनाओं का सवाल है। एक बात को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री रिखी राम कौंडलः उपाध्यक्ष महोदय, धिक्कार शब्द असंसदीय है अतः हम चाहेंगें कि इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए ।

उपाध्यक्षः जो असंसदीय शब्द अभी कहा गया इसको कार्यवाही से निकाला जाता है। श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार चोरी की घटनाएं बढ़ी है और अधिकांश चोरिया प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों की हो रही है । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर, नेपाल में गोरखा रेजिमैंट पर सरकार की कितनी विश्वसनीयता थी, आज भी है लेकिन आज देखा गया कि अधिकांश चोर, विशेषकर मूर्तियों के--

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी-

16.3.2015/1610/jt/av/1

श्री महेश्वर सिंह--------जारी

लेकिन आज देखा गया है कि अधिकांश मूर्ति चोर हमारे साथ लगते नेपाल देश से आ रहे हैं। हमारी यहां पर उनके साथ कोई ऐक्स्ट्राडिशन ट्रिटी नहीं है। फलस्वरूप चोर चले जाते हैं और उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की शंका करना अच्छी बात नहीं है और वे चोर किस प्रकार से पकड़े वह बहुत लम्बा इतिहास है। अगर किसी को इस बारे में शंका है तो आये, हम उनके पास इसका निराकरण कर देंगे कि हम वहां पर कैसे-कैस पहुंचे। वहां कौन-कौन गये। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूंगा। पुलिस विभाग में उन लोगों को वहां कैसे भेजा गया। कैसे यह तय किया गया कि वहां उस चोर को पकड़ कर उससे सच्चाई उगलवाई जाए। ऐसी कई बातें हैं जो ओपन में नहीं कही जा सकती। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नेपाल सरकार के साथ हिन्दुस्तान की ऐक्स्ट्राडिशन ट्रिटी अवश्य हो ताकि वहां जो कोई चोर भाग कर जाये तो उसको भी पकड़ा जा सके और उधर कोई गड़बड़ करके इधर आता है तो उसको भी पकड़ा जा सके। जब तक ऐक्स्ट्राडिशन ट्रिटी नहीं होगी वहां चोर पकड़ना सरल नहीं है, यह बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने उसको कैसे हमारे लोगों के हवाले किया, उसमें क्या-क्या हुआ है। विजय सिंह मनकोटिया जी भी सब जानते हैं क्योंकि उनकी बहन की शादी भी हमारे वहां पर हुई है और वह हमारे मामा की बहू है। हमने सारी बातें किस प्रकार की है वे यहां कहने की जरुरत नहीं है। जिनको इस बारे में शंका है उनका समाधान हो जायेगा। जो हमारे से संतुष्ट नहीं होगा तो भगवान उसकी संतुष्टि करें।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक यहां पर मीटरों की बात की गई है तो यह देखना होगा कि आखिर ये मीटर खरीदे कब। ये मीटर कब खरीदे गए इस बात को वैरिफाई करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीटर उसी वक्त के खरीदे हों जो घटिया साबित हुए। इसलिए इस बात की जांच करें कि मीटर कब खरीदे। (---व्यवधान---) तो फिर वर्तमान सरकार की गलती है। (---व्यवधान---) कौन सी बात? उसमें क्या दिक्कत है? मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सबस्टेंडर्ड मीटर कब खरीदे गये? इस

16.3.2015/1610/jt/av/2

बात को देखना होगा। (---घंटी---) मैं समाप्त कर रहा हूं। महेंन्द्र सिंह जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि बिजली का हमारे यहां पर उत्पादन होता है। हमारे यहां उत्पादन होता है तो उस बिजली को वहीं पर क्यों नहीं देते? उस बिजली को ग्रिड में डालकर प्रदेश से बाहर ले जाना या प्रदेश के कोने में ले जाना और फिर वापिस लाना; वह खर्चा भी बचेगा। हमने यह प्रस्ताव रखा था। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिए थे लेकिन जो एम.ओ.यू. उनके साथ हुआ है उसमें यह लिखा है कि यह बिजली पहले नालागढ़ जायेगी। इसलिए उस पर इम्पलिमेंटेशन नहीं हो सकी। मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करें। जहां तक मणिकरण घाटी में मलाणा- i और मलाणा-ii है; बल्कि मलाणा-i की बिजली कुछ दिन सप्लाई हुई है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन आपके भूभूगले से होकर आती है उसकी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी हमारा पूरा ऐसे ही हो जायेगा । इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए। माननीय महेन्द्र सिंह जी ने अच्छा सुझाव दिया है और उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि क्यों न वहां की बिजली वहीं खरीदे। ऐसा करने से ट्रांसपोर्टेशनशिप में जो ट्रांसमिशन लोसिज होती है वह भी खत्म हो जायेगी और हमें सस्ती दरों पर बिजली मिल पायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति और इस माननीय सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपका धन्यवाद।

समाप्त

16.3.2015/1610/jt/av/3

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने जो कहा मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अगर कुल्लू के एक मंदिर में हुइ मूर्ति की चोरी की शिनाख्त गूगल के द्वारा की जाती है तो जो बाकी मंदिरों में चोरियां हुई हैं या बाकी दूसरी जगह भी चोरियां हुई हैं, उसके लिए पुलिस ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। पुलिस या उस एजैंसी को चाहिए था वे उन सभी चोरियों की शिनाख्त उसके माध्यम से करते ताकि प्रदेश का पैसा भी बचता और चोर तथा उनके द्वारा किया गया चोरी का सामान भी पकड़ा जाता। यह मेरा सुझाव रहेगा।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो 'धिक्कार' शब्द का इस्तेमाल किया है इसको ऐक्सपंज किया जाए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, धिक्कार शब्द को कार्यवाही से ऐक्सपंज कर दिया गया है।

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

16.3.2015/1615/negi/jt/1

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 11 मार्च, 2015 को जो अभिभाषण यहां मान्य सदन में रखा है और जिसपर चर्चा पिछले दो दिन से चली है, मैं भी उसपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को हमने भी 2-3 बार बड़े गौर से देखा और पढ़ा है लेकिन इसमें सरकार ने एक वर्ष में या दो वर्ष में कुछ किया, ऐसा कोई कार्यक्रम, कोई नीति देखने को और पढ़ने को नहीं मिली। हां, महामहिम राज्यपाल महोदय ने पहले दो पैरे और अन्तिम दो पैरे पढ़ें। अभी मुझ से पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने महामहिम राज्यपाल के बारे में कहा कि अस्वस्थता के कारण पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। मैं यह कहूंगा कि उनके बारे में सारी दुनिया जानती है और सारा देश जानता है कि वह कैसे कर्मठ हैं और इस उम्र में भी कैसे काम कर रहे हैं। इससे पहले हिमाचल में शायद ही कोई गवर्नर रहा होगा जिसने संजौली चौक में खड़ा हो करके रेहड़ी पर चाट खाया हो । लेकिन वहां पर किसी ने चाट खाया है तो वर्तमान राज्यपाल महोदय ने खाया है। इससे पता चलता है कि उनका स्वस्थ्य बिल्कुल ठीक है तभी उन्होंने वहां पर चाट खाया है । अगर किसी को शक है तो

खुद अपना मुआइना करवाना चाहिए। बड़ी सेहत होने के कारण कोई बड़ा स्वस्थ नहीं होता है और जो मेरे जैसे स्लिम होते हैं वे भी अच्छे/स्वस्थ होते हैं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी के स्वास्थ्य के ऊपर ऐसी शंका जाहिर करना अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो दूसरा पैरा पढ़ा गया है उसमें कांग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र को सरकार ने नीतिगत दस्तावेज़ मान लिया है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय, ज़रा ध्यान देंगे, जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र वर्ष 2012 में बन रहा था तो उस समय दिल्ली में बड़ी राजनीतिक रोटियां पक रही थी । उस समय वर्तमान के मुख्य मंत्री और प्रदेश के अन्य नेता और आपके दो सहयोगी उनका मैं निश्चित तौर पर नाम लूंगा, भाई मुकेश जी और भाई सुधीर शर्मा जी, जो दोनों वर्तमान में मंत्री हैं,ये दोनों लगातार दिल्ली में आपके साथ रहते थे। शायद

16.3.2015/1615/negi/jt/2

आपको पता ही नहीं है कि घोषणा-पत्र में क्या लिख दिया ? क्योंकि उस समय जो घोषणा-पत्र कमेटी बनी, न तो ये दोनों भाई उसमें शामिल थे और न ही आपके कोई सुझाव लिए गए। आपने उसको नीतिगत दस्तावेज़ तो बना दिया और आपने यह कह दिया कि हमने सारे का सारा घोषणा-पत्र इम्प्लीमैन्ट कर दिया । मुझे लगता है, न तो इसको आपने पढ़ा और न ही इन दोनों मित्रों ने पढ़ा और न ही मुकेश अग्निहोत्री जो आपको लगातार सुझाव देते रहते हैं उन्होंने सुझाव आपको दिया कि ऐसा लिखना जायज है कि नहीं है । इसलिए निश्चित तौर पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह समझा कि इसको पहले दो पैरा और अन्तिम दो पैरा पढ़ कर, पढ़ा हुआ समझा जाए। यह सही है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अगर आप देखेंगे तो आपके ये जो पैरे हैं इसमें शिक्षा पर 3 से ले करके 13 तक पैरे हैं। आज प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है इस बारे में मेरे से पूर्व वक्ता यहां बोल चुके हैं और उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर बड़ा चिन्तन किया है। अच्छा होता कि आप घोषणाएं करने के बजाय प्रदेश के पूरे शिक्षण संस्थानों का एक डाटा/खाका तैयार करते। अच्छा होता, सारी स्थिति आपके पास आ जाती । उसके बाद हमारे क्षेत्रों के जो लेक्चरर बिना मतलब के ट्राइब्ल क्षेत्रों में बैठे हुए हैं ,जहां सब्जैक्ट पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है, वहां कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वहां पर ऐसी स्थिति है, बताया गया है

कि वहां पर बच्चे दो हैं और टीचर 7-7 हैं। ऐसी स्थिति प्राथमिक पाठशालाओं की भी हैं, मिडल स्कूलों में भी हैं, उच्च-पाठशालाओं में भी है और प्लस टू स्कूलों में भी है। अगर आप उनको स्ट्रैंथन करने की, मज़बूती प्रदान करने की और शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कोशिश करते तो शायद हम मानते कि वाकयी आपने एक वर्ष में कुछ काम किया। आपने निश्चित तौर पर शिक्षा के ऊपर बड़ी घोषणाएं कर दी। आप जहां जाते हैं वहां घोषणा करते हैं। आप हमारे क्षेत्र में भी गए । आपने जिला कांगड़ा का दौरा किया । पिछले डेढ़ महीने से आप लगातार निचले क्षेत्रों में रहे। आप हमीरपुर में रहे, ऊना में रहे, कांगड़ा और चम्बा में रहे। अच्छा है ,मुख्य मंत्रियों का प्रवास कई सालों से ऐसा चला हुआ है और यह चलना भी चाहिए। इससे लोगों को नज़दीक प्रशासन देखने को मिलता है। लेकिन उसके पीछे विकास को तवज्ज़ों देने की और

16.3.2015/1615/negi/jt/3

लोगों की समस्याओं को हल करने की मन्शा रही है। शायद वो की होती तो शायद हम मानते और हम आपका यहां समर्थन करते । मुख्य मंत्री महोदय, यह हंसने की बात भी नहीं है और स्मॉइल देने की बात भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई समय था, उस समय प्रदेश में हर कोई चाहता था, विधायक भी चाहता था कि...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

16/03.2015.1/620यूके/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंह---जारी----

हर कोई विधायक चाहता था कि मुख्य मंत्री मेरे क्षेत्र में आ कर उद्घाटन करे । चाहे वह विपक्ष का है या पक्ष का है हर कोई चाहता था । बाकी कोई काम होते थे या नहीं होते थे, यह मुझे पता नहीं । पानी की कोई योजना बनी या कोई स्कूल अपग्रेड हुआ कोई पता नहीं, नया कोई अस्पताल खोल दिया, कोई पता नहीं । लेकिन एक काम जरूर होता था, जहां मुख्य मंत्री जी जाते थे वहां सड़कों का पूरे प्रदेश में सुधार जरूर हो जाता था । वहां पर सड़कों को ऊपर एकदम ब्लैक टॉप कर दिया जाता था। मुख्य मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है आपसे जरा हमारे साथ चल कर देखिए । जिन-जिन क्षेत्रों में आप जा कर आए हैं, वहां की सड़कों का हाल ,मीटर-मीटर गड्ढे पड़े हुए हैं और आज उन गड्ढों को भर रहे हैं, बरसात हो रही है, मिट्टी उड़ रही है,

कीचड़ हो रहा है, कई ऐक्सीडैंट्स से इसी कारण से हो रहे हैं । यह समस्या आपकी नहीं है, समस्या यही है क्योंकि बड़ा हैवी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का आपके ऊपर बड़ा भारी एडमिननिस्ट्रेशन का बोझ है । उसमें हैवी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई करटेल आप कर दें । उसमें एक काम करें कि क्योंकि उसका सारा बजट कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जाता है, उसमें उसके रख-रखाव के लिए भी बजट होना चाहिए । रख-रखाव के लिए किसी विभाग में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, कोई पैसा नहीं है उसके लिए आज के दिन में । इन सड़कों की मेनटेनेंस के लिए आज दिन तक कोई पैसा नहीं है । आप गए हमारे क्षेत्र में आपने वहां पर बड़े भाषण किए, उसके ऊपर मैं निश्चित तौर पर कहूंगा । लेकिन ये दो बिन्दु एक शिक्षा का मैने कहा और साथ में लोक निर्माण विभाग के ऊपर । हालांकि कई अधिकारी अच्छे सक्षम है काम करने के लिए । लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनके ऊपर कुछ काम हो रहा है । क्योंकि एक भी पैरा सड़कों के ऊपर नहीं है । कुछ किया होता तब तो पैरे आते, किया ही कुछ नहीं है। पैरा कहां से आयेगा ? आपने पुल इतने बना दिए, आपने इसमें लिखा है कि 27 पुलों का उद्घाटन किया । 27 पुलों में से एक भी पुल बनाने के लिए कोई पैसा दिया गया है तो बताइए । जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 पुलों का आप उद्घाटन करके आए । सारे का सारा पैसा तब का है और आपके द्वारा

16/03.2015.1/620यूके/एजी/2

उन पुलों का मेरे ख्याल में 9 महीने हो गए हैं, जनता को वहां आने-जाने में कितनी समस्या आ रही है, अगस्त 2014 को तैयार हो गए थे, उदघाटन मांग रहे थे, लेकिन बीच में काम लटका दिया गया । मैने यहां पर प्रश्न भी किया था, उसके बाद उसको थोड़ा ऐक्टिवेट किया गया । उसमें थोड़ी ऐपरोचिज़ वगैरहा बनाने को थीं । पूरे प्रदेश में ऐसी ही स्थिति है । जिन पुलों के निर्माण के लिए जहां पुल बन गए हैं, आप उद्घाटन करते रहिए । आपको शौक है, मुझे मालूम है कि आपको वहां पर नाम लगना चाहिए, आपको बड़ा शौक है । लेकिन वह बाद में भी हो सकता है । ट्रैफिक आने-जाने के बाद भी यह हो सकता है । उसमें रुकावट नहीं पड़नी चहिए । आवागमन ठीक रहे तो उन पुलों का निश्चित तौर पर हमें फायदा मिलेगा ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैने एक बड़ा गम्भीर विषय पीछे यहां पर उठाया था, वन माफिया का । निश्चित तौर पर मेरा वह विषय अभी भी जारी है । आपने धर्मशाला में कहा था कि रिपोर्ट आने पर मैं ज़ीरो टॉलरैंस के तहत कार्रवाई करूंगा ।

यह आपकी स्टेटमैंट है । आपने क्या कार्रवाई की? मैने अध्यक्ष महोदय को सी0डी0 दी थी, इन्होंने भी देखी थी, वह पैन ड्राईव इन्होंने भी देखा है । मै आपको भी उसकी कॉपी दे दूंगा । मेरा निवेदन है आपसे कि उस पर आपने कुछ कार्रवाई की होती तब भी मैं मान जाता। मुख्य मंत्री महादेय, 22 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में वहीं पर एक और DFO चम्बा वहां एक बीट है, तंग नाम की बीट है, उस तंग नाम की बीट में 43 देवदार के खड़े पेड़ 22 से 27 फरवरी के बीच में काटे गए हैं । यह काम रुका नहीं है । वहां बर्फ पड़ी हुई है लेकिन बिल्कुल अन्धाधुन्ध कटान रुका नहीं है, अभी भी कटान वहां पर हो रहा है । यह किसका आशीर्वाद है, यह क्यों हो रहा है? यह सारे तथ्य जांच करने के लिए है, मैने बार-बार आपसे निवेदन किया है । मैने उस समय भी कहा था । आप तो कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया था कि मैं वनों की रक्षा करूं । लेकिन आज के दिन यह हो क्या रहा है ? रोहड़ू में जंगल कट गए, खबर लगी हुई है । नालागढ़, मंडी जिले में और नदौन जंगल कट रहे हैं, वहां खबरें

16/03.2015.1/620यूके/एजी/3

लगी हुई है । प्रदेश में वन माफिया इतना हावी आज के दिन में है, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है । लेकिन यहां जिक्र तक नहीं है । यह जिक्र क्यों नहीं है? क्यों यह निरन्तर हो रहा है । कौन इसके पीछे है? जो लोग वहां पर आपने अरेस्ट किए हैं, उनका उसमें कोई कसूर नहीं है । मुख्य मंत्री महादेय, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं । जो आपका सहयोग करना चाहते हैं, उनको तो आपने थाने में ला कर बन्द कर दिया । उनका इसमें कोई लेना-देना नहीं है । उनकी केवल एक-एक साल की गार्ड की नौकरी हुई है । उनको तो बेचारों को कोई ऐक्सपीरिएंस भी नहीं हैं और उनको आपने जेल में बन्द कर दिया । उनका कसूर कोई नहीं है और जो कसूरवार है वह बचा हुआ है । जो सबसे बड़ा कसूरवार है उसको आपने चम्बा से हमीरपुर ट्रांसफर कर दिया, ले भाई तू चम्बा साफ करके आ गया अब हमीरपुर के क्षेत्र जो भी साफ करना है वह कर ले । उसको आपने इनाम दिया ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1625/sls-ag-1

श्री रविन्द्र सिंह ... जारी

ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, उनको आप सम्मानित कर रहे हैं लेकिन जो लोग अभी ट्रेनिंग पर हैं, उनको ससपैंड किया जा रहा है। मुख्य मंत्री महोदय, यह अच्छी

बात नहीं है। उस समय आपने जो जीरो टौलरैंस के बारे में कहा था ,इसमें आपसे मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। ताकि जो वन माफिया पूरे प्रदेश में हाबी होता जा रहा है ,उसे नियंत्रित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। प्रदेश में पिछले दो-अढ़ाई सालों से पूरा-का-पूरा राज माफियाओं का हो गया है। वह चाहे वन माफिया हो, कानून-व्यवस्था को खराब करने वाला माफिया हो, खनन माफिया हो या ड्रग माफिया हो; यह सारे माफिया आज के दिन पूरे प्रदेश में पनपे हैं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अभी आपने पूरे प्रदेश का दौरा किया। नीचे गए थे। लोगों ने मिलकर आपके ध्यान में कई बातें लाईं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था का क्या हाल है ,ज़रा आप इन तथ्यों के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे। सुन्दरनगर, चम्बा, मनाली का दुष्कर्म, डैहर में नशा पिलाकर नाबालिग लड़की से रेप, चुराह में विवाहिता से दुष्कर्म के बाद मारपीट, युवती से दुराचार; ऐसे मामले आज के दिन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसे ही कण्डाघाट में ममलीग के बुजुर्ग की हत्या, अपनो ने आबरू लूटी आदि। एक केस है, फॉदर इसमें जेल में बंद हैं, इसमे दो राय नहीं है। लेकिन उस परिवार की इस लड़की का मैंटल डिसआर्डर हो गया है। छः महीने हो गए जब डी० सी० कांगड़ा ने एक केस आपके पास भेजा कि उसकी कोई सहायता की जाए। लेकिन अभी तक डी० सी० भी इंतजार में है कि सरकार की ओर से मुझे कुछ कहा जाए कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। ऐसे ही केस सारे प्रदेश में हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिला हमीरपुर का आदित्य केस है। अभी तक पता नहीं है कि वह बच्चा कहां है। उसके बाद हमीरपुर में एक और घटना हुई। चोरों ने पक्का बरोह से बच्चे का अपहरण। कुछ ही दिनों के

बाद वहां एक और घटना हुई, 15 फरबरी से वह लापता भी है। साथ ही, एक और बच्चे को अगवा करने का हुआ था प्रयास। अभी भी वह काम चला हुआ है। मैं आपको एक घटना बताऊं। मुख्य मंत्री महोदय, मुझे याद है। उस समय हम विपक्ष में थे आप मुख्य मंत्री थे। यह 2003-07 के बीच की बात है। मेरे पुराने विधान सभा क्षेत्र का एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए धर्मशाला गया। वहां पोस्ट ऑफिस में इंटरव्यू देने के बाद डी० सी० ऑफिस के बाहर बस का इंतजार कर रहा था। वहां

पर एक वैन आई और वैन से उसको पूछा कि क्या यह सड़क पालमपुर जाती है? उसने कहा 'हां'। गाड़ी चलते-चलते रुक गई और उसको पूछा कि आप कहां जाना चाहते हैं? उसने कहा कि पालमपुर की ओर। उन्होंने उसको बिठाया और गाड़ी में वह बेहोश हो गया। वहां से वह लड़का गायब हुआ। सात दिन के बाद उसका फोन चेन्नई से आई। पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ढूढ़ती रही। चेन्नई में कैसे-न-कैसे किसी मंदिर में पहुंचा जहां से उसने फोन किया कि मैं इस स्थान पर हूं। फिर लम्बागांव थाने की पुलिस उसको लेकर आई थी। जब हमने सारी स्टोरी सुनी ,उस समय धर्म परिवर्तन की बात चली हुई थी और पालमपुर थाने में भी उस समय बड़ा हंगामा हुआ था। उसी कड़ी का वह हिस्सा था। आज के दिन भी पूरे हिमाचल में बच्चों के अपहरण के ऐसे कांड हो रहे हैं। मेरे मित्र चले गए। उन्होंने कहा कि गुग्गल में कोई ढूंढ़ रहा है। अगर कोई गुग्गल है तो ढूंढ़ लो। गुग्गल को ऐसे काम में लगाओ ताकि यह सारे अपराधी पकड़े जाएं। चोरी, डकैती, आत्महत्या करने के लिए उकवाने वाले सारे पकड़े जाएं।

मुख्य मंत्री महोदय, पिछले साल रामपुर में किन्नौर की लड़की के साथ वारदात हुई। चारों ओर दरिंदगी की निगाह, नहीं मिली पनाह। यह बच्ची, उपाध्यक्ष महोदय, किन्नौर से चल कर रामपुर अपने परिजनों से मिलने के लिए आई थी। यह 16 जनवरी, 2014 की बात है। वह शाम को लेट पहुंची। जहां उसने जाना था, उनका मोबाईल बंद था और उसको आने-जाने का कोई पता नहीं था। वहां से उसने जाने के लिए ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शा वाले समझ गए कि यह लड़की भूल गई है, इसलिए उन्होंने उसको अगवा किया। वह उसको किसी गैस्ट हाऊस में ले गए। फिर

16.03.2015/1625/sls-ag-3

वहां से छूटकर वह लड़की भाग गई। बस स्टैंड पर पहुंची तो पीछे गैस्ट हाऊस के दो लोग वहां से आए। अख़बार में उनके नाम भी लिखे हैं। एक विशाल कश्यप और वहां का होटल मैनेजर योग राज, दीपक गैस्ट हाऊस। इन्होंने वहां आकर उसको किडनैप किया और 4 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे और उसके बाद उसको किन्नौर की बस में बिठाया।

जारी ..गर्ग जी

16/03/2015/1630/RG/JT/1

श्री रविन्द्र सिंह---------क्रमागत

और चौथे दिन उसको रात को किन्नौर की बस में बैठाया। यह किन्नौर की बच्ची के साथ रामपुर की घटना है। ऐसा नहीं है, यह सारे प्रदेश में हो रहा है। ऐसे ही काण्ड जिला कांगड़ा में भी हुए हैं ,प्रदेश के जिला कांगड़ा का तो आपको पता ही है। बैरगट्टा जहां दो पुलों का आपने शिलान्यास किया जो विधायक प्राथमिकता में थे। वहां आपको एक बहुत बड़ा डेपुटेशन मिला। वहां ये सी.पी.एस. (श्री जगजीवन पाल की ओर इशारा करते हुए) साहब भी गए थे, इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। वह बच्ची 11 साल की शादी में आई थी ,उसका बलात्कार हो गया। सभी को मालूम है कि किसने किया? आज पुलिस उस पर हाथ क्यों नहीं डाल रही है? ये सी.पी.एस. साहब गए थे, ये बोलते ज्यादा हैं, इनको बैठे-बैठे बोलने की आदत है। ये वहां बोलकर आए हैं कि मैं इसकी सी.बी.आई. से जांच कराऊंगा। अभी तक तो अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हुए, इसकी जांच क्या होगी? इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र देहरा के ठाकुरद्वारा का एक व्यक्ति पालमपुर में रहता है ,आपको कुछ लोग भी देहरा में मिले हैं। उसका बनूरी के पास मर्डर हो जाता है, औटर गांव में वह गिर जाता है ,तो पुलिस ने केस बना दिया कि ऊपर ढाक से नीचे गिरने से वह मर गया और जब नीचे देखते हैं, तो चार गिलास और बोतल वहां पड़े हुए थे। अब आप ही बताइए जब वहां सब कुछ पड़ा हुआ है और सामने नजर आ रहा है। उसके साथ तीन या चार और भी लोग थे ,तो वह आत्महत्या कैसे हुई, वह गिर कैसे गया? यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला भी मेरे विधान सभा क्षेत्र देहरा का है। नदौन पुल के ऊपर अभी पीछे हाल ही में एक-डेढ़ महीने पहले किसी को वहां मारकर फेंक दिया और आज तक उसका कोई पता नहीं है कि वह कहां है? ऐसे ही नौरा कॉलेज की पूजा ,आप कहां घूम रहे हैंख् घर में मार दी। बच्चों ने आंदोलन किया और अभी तक पूछने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ,ये कुछ चुनिन्दा मामले हैं बाकी कितने केस आत्म हत्या में बदल दिए ,वह एक अलग बात है। लेकिन जिला कांगड़ा का ऐसा ही हाल है, वैसे तो सारे प्रदेश में ही यही हाल है। मैं आपको उसकी जानकारी यहां दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार प्रदेश में यह 'काला ने फैला रखा है काला साम्राज्य" ,जैसे मैंने ड्रग्ज की बात की। शायद आपने उसके कुछ सहयोगी गिरफ्तार

भी किए हैं। यहां ड्रग्ज का कितना धंधा हो रहा है। पुलिस ने पूरे प्रदेश में बैरियर्ज लगाए हुए हैं ,ज्यादा चैकिंग उनकी होती है जिन्होंने हैलमैट नहीं पहना है उनके

16/03/2015/1630/RG/JT/2

ज्यादा चालान होते हैं या गाड़ी में बैल्ट नहीं पहनी है, तो गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि बैल्ट नहीं लगाई है अब आपका चालान होगा। ये जो मनाली से रातों-रात यहां गाड़ियां पहुंचती हैं उन गाड़ियों को आप चैक करो कि उन गाड़ियों में क्या आ रहा है? ये प्राइवेट बसिज जो लम्बे-लम्बे रूट्स पर चलती हैं आप उनके ड्राईवर और कन्डैक्टर्ज को पूछिए कि वे उन गाड़ियों में भरकर क्या ले जाते हैं? आप उन प्राइवेट बसों की तलाशी लेना शुरू करें ,जो बड़े-बड़े प्राइवेट बसों वाले हैं, सारे-का-सारा यह काला सोना उनमें आ रहा है। मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है और यही नहीं अभी 12 और 13 मार्च की रात को मेरे विधान सभा क्षेत्र मानगढ़ में देहरा के पास रात को एक ट्रक पलट गया और ड्राईवर एवं कंडैक्टर भाग गए। उस एक ही ट्रक में लगभग 90 भैंसें भरी हुई थीं। जो कार वाला लपेट में आया वह भी भाग गया। उन 90 भैंसों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने वहां मदद की। उस ट्रक का नंबर उत्तर प्रदेश का था। मैं वही कह रहा हूं कि स्थानीय लोगों का कोई ट्रैक्टर बजरी वाला आ रहा है, तो उसका भी चालान कर रहे हैं ,उसको पकड़ रहे हैं , लेकिन ऐसी-ऐसी गलती करने वालों को नहीं पकड़ते। वह ट्रक भी कैसा था पूरा ट्राला था। उसमें तीन स्टोरीज़ थीं और उनमें भैंसों को भरकर ले जा रहे थे। वह ट्रक वाला चंबा से चलता हुआ इस रास्ते से होता हुआ आया और उसका वहां तक किसी ने पूछा तक नहीं। मेरा कहना यही है कि ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है और बॉर्डर ऐरियाज़ में ज्यादा हालत खराब है। पांवटा साहिब से लेकर नूरपुर और चंबा तक के क्षेत्र में चिट्टा-पन्नी के नाम से एक नशा बिक रहा है। यह नशा स्कूलों के नजदीक ज्यादा बिक रहा है जिससे हमारे सारे स्कूल तबाह हो गए। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर आप चैकिंग करिए। मुझे याद है कि थुरल जमा दो स्कूल में एक स्टेशनरी की दुकान है उस दुकान में व्हाइट फ्ल्यूड की एक साल की सेल तीन लाख रुपये की हुई। उसने व्हाइट फ्ल्यूड की छोटी-छोटी शीशियां बेचीं। उसमें नशा होता है। बच्चे उसको रूमाल में डालकर सूंघते हैं। स्कूल में मैट्रिक, प्लस वन एवं प्लस टू के बच्चों को होश ही नहीं था। इसलिए मेरा कहना यह है कि प्लस टू स्कूलों के नजदीक चेकिंग शुरू करवाइए ताकि इस नशे पर काबू पाया जा सके और इस पर नियंत्रण

पाया जा सके। इस नशे से हमारी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। इससे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो रही है।

16/03/2015/1630/RG/JT/3

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत ठीक नहीं है। यहां से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उठकर चले गए। सारे प्रदेश की स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति को तो सारे लोग जानते हैं। यहां स्टाफ की कितनी कमी है, हमने बार-बार यह मुद्दा सदन में उठाया, परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ और इसके अतिरिक्त डेपुटेशन का सिलसिला अभी भी बन्द नहीं हुआ। अभी प्रागपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सिंगल डॉक्टर था जिसको कांगड़ा में लगा दिया-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

16/3/2015/1635/MS/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी---------

अभी भी हमारे वहां परागपुर प्राइमरी हैल्थ सेंटर से जो एक सिंगल डॉक्टर था, उसको डेपुटेशन पर कांगड़ा में लगा दिया। पिछले सत्र में धर्मशाला में इस बारे में चर्चा हुई थी और उस समय कहा गया था कि डेपुटेशन पर किसी को नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी तीन-चार दिन पहले ही यह ऑर्डर हुए हैं।

आज स्वाइन फ्लू पूरे प्रदेश में फैल रहा है। पता नहीं मुख्य मंत्री जी आपकी स्वास्थ्य मंत्री महोदय के साथ कैसी है कैसी नहीं है, हमें इन बातों से क्या लेना-देना लेकिन आप उद्घाटन के बाद जब गए थे तो आपने उस समय भी कहा था (घण्टी) उपाध्यक्ष जी, मैं तो बहुत अच्छे सुझाव दे रहा हूं। अभी तो शुरूआत है। आप स्वयं ही देख लीजिए कि मुझे बोलते हुए कितना समय हुआ है। उपाध्यक्ष जी, स्वाइन फ्लू से 22 फरवरी तक पांच मौतें हो चुकी थी लेकिन मुख्य मंत्री जी, तब तक आपकी इस बारे में कोई स्टेटमैंट नहीं आई थी कि स्वाइन फ्लू के रोग के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप देहरा और जसवां-परागपुर में गए तो 22 तारीख को आपकी स्वाइन फ्लू के बारे में पहली स्टेटमैंट लगी थी। उससे पहले जिला कांगड़ा में आप घूमते रहे। आपने स्वास्थ्य विभाग पर कोई टिप्पणी करने से

किनारा ही कर दिया कि इस पर कुछ नहीं बोलना है। आप तो मुख्य मंत्री है इसलिए आप कह सकते थे। मयाड़ा के पी0एच0सी0 का शिलान्यास करते वक्त आप कहते हैं कि यह नाम बीच में क्यों आ गया? वह नाम कौल सिंह जी का था। आपने ऐसा कहा था ,मेरे पास फोटो पड़ी हैं। इसी तरह से देहरा में आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन का उद्घाटन करते वक्त भी आपने कहा था। आपने सी0एम0ओ0 को कह दिया था you are suspended. आपने उनको मौके पर सस्पैंड कर दिया था। सारे काम कीजिए लेकिन मेन काम है कि लोगों को राहत दी जाए। स्वाइन फ्लू का प्रदेश में बुरा हाल है। इस बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका प्रकोप इतना ज्यादा हो गया है कि इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बाहर चले गए हैं। मेरा निवेदन है कि जितने भी डॉक्टर्ज ,ऑफिसर्ज और अन्य स्टाफ है, इनकी ड्यूटि लगाइए। ये पूरे प्रदेश में घूमें और वहां जाकर देखें कि कितने लोग इस बीमारी

16/3/2015/1635/MS/AG/2

से पीड़ित हैं। लोगों को इसकी दवाई नहीं मिल रही है जो आप कह रहे हैं कि वहां पर दवाई मिलेगी। आप लोग तो मुंह में मास्क लगाकर सब जगह घूम लेते हैं लेकिन पूरे प्रदेश में हालत खराब है। कौल सिंह जी आ गए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो यह आउसोर्सिंग वाला किस्सा है, यह प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए सही नहीं है। आपने पहले सारे टैस्ट्स प्राइवेट लैब में कह दिए कि वहां होंगे। मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं। मैंने अपनी धर्मपत्नी का टांडा में टैस्ट करवाया। आप हैरान होंगे, जब रिपोर्ट मेरे पास आई तो उसमें उनको 240से ऊपर शुगर बता दी। मैं भी परेशान और जिसको समस्या है, स्वभाविक है कि वह तो परेशान होगा ही। मैं फिर उनको लेकर प्राइवेट लैब में गया। मैं पालमपुर में एक प्राइवेट लैब में गया तो वहां रिपोर्ट नॉर्मल निकली। इस तरह से इस आउटसोर्स के कारण पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा, जहां-जहां आपने ये लैब खोली हैं ?इसलिए इसको चैक कीजिए। उन लैब्स में गलत रिपोर्ट्स आती हैं क्योंकि वहां पर ट्रेंड स्टाफ नहीं है।

इसी तरह से आपने एक नया शोशा नर्सों को आउसोर्सिंग का कर दिया। जब आपके पास ट्रेंड नर्सिज हैं और नर्सिज की शॉर्टेज आपके पास है तो उनको आउटसोर्सिंग में क्यों कर रहे हैं? उनकी सीधी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? इसी तरह से जब आपके पास हिमाचल में सुबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड हमीरपुर

है तो टीचर्स की भर्तियां एस0एम0सी0 से क्यों होगी? मेरा कहना है कि ये क्यों करेंगी? आप उनको टीचर्स की भर्ती के लिए एस0एस0एस0बी0 को कहो, वह चार महीने में सिलैक्शन करके देगा और नर्सों की भर्ती के लिए भी आप सुबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड हमीरपुर को कहो।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः इसी तरह से प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जो 'कौशल विकास भत्ते' की बात की गई है, उसका तो आपने दिवाला निकाल दिया है। आप लोगों ने वर्ष 2003 के चुनाव के समय में कह दिया था कि हर परिवार के सदस्य को हम नौकरी देंगे। आप वर्ष 2003 से लेकर पांच साल राज करके चले गए लेकिन किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। वर्ष 2012 में आपने नया शोशा छोड़ दिया कि हम दसवीं, जमा दो

16/3/2015/1635/MS/AG/3

और इससे ऊपर के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैंने यही तो कहा कि इन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बेरोजगार नौजवान जो पढ़े-लिखे हैं, उनके साथ इतना अन्याय मत कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी हमारे सम्माननीय नेता यहां बात कर रहे थे तो इन्होंने उस समय कहा था कि आप तथ्य लेकर आइए। मुख्य मंत्री जी, प्रदेश में ट्रांसफर्ज का बुरा हाल है। आपने जितने भी हारे हुए लोगों को चैयरमैन और वाइस चैयरमैन बनाया है, इनका वन प्वांइट प्रोग्राम है और कोई काम नहीं है। लिस्टें लेकर आओ। जितनी आपकी एप्रूव लिस्टें हैं सारी की सारी एप्रूव। मैं लिस्ट के ऊपर बोल रहा हूं। जैसे एक आपका यह एसोसिएशन ऑफ स्कूल प्रिंसिपल्ज एण्ड इन्सपैक्शन ऑफिसर्ज है, माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे। इन्होंने लिस्ट दे दी। मैं इसे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लिस्ट लम्बी है। उन्होंने पूरी लिस्ट दी है। इसमें लिखा है कि राजा साहब,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

16.3.2015/1640/जेके/जेटी1/

श्री रविन्द्र सिंह :--------जारी-----

लिखा है कि - I have written to your goodself that such and such are the workers of RSS and BJP, फलां-फलां । ये लिस्ट दी हुई है। यह जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है यह मैं आपको दे रहा हूं। मैं इसको इस माननीय सदन में ले कर रहा हूं। This is Association of School Principals and Inspection Officers. इसका एडवाईजर राजेन्द्र वर्मा है और इसका चीफ एडवाईजर श्री जोगिन्द्र सिंह राव, प्रिंसिपल डाईट ,बिलासपुर। दूसरा प्रिंसिपल हमीरपुर है। इन्होंने सारी की सारी सूची दी है और आपने अप्रूव कर दी है। आपके हाथों से अप्रूवड है। इस तरह से एक और चिट्ठी श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया की भी है। ये सारी अप्रूवड है और आपके दस्तखत से अप्रूवड है। All approved.

Chief Minister: You put it on the Table of the House.

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी मैं इस सारे को यहां पर ले कर रहा हूं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो चेयरमैन्ज और वाईस चेयरमैन्ज को आपने काम दिया है इनको वही काम करवाओ और जो वे इस तरह का काम कर रहे हैं उसको बन्द करवाओ। स्कूल खाली हो गए, हॉस्पिटल्ज खाली हो गए । इनका काम ही यह हो गया है कि पैसे इकट्ठे करना। मुझे याद है जब आपके पास एक बार थुरल का केस आया था तो आपने अपने उस कार्यकर्त्ता को कहा था कि अरे भई कमाता है तो कमाने दो उसको, तुम भी लाया करो, तुम्हारे आदमियों की भी ट्रांसफर करता रहूंगा। ऐसी स्थिति तो आप खुद पैदा करते हैं। यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कांगड़ा सेन्ट्रल कॉप्रेटिव बैंक का मामला मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। 10 करोड़ रूपया 31 ,मार्च, 2014 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर हो गया। न तो उसने इतनी मांग की थी, उस बैंक ने कोई भी पैसे की मांग नहीं की थी और बाद में कहते हैं कि यह तो होता रहता है। क्या इसकी जांच करवाएंगे? कितना भारी उसमें लेनदेन हुआ?

16.3.2015/1640/जेके/जेटी/2

कांगड़ा बैंक जो हमने 90 करोड़ रूपये के प्रोफिट पर छोड़ा था आज वह 18-17करोड़ पर आ गया है। इतनी लूट पड़ी हुई है। विदेशों में उनको भेजो जो वहां से आकर यहां पर काम करेंगे। मैं यहां पर संत्रियों को भी कहा रहा हूं, विधायकों और मंत्रियों को भी कह रहा हूं कि विदेश में जाना अच्छा होता है लेकिन विदेश से जो कुछ सीख कर आते हैं उसको प्रदेश में इम्पलीमैंट भी करो। मजा तब आता है। प्रदेश के पैसे की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि यह प्रदेश की जनता का ही पैसा है। घूम करके क्या इसलिए आए थे कि 31 मार्च को कांगड़ा सेट्रल कॉप्रेटिव बैंक का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों को ट्रांसफर कर देंगे। मेरे पास इसके तथ्य है। --- घण्टी--आपको उन्होंने रिपोर्ट की है, जो पैशनर्ज इस बैंक के हैं। कितनी लूट प्रदेश में मची है? इसको सम्भालने की आवश्यकता है। बोलने को तो बहुत कुछ है। उपाध्यक्ष महोदय आपकी घण्टी और आपका बार-बार यह कहना कि समाप्त करें।

अंत में एक बात करते हुए मेरा निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे सैन्ट्रल यूनिविर्सिटी के बारे में है। अब तो आपके पास सारे तथ्य आ गए हैं। मैं इसमें कोई लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं। अभी-अभी परिवहन मंत्री जी ज़वाब दे रहे थे आई.आई.टी. ऊना के बारे में। उसमें वे यह कह रहे थे कि ये जो नोटिफिकेशन हुई है यह भारत सरकार ने की है। जैसी नोटिफिकेशन आई.आई.टी. ऊना की हुई है हम उसको इम्पलीमैंट करते हैं तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप दो कानून एडॉप्ट क्यों कर रहे हैं?

(अध्यक्ष महोदय पीदासीन हुए)

दोहरा मापदण्ड क्यों है? यह 23 अप्रैल, 2010 की चिट्ठी है। डायरैक्टर, एच.आर.डी. दिल्ली , आर.डी. सहाय की है। एस्टैब्लिशमैंट ऑफ सेन्ट्रल यूनिविर्सिटी ,मैं बार-बार कह रहा हूं, इसकी कॉपी में ले कर दूंगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि धर्मशाला अच्छा नहीं है और मैं यह नहीं कहता हूं कि देहरा बहुत अच्छा है। यह चिट्ठी जो

16.3.2015/1640/जेके/जेटी/3

इम्पलीमैंट आपने कहा आई.आई.टी. ऊना को, आप दोहरे मापदण्ड को न करो, उसी तरह से इसको देहरा में इम्पलीमैंट करो, यह मेरा आपसे निवेदन है। 900

कनाल जमीन सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। मैं अपने छोटे भाई, श्री सुधीर जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये संस्थान राजनीति के अखाड़े नहीं होने चाहिए। जो जगह आपने वहां पर दी है ,ये मेरे पास सारे तथ्य आ गए हैं। वहां पर यह लिखा हुआ है कि खाता नम्बर 114, मिन 140, मिन गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन खड्ड ,गैर मुमकिन खड्ड आदि। ये सारी की सारी खड्डे हैं। Central University means something. आने वाले समय के लिए हमारे बच्चों का भविष्य है। आप चल कर देखो तो सही। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप स्पैशल आईये मैं आपक स्वागत करूंगा, आप उस जगह को देखिए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

16.03.2015/1645/SS-AG/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी..

मैं आपका स्वागत करूंगा। आप जगह को देखिये जो इसके लिए सिलेक्ट की है, जो हमने ट्रांसफर की है। दोनों की तुलना करिये। उस समय साइट सिलैक्शन कमेटी आई थी। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा है कि कितना सुन्दर दृश्य है एक तरफ पौंग डैम नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ धौलाधार की रेंजिज़ नज़र आ रही हैं। शायद विश्व में ऐसा स्थान कहीं नहीं होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस राजनीति को छोड़ते हुए 7 0परसैंट हिस्सा, जो नोटिफिकेशन है, वह देहरा में और 30 परसैंट धर्मशाला में है। धर्मशाला, कांगड़ा जहां आपकी इच्छा है वहां करें। मेरा निवेदन है कि वहां पर 900 कैनाल जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। यह तो लेटैस्ट चिट्ठी है जो भारत सरकार को चली गई है कि धर्मशाला में जमीन ही नहीं मिली। जो लेटैस्ट साइट सिलैक्शन कमेटी आई थी उसने भी धर्मशाला को रिजैक्ट कर दिया है।

--(व्यवधान)-- यह तो खड्ड-खड्ड है। फिर आप कहेंगे कि खड्ड क्या है? फिर बोलेंगे कि डिलीट कर दो।

Speaker: Hon. Member, please wind up.

श्री रविन्द्र सिंहः मेरा आपसे निवेदन है कि ये सारे बिन्दु सामने रखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण 11 तारीख को दिया ,मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। उनकी मंशा ठीक थी लेकिन जब आपने एक साल या डेढ़ साल में किया कुछ नहीं तो फिर करने को था क्या?

पार्लियामैंट अफेयर मिनिस्टर चले गए। एक तरफ आपने खेलों के बारे में लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कुछ कहना चाहता हूं। एक विषय है। यह धर्मशाला सैशन के दौरान भी उठा था। यह पूजा देवी सुपुत्री जगदीश राम, जाति हिन्दू गुज्जर, ऊना की है। कबड्डी में नेशनल खेल कर आई है। जब प्रदेश की सिलैक्शन की बारी आई तो आपने मुझे वहां कहा था कि इसका सिलैक्शन हो जायेगा। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है, कॉपी साथ में है। इसके पीछे कारण क्या बना? एक आपके प्रदेश के वाइस चेयरमैन हैं, शायद चेयरमैन होंगे। उनका भाई इस कबड्डी सिलैक्शन कमेटी का प्रदेश का प्रैजीडैंट है। उसने अपने रिश्तेदार को शामिल करने के लिए इस बेचारी को निकाल दिया। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो खेली नहीं है, नाम लिखा हुआ है, उसको शामिल कर दिया और इस लड़की को निकाल

16.03.2015/1645/SS-AG/2

दिया। यह बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ऐसा खिलवाड़ इन बच्चों के साथ क्यों? मैंने दिया और मुकेश जी उस वक्त मान भी गए थे कि हो जायेगा। यह कॉपी मैं आपको दे दूंगा। मुख्य मंत्री जी, आपके लिए यह कुछ नहीं है लेकिन उस बच्ची के लिए बहुत कुछ है।

मुख्य मंत्रीः पहले तो मैं 50 हजार बातें आपके बारे में कह सकता हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः हम मना थोड़े करते हैं। आप कहते तो हैं। आपने तो यहां हरिपुर में यह कहा कि उसको तो मैं मूर्खश्री की उपाधि दूंगा जिसने जंगल में कॉलेज बना दिया। नाहन में जाकर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास आपने जंगल में कर दिया। जब हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने शहर में किया था तो आपको अच्छा नहीं लगा और नाहन में आप जंगल में करके आ गए । आप खुद करते हैं तो ठीक होता है और जब दूसरा करता है तो गलत होता है। जब हरिपुर में जगह कहीं थी नहीं, आप कहते हैं कि मैं उसको मूर्खश्री की उपाधि दूंगा जिसने यहां पर बिल्डिंग बनाई है। आप क्या भाषा बोलते हैं? मुख्य मंत्री को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आप 6 बार के मुख्य मंत्री हैं। केन्द्र में मंत्री रहे हैं। मेरी उम्र के बराबर आपका राजनीतिक कैरियर है। जब आप ऐसे बोलते हैं तो हमें ग्लानि होती है। अगर शब्दों का अच्छा उच्चारण हो जाए तो हमें भी अच्छा लगता है। हम आपका सम्मान करते हैं। मेरा आपसे निवेदन यही है कि हमने

चर्चा के दौरान आपको सुझाव दिए हैं इन पर विचार करें। बाली जी, आप बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ न करें। एक जो सिस्टम बनाया गया है उसके माध्यम से सारी भर्तियां करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि वे समय-सीमा में बोलें क्योंकि मुझे पार्लियामैंटरी अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा है कि आपसे कोई एग्रीमैंट हुआ है कि साढ़े पांच बजे मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तीन मेम्बर और बोलने वाले हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा टाइम लीजिए। बहुत ज्यादा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र रवि ने अपने भाषण में कहा और उन्होंने कुछ कागज़ दिखाए कि मुख्य मंत्री को ट्रांसफर के बारे में लिखा गया

16.03.2015/1645/SS-AG/3

कि आर0एस0एस0 के हैं और मैंने स्वीकृति दी है। मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि उस पत्र को वे सभापटल पर रखें।

श्री रविन्द्र सिंहः मैं इसको सभापटल पर रख दूंगा।

Chief Ministerः Please lay it. सवाल यह है कि आप कोई कागज़ उठाकर कुछ भी कहते हैं। मेरे पास कई किस्म के पत्र आते हैं मगर हम उस पर कार्रवाई सोच समझकर करते हैं। You put the letter on the Table of the House.

जारी श्रीमती के0एस0

/1650/16.03.2015केएस/एजी/1

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा इस माननीय सदन में हो रही है, मैं भी उसमें शामिल होने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट सत्र है। स्वभाविक रूप से जब तीसरा बजट सत्र हो जाता है, तीसरा महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि सरकार का आधा से ज्यादा

समय यानि कि आधी छुट्टी की घंटी बज चुकी है। दो बजट सत्र बाकी बचते हैं और दो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण बाकी बचते हैं और जहां तक उपलब्धियों का जिक्र जिस रूप में आना चाहिए था हम तलाशते रहे, नहीं मिला। मैं महसूस करता हूं कि लगभग ढाई साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का जो पूरा होने जा रहा है उसमें से बहुत सा समय व्यर्थ की बातों में गुजर गया। जो वक्त असली कामकाज का था, जिस वक्त का इस्तेमाल सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए अपने योगदान के रूप में आगे बढ़ाने के लिए कर सकती थी, अपना ध्यान विकास पर केन्द्रित करके इस प्रदेश के विकास को एक दिशा दे सकती थी, मुझे लगता है कि वह मिसिंग है, गायब है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी बातों में नहीं जाना चाहता। बहुत लम्बा कार्यकाल ऐसी बातों में गुजर गया है और मुझे मालूम नहीं किसको क्या हासिल हुआ लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, पूरे देश के अंदर अगर कहीं ईमानदारी का जिक्र होता है, कहीं बाकी प्रदेशों की तुलना में ईमानदारी अगर ज्यादा है तो हिमाचल का उसमें जिक्र होता है लेकिन

/1650/16.03.2015केएस/एजी/2

उसके बावजूद हम बातें करते-करते यहां तक पहुंच गए। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की जो छवि थी उसको ठेस पहुंची है। अंजाम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम लेकिन यहां पर बहुत वरिष्ठ सदस्य भी बैठें हैं। कई आठ-आठ बार विधान सभा के अंदर है, कई लोग सातवीं बार इस माननीय विधान सभा के अंदर है, छठी और पांचवी बार भी कई माननीय सदस्य यहां पर जीत कर आए हैं और अध्यक्ष महोदय, लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल चौथी बार विधान सभा में आने के बाद हमारा भी पूरा हो रहा है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। इस माननीय सदन में बहुत सारे ऐसे नेता, जब तल्खी होती थी, दोनों तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ बोलते भी थे ,उलझते भी थे। लोकतंत्र है, पक्ष और विपक्ष स्वभाविक रूप से जहां आमने सामने होंगें तो चर्चा भी होगी और तीखी नोंक-झोंक भी होगी लेकिन जो वरिष्ठ सदस्य होते थे, उस वातावरण को ठीक करने के लिए बीच में दखल देते थे, अपनी भूमिका निभाते थे। चाहे हम जय बिहारी लाल खाची जी का जिक्र करें, चाहे ठाकुर राम लाल जी का

जिक्र करें । हमने अपनी आंखों के सामने इन सारी चीजों को देखा है। मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूं कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

16.3.2015/1655/jt/av/1

श्री जय राम ठाकुर--------जारी

मैं इस विधान सभा के अंदर अपने 17-18 साल के कार्यकाल से यह अनुभव करता हूं कि हम कहां थे और कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। यह बात मुझे सचमुच में पीड़ा देती है। मैं आज भी इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि बाकी प्रदेशों की तुलना में अगर ईमानदारी की बात की जाए तो हिमाचल उनसे पीछे नहीं बल्कि हिमाचल उनसे आगे हैं। हम हर बात को इस तरह से एक-दूसरे पर आरोप लगाकर उठाते रहते हैं। चाहे वह बाहर की जनसभा है या विधान सभा के अंदर की बात है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। इस देश के अंदर हिमाचल की छवि खराब न हो, देवभूमि की छवि खराब न हो; यह जिम्मेवारी हम सब लोगों की बनती है। हम सब लोगों को इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं और यहां पर बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात से पीड़ा होती है। शायद पीड़ा तो दूसरे लोगों को भी होती होगी मगर किसी ने यहां जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें सब्र करना चाहिए, संयम रखना चाहिए; चाहे हम इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अच्छा राज्य बने, विकसित राज्य बने और विकास की राह में आगे बढ़कर के यह प्रदेश एक मोडल स्टेट बने। उसमें जो हमारी लोकतंत्र की भूमिका है हमें उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में दोनों पक्षों की तरफ से बातें होंगी लेकिन जो अनावश्यक रूप से बातें होती है उनको रोकने की आवश्यकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि चार्जशीट बनी और हमने उस चार्जशीट पर अमल किया। मगर इस बात को जानने की आवश्यकता है कि क्या उस चार्जशीट को बनाते वक्त उसकी गम्भीरता पर विचार किया गया और क्या उस पर अमल करना लाजिमी है? कई बार इस बात का जिक्र होता है कि यह चार्जशीट हमने नहीं बनाई बल्कि पार्टी

16.3.2015/1655/jt/av/2

के लोगों ने बनाकर दी है। अगर पार्टी के लोगों ने बनाकर दी है तो उसमें यह देखने की जरुरत है कि क्या पार्टी के लोगों ने उस चार्जशीट को तैयार करने में अपनी सही भूमिका निभाई है। यह सही नहीं है कि हर रोज विपक्ष के खिलाफ कुछ-न-कुछ जरूर लिखना है और लिखकर बदनाम करना है। मुझे लगता है कि इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। पिछले दो वर्षों में इस सरकार के कार्यकाल में केवल इसी तरह की बातें उठती रही हैं और यह एक पीड़ा का विषय है। अगर हम विकास की बात करें तो मुझसे पहले मेरे कई साथियों ने यहां जो जिक्र किया है मैं उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। इस बार विंटर सीजन बहुल लम्बा रहा है और इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में देख रहा था कि पहली बार डेढ़-डेढ़ महीने तक बिजली नहीं आई। सेब के 20-20, 25-25 साल पुराने पेड़ टूट कर नष्ट हो गये। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें न केवल अवरुद्ध हुईं बल्कि सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। प्रदेश में बहुत सारी पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन सारी चीजों का जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिए था कि सरकार ने इसके लिए यह प्रयत्न किया और हम इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि अभिभाषण में इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे अपने गांव में बीस दिन के बाद बिजली पहुंच पाई। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब भारी बर्फबारी हुई तो मैंने जिलाधीश, मण्डी को फोन किया कि मैं अपने क्षेत्र में सहयोग करना चाहता हूं। बिजली के जो खम्बे टूटे हैं या सड़कों को जो नुकसान पहुंचा है हम उस बारे में आपके साथ बैठना चाहते हैं। आप एस.डी.एम. साहब को कहिए, बिजली बोर्ड को कहिए, लोक निर्माण विभाग को कहिए, आई.पी.एच. डिपार्टमैंट को कहिए और एक स्थान तय करें जहां मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूं।

बी.जे.नेगी द्वारा जारी

16.3.2015/1700/negi/ag/1

श्री जय राम ठाकुर ..जारी..

आप एस.डी.एम. साहब को कहिए, एक्सइएन, बिजली बोर्ड को कहिए, पी.डब्ल्यु.डी. को कहिए और आई.पी.एच. डिपार्टमैन्ट को कहिये, एक स्थान तय करें, जहां मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, वक्त लग गया और

कहा कि बैठक नहीं कर सकते । हमने कहा, कम से कम चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते हम हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं और अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। फिर मुश्किल से उनके साथ सम्पर्क हो पाया , बातचीत हुई। हमने गांवों के लोगों को अपने घर की रोटी खा करके काम पर निकाले तब जा करके वो बिजली के खम्बे खड़े किए। तब जा करके बिजली की तारें जोड़ करके वहां पर बिजली बहाल करने में अपनी भूमिका निभाई। तब जा करके जो पेयजल योजनाएं 15-20 दिन से बन्द पड़ी थी और लोग बर्फ पिघला करके पानी पी रहे थे उन पेयजल योजनाओं को हमने चालू हालत में लाया। उस परिस्थिति में तो सरकार को बहुत एक्टिव होना चाहिए ,मैं मानता हूं विभाग ने अपनी ओर से काम किया लेकिन उसके बावजूद भी जितनी आवश्यकता थी उतना नहीं कर पाये क्योंकि विभाग की तैयारी नहीं थी । हमने पहली बार देखा कि सीमेन्ट के खम्बे तो टूटे ही टूटे, साथ में जो लोहे के खम्बे थे वे भी टूट गए। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने प्रयत्न किए । लेकिन अभी तक भी जो व्यवस्था की गई है वह अस्थायी व्यवस्था है । उसको आगे मौनसून सीजन आने वाला है उससे पहले ठीक करने की आवश्यकता है । उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे क्षेत्र में लोगों को कहा कि सरकारी क्षेत्र में उतने रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सकता है तो आप लोग पॉली-हाऊसिज़ लगाओ, फ्लोरिकल्चर की ओर जाओ और ऑफ सीजन वैजिटेबल्ज़ पैदा करो। बागवानों ने, किसानों ने लाखों रूपये के लोन ले करके पॉली-हाऊसिज़ लगाए।

16.3.2015/1700/negi/ag/2

लेकिन जब बर्फ गिरी तो सब-कुछ तहस-नहस हो गया, तबाह हो गया। लेकिन उनके आंसू पौंछने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मंडी में ग्रिवैंसिज़ कमेटी की मीटिंग थी उसमें श्री महेन्द्र सिंह जी भी साथ थे और हम दोनों ने इस मामले को राज्स्व विभाग से उठाया और कहा कि जिन्होंने लाखों रूपये का लोन ले रखा है उनका कुछ नही बचा है । ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर चिन्ता करने की आवश्यकता है ।

Speaker: Please try to wind-up.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसके आगे बढ़े तो यहां पर स्कूलों की बात आ रही है । सरकार ने कहा कि 234 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल बना दिया। 225 हाईस्कूलों को प्लस-टू स्कूल बना दिया और 14 महा-विद्यालय खोल दिए । हम आगे दौड़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता भी महसूस होती है । क्या यह सच्चाई नहीं है, जो संस्थान खोले गए हैं ,क्या वहां पर अध्यापक हैं? हम देखते हैं कि बड़े-बड़े नेता हमारे क्षेत्र में जाते हैं और उद्घाटन का फट्टा लगा देते हैं और उद्घाटन करने के बाद जब नोटिफिकेशन होती है तो पद तो सृजित करते है। काग़जों में पद सृजित करना एक बात है लेकिन मौके पर कर्मचारी होना, अधिकारी होना और अध्यापक होना दूसरी बात है। लेकिन नहीं है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सचमुच में हमको यह पीड़ा देता है । लेकिन जहां तक स्कूल खोलने की बात है, हम इस बात को मानते हैं कि जहां आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोलिए। लेकिन इतना भी अंधाधुंध मत खोलिए कि वहां पर टीचर भेजने में कठिनाई हो। अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अगर हम हेल्थ डिपार्टमैन्ट की बात करें तो अभी यहां पर मंत्री जी नहीं बैठे हैं। 7 नए सिविल हॉस्पिटल, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में, गौहर में 30 बेडिड हॉस्पिटल पहले से एग्ज़िस्ट करता था और उसकी बिल्डिंग वहां

16.3.2015/1700/negi/ag/3

पर बनी हुई थी वहां पर घोषणा कर दी गई कि इसको सिविल हॉस्पिटल बना दिया गया है। लेकिन एक साल का कार्यकाल बीत गया है और एक साल के कार्यकाल के बावजूद अभी भी हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर की स्ट्रैंथ वहां पर मौजूद होती थी उससे भी संख्या कम हो करके वहां पर केवल 2 या 3 डॉक्टर बैठ रहे हैं। सरकार में रहते हुए आपको अधिकार है कि आप संस्थान खोल सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर सुनिश्चित करें कि जो संस्थान आप खोल रहे हैं वहां पर...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

16/03.2015.1705/यूके/एजी/1

श्री- जय राम ठाकुर--जारी----

वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रबन्ध करें । यदि कहीं स्कूल या कॉलेज खोलते हैं तो वहां मास्टर का इन्तजाम करें, जहां हास्पिटल खोलते हैं वहां पर कम से कम डाक्टर, स्टाफ नर्स आदि का भी इन्तजाम करें । इस बात को सुनिश्चित करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक PHC बागा-चलोगी में खोली, PHC तो खोल

दी और वहां पर नोटिफिकेशन की कॉपी भी साथ में लगी कि यहां के लिए डॉक्टर और स्टॉफ नर्स का पद भी सृजित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक वहां पर एक भी कर्मचारी नहीं है। एक और PHC गोहड़ानाल खोल दी और वहां पर उद्घाटन कर दिया गया। मुख्य मंत्री जी, आप वहां पर आएं उद्घाटन करें, आपका स्वागत है। लेकिन आपके नाम पर दूसरे लोग उद्घाटन का फट्टा लगाते हैं और कहते हैं कि मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से और आगे अपना नाम छापते हैं और लिखते हैं कि उनके सहयोग से इस PHC का उद्घाटन किया गया। बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है। हमने आज तक ऐसा देखा नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो एक-एक नहीं सेवा में दो-दो रखे हुए हैं, उनकी उद्घाटन की होड़ लगी रहती है। चाहे वह स्कूल का ऐनुअल फंक्शन है, वहां इस बात की होड़ लगी रहती है कि एक को बुला लिया तो दूसरे को भी बुलाएं। कर्मचारी इस बात के लिए परेशान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय परिस्थिति यहां तक आ गई है कि वहां दोनों तो उद्घाटन करें, स्कूल के फंक्शन मे जाएं लेकिन उसके साथ-साथ कांग्रेस के पदाधिकारी तक टूर्नामैंट की ओपनिंग और क्लोज़िंग कर रहे हैं। ऐनुअल फंक्शन में प्रिज़ाईड ओवर कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन सारी बातों पर गौर करेंगे।

मंडी का ESI मेडिकल कॉलेज, उद्घाटन कर दिया। लेकिन सचमुच में उसका होगा क्या ? न सरकार जान पा रही है न लोग जान पा रहे हैं। दिल्ली में इन सारी बातों को लेकर के जब हमने मालूम किया कि ESI मेडिकल कॉलेज की हमने कोई बात कही है, हमने कहा कि यह कॉलेज तो खोला लेकिन उसका संचालन

16/03.2015.1705/यूके/एजी/2

कैसे होगा ? तो कहा कि पिछली सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की, आनन-फानन में यह सारा कुछ किया गया और जाते-जाते किया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच में चिंता का विषय है।

एक विषय और है, आऊटसोर्सिंग का। ऐसी परिस्थिति हो गयी है, सभी विभाग में ,पूरी सरकार सारी चीजों को लेकर आऊटसोर्सिंग करने में लगी है। वह भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। उससे एक पारदर्शिता इसमें नहीं होने वाली है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी, आप हरेक बात को टच करेंगे, हरेक चीज को हाई लाईट करेंगे यहां पर तो it will take hours together. आप सीधी स्पीच बोलिए।
श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कम वक्त मांगा है। हमने अपने सदस्यों के नम्बर कम कर दिए हैं।

अध्यक्षः आप 20 मिनट बोल चुके हैं, अब वाईंड अप कीजिए।

श्री जय राम ठाकुरः सर, मैं वाईंड अप करने की कोशिश करता हूं। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को यदि हम देखें। तो मुझे लगता है कि इस बात पर चिंता स्वाभाविक रूप से है। मेरे चुनाव क्षेत्र की अनुसूचित जाति की दो बहनें रास्ते से जा रहीं थीं। रास्ते में उन दोनों बहनों को चाकू से गोद दिया। उनमें से एक जोनल अस्पाताल मंडी से शिमला रैफर की गयी लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उसके बाद दूसरी घायल अवस्था में रही और उपचार प्राप्त करने के बाद वह बच पायी है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। इसी

16/03.2015.1705/यूके/एजी/3

प्रकार से दूसरी घटना वहां पर हुई है, बाड़ी चौकी में। एक बच्ची घर से जा कर गायब होती है। उसके बाद जब छानबीन की जाती है और वह नहीं मिल पाती है उसके बाद तब तक के लिए जिस लड़के ने उस लड़की की हत्या की थी, उसने आत्म-समर्पण नहीं किया तब तक पता नहीं चला। जब उसने आत्म-समर्पण किया तब जा कर मालूम हुआ कि उसकी हत्या हो गयी थी। उसकी डैड बॉडी एक खाई में से निकाली गयी। दोनों ही अनुसूचित जाति की लड़की थी। यह बहुत ही पीड़ादायक घटनाएं थी। मैं चाहूंगा ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के आगे आने वाले समय में सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना न हो। इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर वन मंत्री जी बैठे हैं। बाप बहुत जिक्र करते हैं टी0डी0 राईट्स का।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1710/sls-ag-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

हम भी इस बात के लिए लड़ते रहे कि टी० डी० राईट मिलना चाहिए। मिला, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के लोग 20-20 ऐप्लिकेशंज का पुलिंदा अपने बैग में डालकर यहां डी० एफ० ओ० से कह रहे हैं कि यह कर दीजिए। उनसे करवाया जा रहा है। एक पेड़ सैंक्शन हो रहा है, तीन पेड़ और काटे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो जैनुअन आदमी है, जिसका घर जल गया है ,उसको टी० डी० नहीं मिल पा रही है। जिसका घर बाढ़ में बह गया है, उसको टी० डी० नहीं मिल रही है। टी० डी० केवल चुनिंदा लोगों को मिल रही है। गोहर के डिवीजन से मालूम करें तो उसमें 90% लोग प्रभावशाली लोग हैं ,एक दल से संबंधित हैं। वहां जाकर टी० डी० निकाल रहे हैं। फिर आप पता भी करें कि उन्होंने उस टी० डी० का इस्तेमाल किस प्रकार से किया। जो टी० डी० का पेड़ काटा गया है, वह इस्तेमाल हुआ भी या वह कहां गया? अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच चिंता का विषय है। टी० डी० का उपयोग किसी गरीब के घर को बनाने के लिए हो ,किसी का घर जल गया हो या बाढ़ में बह गया हो, उसके लिए मदद हो। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। अब आपके ही सदस्यों का समय कटता जा रहा है। मैं उनको समय में रियायत नहीं दूंगा। You have spoken for thirteen minutes.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरी थोड़ी-सी बात सुन लें। बहुत दिनों के बाद अच्छे माहौल में चर्चा चली हुई है।

Speaker: But if you want to speak on each and every incident. चर्चा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार बोलना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। दूसरे लोग भी अपनी बात रखेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपने विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें बनाईं। अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में

16.03.2015/1710/sls-ag-2

हमने अपने विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगभग 200 किलोमीटर सड़कें बनाईं। 25-25 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन करने के बाद बसें भी चलाईं। आज 10 से ज्यादा रूट ऐसे हैं जो ससपैंड किए हुए हैं, बंद पड़े हैं। पहले वहां बसें चलती थीं लेकिन आज वह सारे-के-सारे बंद पड़े हैं। इन सारी बातों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे स्कूलों का वहां पर शिलान्यास किया था। बजट प्रावधान करने के बावजूद, चाहे बाली चौकी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है चाहे थाटा घनियार का है , चाहे घाट का है चाहे गाड़ा-गुसैणी का है; बजट प्रावधान किया, AA&FS दी और उसके साथ-साथ शिलान्यास किया। लेकिन दो साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद, अध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उलटे हमने जहां-जहां शिलान्यास किए थे ,वहां पर जो फाऊंडेशन स्टोन लगे थे, वह पत्थर तोड़ने का काम बड़े जोरों पर चला है। ठाकुर गुलाब सिंह यह पर बैठे हैं। थाची में हमने पी० डब्ल्यू० डी० के एक इंस्पैक्शन हट का शिलान्यास किया। वहां पर उस पत्थर के टुकड़े-टुकड़े करके ज़मीन पर फैंक कर रखा हुआ है। इसी प्रकार से मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बौड़ीधार की आई० पी० एच० की स्कीम है, वहां पर हमने शिलान्यास करने के बाद उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन का पत्थर तोड़ कर वहां पर रखा हुआ है। एक फुड़ागी बृज का हमने शिलान्यास किया। बजट प्रावधान करने के बावजूद उस पुल के शिलान्यास का पत्थर तोड़ कर रख दिया गया है। एक सोमघाट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए बजट का प्रावधान किया, शिलान्यास किया, लेकिन पत्थर तोड़कर रखा गया है। मुझे लगता है कि इस बारे में आपको फील्ड में इंस्ट्रक्शन्ज देनी चाहिए कि यह एक अच्छी परंपरा नहीं है ,इस परंपरा को रोकने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत हैं लेकिन अब मुझे केवल इतनी बात कहनी है कि महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है ,महामहिम राज्यपाल के प्रति हमारा बहुत आदर है ,लेकिन हम अभिभाषण में ऐसी

16.03.2015/1710/sls-ag-3

कोई पुख्ता बात नहीं ढूंढ़ पाए जिसका समर्थन किया जा सके, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

धन्यवाद।

अध्यक्ष : विपक्ष की ओर से दो और सदस्य बोलने वाले हैं। यदि सदन की इज़ाज़त हो तो क्या माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा का जवाब अभी दे सकते हैं।...(व्यवधान)... यह आपने ही पहले डिसाईड किया हुआ है कि साढ़े पांच बजे माननीय मुख्य मंत्री जवाब दे देंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और हमारे सचेतक श्री रिखी राम कौंडल जी के मध्य बात हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कल जवाब देना था लेकिन ..

जारी ..गर्ग जी

16/03/2015/1715/RG/JT/1

श्री रविन्द्र सिंह----------क्रमागत

और जो हमारे सचेतक हैं श्री रिखी राम कौंडल जी, इनके मध्य बात हुई थी। वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब कल देना था ,लेकिन जैसा श्री मुकेश अग्निहोत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमें कहा कि कोई सामाजिक कार्यक्रम होने के कारण ऐसा मुश्किल है, तो हम उनसे सहमत हो गए और हमने अपने वक्ताओं में कटौती कर दी। आज हमारे पांच वक्ता बोलेंगे ,अभी तीन बोले हैं। अभी समय है और सात बजे तक सत्र चलना है। इसलिए जो बचे हैं उनको बोलने दें।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आपसे कोई बात हुई है कि 5.30 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें। अब यह तो आपने निर्णय लेना है, मैंने निर्णय नहीं लेना।

श्री रविन्द्र सिंह : ठीक है, बोलने वालों को 4-5 मिनट लगने हैं। आप उनको बुलवाइए।

अध्यक्ष : क्या निर्णय लिया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सहमति तो श्री रविन्द्र सिंह जी को मालूम है कि 5.30 बजे की हुई थी। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को भी रामपुर जाना है इसलिए हमने आपसे आग्रह किया था। अभी 15 मिनट का समय है।

अध्यक्ष : अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब देना है।

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय मुख्य मंत्री जी 5.30 बजे उत्तर देंगे। चलिए, 5.30 बजे के बजाय माननीय मुख्य मंत्री जी 5.45 बजे उत्तर दे देंगे।

अध्यक्ष : अब श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखिए और 10 मिनट बोलिए ,तभी अच्छा रहेगा। जो भी आप बोलना चाहते हैं, संक्षेप में बोलिए।

16/03/2015/1715/RG/JT/2

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, 11मार्च, 2015 को इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। सरकार ने इस अभिभाषण के माध्यम से भरपूर प्रयास किया कि गत् दो वर्षों की सफलता की कहानी वह इस पुस्तिका में छापे ,लेकिन यह लगता है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण की पुस्तिका को पढ़ा जिसमें 39 पृष्ठ और 128 पैराग्राफ हैं, तो पढ़कर उनको भी यह लगा कि पहला पैराग्राफ और आखिर की दो पंक्तियां केवल मात्र काम की हैं बाकी सबका-सब पढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी जो हर दृष्टि से स्वस्थ्य हैं ,बढ़ियां हैं ,सबको अच्छी लीडरशिप दे रहे हैं ,उन्होंने जो यहां सदन को संबोधित किया' कि बाकी पढ़ा हुआ समझा जाए।' क्योंकि लगता है कि अभिभाषण दो साल की कांग्रेस सरकार की नाकामियों और असफलताओं का पुलिन्दा है।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह कही गई कि हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज़ बनाया और यह कहा कि अधिकांश वायदों को पूरा करने का प्रयास किया ,लेकिन जब इस माननीय सदन में विपक्ष के नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने तथ्यों के आधार पर यह बता दिया कि यह नाकामियों का पुलिन्दा है ,तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि यह केवल मात्र अब का नहीं है,

इसको पूरे पांच सालों में पूरा करना था यानि इन्होंने स्वीकार किया कि अभी तक भी इसमें कुछ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। इस साल वर्षा व हिमपात के कारण प्रदेश में जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है ,तो कुल्लू जिले के मनाली विधान सभा क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान हुआ है और इतनी बर्फबारी के कारण अभी तक डेढ़-दो महीने बीतने के पश्चात भी बिजली की सप्लाई ठीक प्रकार से बहाल नहीं हो पाई है ,पीने-के-पानी की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं हो पाई है ,सड़कों का अत्यधिक नुकसान हुआ है और अभी एक बात यहां कही जा रही थी कि वर्ष 2012 में प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने एक योजना को अमलीजामा पहनाने के आदेश दिए थे। वह यह था कि मनाली और कुल्लू के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान स्थाई रूप से करने के लिए----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

16/3/2015/1720/MS/AG/1

गोविन्द सिंह ठाकुर जारी---------

वह यह था कि मनाली और कुल्लू के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान स्थायी रूप से करने के लिए जो मनाली के डिवीजन को बिजली बजौरा के सब-स्टेशन से जाती है, उसको प्रीणी अलाइन दुहांगन के पावर हाउस से प्रीणी बिजली बोर्ड के सब-स्टेशन से जोड़ा जाए। तत्पश्चात उसके टैण्डर भी हुए थे और वर्ष 2013 के विंटर कार्निवाल में मुख्य मंत्री जी आप पधारे और आपसे वहां पर एक घोषणा भी करवाई गई। अलाइन दुहांगन परियोजना के पावर हाउस से बिजली बोर्ड के सब-स्टेशन को जोड़ा जाएगा ताकि बिजली सीधी नालागढ़ न जाकर के पहले हमें मिलेगी, जिससे आने वाले कई सालों की बिजली की व्यवस्था मनाली और कुल्लू की पूरी होगी। मुख्य मंत्री जी अभी दो बार आपसे घोषणा करवाई गई है लेकिन अभी तक भी ट्रांसमिशन कारपोरेशन ने, बिजली बोर्ड ने, अलाइन दुहांगन परियोजना ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की है। मैं तो सीधा-सीधा इस मामले में सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आखिरकार क्या ऐसे कारण हैं कि जब मुख्य मंत्री घोषणा करते हैं तो उसको अमलीजामा पहनाने के लिए अभी तक भी विभाग निष्क्रिए बैठे हैं? उसके साथ जो फोजल में एक 100 मैगावाट बिजली के सब-स्टेशन का फाउंडेशन धूमल जी ने किया था, वह अभी तक तैयार नहीं हो पाया, वह तैयार होना चाहिए। फिर यह भी कहा था कि उसको नग्गर के सब-स्टेशन से और वहां ए.डी. हाइड्रो की

ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अभी तक आपका वह भी फाइनल नहीं हो पाया है। क्योंकि ए.डी. हाइड्रो बिजली बोर्ड से मुंहमांगी कीमत वसूल रहा है और जो जैनुअन है वह उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो मुंहमांगा वसूल रहा है, अधिकारी इन बातो पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं?

इस बार हर क्षेत्र में अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रयास किए कि बर्फबारी के दौरान लोगों को सुविधा मिले। लेकिन उसके बावजूद लाइनमैन वहां पर नहीं, बिजली के फीटर वहां नहीं, सड़कों को ठीक करने के लिए लेबर नहीं और मूलभूत ढांचा भी नहीं है। मैंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी एक बात कही थी कि

16/3/2015/1720/MS/AG/2

सारे क्षेत्र के लिए कम-से-कम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास चार पहिया वाहनों की सुविधा होनी चाहिए। उस सारे क्षेत्र के अन्दर अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, अगर चाहते हैं कि पर्यटक वहां से न भागे तो वहां पर अपने प्रशासन के पास कोई अच्छा स्नो कटर होना चाहिए और उस स्नो कटर की बात भी हम करते आए हैं। अगर स्नो कटर होगा तो पर्यटकों को रातों-रात यहां से नहीं भागना पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी, इसी राज्यपाल अभिभाषण के पैरा 82 में एक बात लिखी है कि विगत वर्ष में हिमाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक में इतना बड़ा झूठ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज वर्तमान में पूरे प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री जी यह निश्चित है और आप भी जानते हैं कि जब आप सुबह समाचार पत्र उठाते हैं तो हर समाचार पत्र की सुर्खियों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रदेश के अन्दर चोरियां, डकैतियां, नशाखोरी और बलात्कार की इस प्रकार की कितनी घटनाएं हो रही हैं? कानून और व्यवस्था के बारे में आपने कहा कि हिमाचल में हमने महिलाओं की स्थिति के लिए तीन पुलिस थाने भी बना दिए हैं। लेकिन पिछले कल के समाचार पत्र में इस बारे में बहुत बड़ी स्टोरी लगी है। बाकी जगह के महिला थानों की बात तो क्या करे, जो शिमला का महिला पुलिस थाना है, उनके पास अभी तक भी आने-जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। यानी

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यह हाल है तो बाकी प्रदेश में क्या स्थिति हो सकती है ?लगता है कि कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस कुछ और कामों में व्यस्त है। पिछली साल रोहतांग जाने के लिए भुंतर-मनाली और कुल्लू के 4000 टैक्सी ऑपरेटर्ज को रोका गया। स्नो स्कूटर वालों की गतिविधियों को रोका गया।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

16.3.2015/1725/जेके/एजी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः------जारी--------

स्नो-स्कूटर वालों की गतिविधियों को रोकना। पैरा ग्लाईडर वालों को रोकना। जब सारी गतिविधियां रोकी गई तो जनता के पास तरीका क्या था? जब आपका प्रशासन सुनता नहीं है। लोग रोज़ डेलिगेशन लेकर जाते हैं। वहां पर कोई सुनता नहीं था। दो दिनों में 5-4 हजार लोगों ने आंदोलन किया। जब आंदोलन दूसरे दिन तक चला तब 5हजार लोग सड़क पर बैठे। आपके प्रशासन ने गिड़गिड़ा कर कहा कि वी.वी.आई.पी. मूवमैंट है। यह रास्ता खुलना चाहिए और मुझसे निवेदन किया और उनके आग्रह पर मैं सड़क पर स्वयं गया कि सरकार व अधिकारियों पर मार न पड़े, सरकार को परेशानी न हो इसलिए जनता के बीच में जा करके सारी बात अपने ऊपर ले करके रास्ते खुलवाए और सारे का सारा सीजन भी स्मूथ चलाया। लेकिन जब तक तो फंसे रहे तब तक तो पीछे पड़ते रहे लेकिन जब काम निकल गया तो 6 महीने के बाद हमको क्या ईनाम मिला? आपके अधिकारी धन्यवाद करते थकते नहीं थे। एम.एल.ए. साहब आपने बचा दिया वरना काम से गये थे । उसके बाद क्या मिला? 6 महीने के बाद एम.एल.ए. के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई। इन सब बातों को मैंने पहले भी आपके ध्यान में लाया है। 2 जनवरी को आप मनाली विंटर कार्निवाल के लिए आने वाले थे। 31 दिसम्बर से पहले 10-12 दिन आपके अधिकारियों ने तथा पुलिस प्रशासन ने सारी फोर्स वहां पर लगा करके लोगों के सारे इलिगल खोखे और ढाबे ऊखाड़ डाले। गरीब को तो मार मारी लेकिन जो बड़ी कोठी वाले थे वे आज भी यथावत खड़े हैं। यह दोहरा कानून कैसे चलेगा? सोलग नाले में तरपाल वाले, चाय वाले को ऊखाड़ा गया। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी चार-चार मंजिलों के स्लैब खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी यह दोहरा कानून कैसे चलेगा?

इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीपकमल पर यूथ कांग्रेस के कार्यकत्ताओं द्वारा प्रदर्शन करना ये कहां की परम्परा रही है? प्रदर्शन कहीं दूसरी जगह जा करके करते। जब किसी पार्टी के कार्यालय के बाहर

16.3.2015/1725/जेके/एजी/2

जा करके किसी को चुनौती देना उसके लिए यूथ कांग्रेस और यूथ प्रदेश अध्यक्ष दोषी है। हमने यह पहले भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। सी.बी.आई. से जांच हो। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपके सामने एक बात और लाना चाहूंगा। मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं आप कुल्लू आए और मैं उस वक्त out of station था। आपने एक बात कही कि हमने माता भीमाकाली के मंदिर का भी ट्रस्ट बनाया। आपकी स्टेटमैंट आई कि रघुनाथ मन्दिर का भी ट्रस्ट बनना चाहिए। हम इस अच्छी बात का अभिनंदन करना चाहते हैं। वह चाहे निजी है या सरकारी है सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है। अगर यह लगता है कि जनहित में जन-भावनाओं के लिए ट्रस्ट बनाना अनिवार्य है तो निश्चित रूप से आप इस ट्रस्ट को बनाएं। विपक्ष के नाते भी और जन-भावना के नाते भी हम आपका साथ देंगे।

इसी के साथ यहां पर शिक्षा विभाग की बात की गई है। आज ही एक समाचार-पत्र के अन्दर यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर शिक्षा के अधिनियम की बड़ी अवहेलना हो रही है। शिक्षा के अधिनियम में कहा गया है कि हर प्राईमरी स्कूल में लगभग दो अध्यापक होने चाहिए। मिडल स्कूल में अध्यापक होने चाहिए। जो कि इस क्राईटेरिया पर कहीं भी टिक नहीं पा रहा है । हम स्कूल तो धड़ाधड़ खोलते जा रहे हैं लेकिन जो स्कूल पीछे चल रहे हैं उन सबका मूलभूत ढांचा यह है कि वहां पर न प्ले ग्राऊंड है, न वहां पर टीचर्ज हैं, न वहां पर शौचालय है। उनको सुविधाएं देने के लिए हमारा ध्यान नहीं है। आनन-फानन में प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर संस्थान को 90:10 के अनुपात में पैसा प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का ढांचा बिगाड़ करके रख दिया है। उसके लिए पहले मूलभूत ढांचे की तैयारी करनी चाहिए थी। मुख्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के सब छात्र संगठन इस रूसा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस पर पुनिर्विचार करें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

16.03.2015/1730/SS-JT/1

श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुर क्रमागतः

ताकि यहां के छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात और है।

Speaker: Please wind up.

श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। अभी पिछले मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को कुल्लू के जोनल होस्पिटल के अंदर तीन लोगों ने जा करके वहां पर जो सबसे अच्छे फिजीशियन, डॉ0 कल्याण ठाकुर हैं, से हाथापाई की। खून से लथपथ लोग गए, उन्होंने शराब पी रखी थी और डॉक्टर से हाथापाई की। मेडिकल हैल्थ ऑफिसर को दौड़ करके पुलिस को इंफोर्म करके अपनी जान बचानी पड़ी। ठीक एक दिन के बाद, फिर से 6 लोग शराब पी करके गए। दो ऑर्थोपिडिसन, डॉ0 संजय और डॉ0 लोकेश की पिटाई की। उनको भाग करके पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जान बचानी पड़ी तो यह क्या कानून-व्यवस्था की स्थिति है? क्या यह शांतिप्रिय है? मैं कहता हूं कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। इस घटना के पीछे एक और बात ध्यान में लाने वाली है कि लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की पिटाई करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जांच करें कि ये कौन लोग हैं। कहीं इसके पीछे प्राइवेट होस्पिटल के लोगों का हाथ तो नहीं है कि अच्छे लोग आ गए हैं उनकी पिटाई करो। तुम कहीं नौकरी छोड़कर चले जाओ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज कुल्लू अस्पताल की ऐसी स्थिति है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारी ट्रांसफर करवाओ या हम नौकरी छोड़ देंगे। यह जांच बिठाना और गहराई से करना ज़रूरी है।

एक और विषय आपके ध्यान में लाता हूं। आज अखबारों की सुर्खियों में कहा है सैंच से ले करके सैंच आऊट के बीच की लारजी की सड़क है। वहां पर अवैध खनन हो रहा है। श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। मैं पढ़ रहा था तो एक पैराग्राफ आपका भी है। वैध खनन और ठीक प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से खनन हो, उसके लिए कोई खनन नीति बनाई है। लेकिन आपको जांच करनी चाहिए। अखबारों की सुर्खियां हैं। कुल्लू-मंडी की अखबारें भरी हैं। लगभग पिछले 5-6 दिन से 100-100, 150 टिप्पर तलाड़ा और भलान गांव के पास लगे हैं। गांव के लोगों ने शिकायत की है कि रात-दिन हमको सोने नहीं देते। अब जब यह नाला हट जायेगा तो बाढ़ का

16.03.2015/1730/SS-JT/2

खतरा है। वह जमीन क्या थी? एन0एच0पी0सी0 ने वह भूमि एक्वायर की थी। एन0एच0पी0सी0 की डम्पिंग साइटें थीं। वहां पर हज़ारों मीट्रिक टन डम्प किया है और एन0एच0पी0सी0 ने वन विभाग को वापिस किया है। माननीय मंत्री जी, वन विभाग की जमीन है और उस डम्पिंग साइट से 100-100150 , टिप्पर जा रहे हैं। आप अखबारें मंगवा सकते हैं। इतने टिप्पर लगे हैं। इसके अंदर कौन दोषी है? इसमें एन0एच0पी0सी0 के जी0एम0 ने कहा है कि हमने अपनी डम्पिंग साइटें वन विभाग को वापिस कीं, हम उठाने की परमिशन दे नहीं सकते। वन विभाग के अरण्यपाल ने कहा कि वन विभाग की जमीन से कोई उठा नहीं सकता लेकिन उस सबके बावजूद उठा रहे हैं। ऐसे प्रभावशाली कौन लोग हैं? माननीय वन मंत्री जी, मैंने आपको कहा था ,जब थलोट में हादसा हुआ तो आपने रीवर राफ्टिंग मनाली तक बंद करवा दी। आपने वन विहार में रीवर क्रॉसिंग करने वाले नौजवान, रीवर राफ्टिंग करने वाले छोटे-छोटे चाय बेचने वाले सब बंद करवा दिए। आड़ क्या ली कि थलोट का हादसा हुआ और बंद कर दिया कुल्लू से मनाली तक। छोटे-छोटे लोगों को बंद किया। लेकिन ये 10 150 ,100-0टिप्पर किसके चले हैं? इसकी जांच करके इस माननीय सदन में नाम बताने चाहिएं कि वे कौन लोग हैं। भुन्तर, जिआ, पतलीकूहल, वासिंग, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग बेलचा लेकर जाते हैं, जो फरूआ लेकर जाते हैं और दिन-रात एक करके एक रेत का ट्रेक्टर भरते हैं पुलिस वाला खड़े होकर उनसे पांच हजार रुपये जुर्माना लेता है। छोटे-छोटे को डरा करके बंद कर दिया। इन बड़े लोगों के पीछे कौन है यह जांच करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, और अधिक न कहता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक कुल्लू अस्पताल में सबसे आवश्यक जो चीज़ है, स्वास्थ्य मंत्री जी, एनस्थीसिया स्पैशलिस्ट अभी भी नहीं है। गत दशहरा में आपने उसको 300 बैडिड अस्पताल की घोषणा की है..

जारी श्रीमती के0एस0

/1735/16.03.2015केएस/एजी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी---

गत दशहरा में आपने उसको 300 बैडिड अस्पताल की घोषणा की है। अभी तक एक साल बीतने को है उसकी न नोटिफिकेशन हुई है, न 300 बैडिड के मुताबिक स्टाफ

स्ट्रैंथ वहां पर बढ़ी है। मनाली के अस्पताल के बारे में मेरा यहां पर एक प्रश्न भी था। वहां पर 6 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है। वह 50 बैड वाला अस्पताल है। वहां पर केवल मात्र तीन डॉक्टर हैं लेकिन वहां पर आपका एक डॉक्टर है उसको पता नहीं किसकी शरण है। हर कभी दो-दो, तीन-तीन महीने की छुट्टी पर जाते हैं। दो डॉक्टर कब-कब डियूटी देंगें?

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आज मेरा इस माननीय सदन में एक प्रश्न था। मैंने कहा था कि मनाली के पतली-कूहल के पास ग्राम पंचायत कटरांई में श्रीकोट आई.टी.आई. के लिए भूमि मंजूर हुई है। वह आई.टी.आई. किराये के मकान में चल रही है लेकिन सरकार का जवाब है कि वहां पर कोई आई.टी.आई. स्वीकृत नहीं है और लिखा है कि निजी भवन में चलाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैंने पूछा था कि क्या उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनेगा कहते हैं कि प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। जबकि कटरांई में आई.टी.आई. प्राईवेट बिल्डिंग में चल रही है और होर्टिकल्चर की 20 बीघा में से 5 बीघा जमीन टैक्निकल ऐजुकेशन के नाम हो चुकी है। दो ट्रेड वहां पर चल रहे हैं यानि इससे ज्यादा नालायकी क्या हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज इस अभिभाषण के माध्यम से कुछ बातों को लाने का यहां पर प्रयास किया। यह जो अभिभाषण है, यह कुल

/1735/16.03.2015केएस/एजी/2

मिलाकर सरकार की गत दो वर्षों की असफलता का पुलिंदा है और इसीलिए इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि जो वास्तविकता है, तथ्य हैं, वे इस पुस्तक में आने चाहिए थे जो कि नहीं आए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

/1735/16.03.2015केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगें। माननीय सदस्य, आपके पास 10 मिनट का समय है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर :माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने पढ़ा । वर्तमान सरकार की पिछले दो वर्ष की जो कारगुजारी रही इसमें मुझे प्रैक्टिकल एप्रोच की बहुत कमी लगी। सरकार के पास न कोई दिशा है और न कोई ऐसी सोच है जिसे यह सरकार प्रदेश के विकास के मामले में आगे ले जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार समय निकालने के लिए, पांच साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, यह सरकार घसीट रही है। यही वजह है कि चाहे ऐजुकेशन है, हैल्थ है, क्रप्शन का मामला है, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुऐशन है, चाहे एग्रीकल्चर है हर फील्ड में सरकार टोटली फेल हो रही है । हर चर्चा के ऊपर यहां पर बड़े जोर-शोर से विषय रखे गए लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर सरकार की लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में बोलना चाहूंगा। यह ठीक है कि क्राईम रुकता नहीं है। क्रिमिनल को आप क्राईम करने से नहीं रोक सकते। क्रिमिनल कब कौन सा क्राईम कर जाए यह किसी को पता नहीं होता लेकिन सरकार की फेलियर कब आती है, जब अफैक्टिड पार्टी को न्याय नहीं मिलता है और क्राईम करने वाला पकड़ा नहीं जाता है या उसको प्रॉपर सजा नहीं मिलती । दो ऐसे इंसिडैंट्स हैं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2015/1740/ag/av/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर--------जारी

जिन्होंने क्राइम किया है उसको उसकी सजा नहीं मिलती। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा मगर प्रदेश में हाल ही में हुए दो इनसिडैंट्स का जिक्र करना चाहूंगा। मैं यह कहूंगा कि प्रदेश में सरकार की लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजिशन चकनाचूर हो चुकी है। हाल ही में पिछले हफ्ते चौपाल में एक इनसिडैंट हुआ। इस इनसिडैंट को बड़ा लाइटली लिया जा रहा है। मैरिज में गोली चली और एक आदमी मर गया। माना, क्राइम करने वाले ने क्राइम कर दिया मगर सरकार का यह फर्ज है कि उस क्रिमिनल को पकड़े और उसको प्रोपर सजा दें। उसके बारे में प्रोपर इनवैस्टिगेशन हो। मगर हुआ क्या, पुलिस वहां जाकर एफ.आई.आर. दर्ज कर रही हैं। वहां मौके पर उस गांव में बैठी है। क्रिमिनल अपने घर में बैठा हुआ है और जिसका मर्डर हुआ उसके सम्बंधी गये और जाकर उसके घर में मर्डर कर दिया। मैं पेपर में छपी खबर के मुताबिक बोल रहा हूं और यह शेमफुल बात है। लॉ एण्ड ऑर्डर पब्लिक अपने

हाथ में ले लें ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल होती है। यह कोई छोटा-मोटा इनसिडैंट नहीं है। किसी को सजा देना सरकार और कोर्ट का काम है। लेकिन खुद जाकर उसका मर्डर कर दें जिसने क्राइम किया है इससे बड़ी सरकार की कोई फैल्योर नहीं हो सकती। जैसे कि पेपर में खबरें आई हैं कि उस क्राइम के तहत तीन गोरखों को पकड़ा गया है। पेपर में यह भी लिखा है कि उन गोरखों को क्यों पकड़ा गया है यह भी पता नहीं है। यह सरकार के लिए बड़ी शेमफुल बात है कि जिसने क्राइम किया उसका भी मर्डर हो गया। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा उदाहरण हाल ही में भारतीय जनता पार्टी कें ऑफिस पर हुए अटैक के बारे में देना चाहूंगा। बड़ी शर्म महसूस हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि बाहर जो लोग थे उन्होंने रिटेलिएट किया। अरे, जब मेरी पर्सनल लाइफ या प्रोपर्टी को खतरा होगा तो इतना राइट ऑफ डिफैंस तो हमें संविधान ने भी दिया है कि हम रिटेलिएट करें। क्या हम उनको रोकेंगे नहीं जब वे हमारे घर के ऊपर आ रहे हैं? हम सबके बच्चे बराबर ही हैं और हम नहीं चाहते कि किसी का करियर खराब हो जाए। लेकिन जब आप प्रोसैशन लेकर जाते हैं तो नाम तो यूथ कांग्रेस का

16.3.2015/1740/ag/av/2

है। उस प्रोसैशन में यूथ कांग्रेस के नेता कम और गुंडे ज्यादा थे। गुंडों ने जो अपना रोल प्ले करना है उसकी गाज प्रोसैशन को लीड करने वाले पर पड़ती है। यह कह देना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब एक की आंख गई है, बाजू टूटे हैं, वहां हमारे पार्टी ऑफिस के दरवाजे और गेट टूटा है। बाद में यह कह देना कि उन्होंने खुद ही तोड़ दिया, खुद ही टांगे तुड़वाई है। यह कहां की इनवैस्टिगेशन है? हम क्या चाहते हैं कि जिन्होंने ऑफैंस किया है whosoever may be, उसकी प्रोपर इनक्वायरी हो, उन्होंने अटैंम्प ऑफ मर्डर ,जो हमारे यहां अटैक किया है, आंख चली गई है उसकी पर्मानैंट डिसफिगरेशन हो गई है। 307 अटैंम्ट ऑफ मर्डर बनता है, 326 बनता है। उस घटना को घटे एक महीना हो गया है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी प्रोपर इनवैस्टिगेशन हो। कोर्ट में फैसला हो जायेगा। जिन्होंने क्राइम किया है वह भुगतेगा और जिन्होंने क्राइम नहीं किया वह कोर्ट से छूट जायेगा। ये दोनों इनसिडैंट एक महीने के अंदर-अंदर हुए हैं जिससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर मेंटेन करने में पूर्णतया फेल है। हम यह नहीं कहते कि क्राइम नहीं होते। क्राइम होते हैं। हम जब सुबह टी.वी. देखते हैं तो 100 न्यूज लगातार आती हैं जिसमें से 70 न्यूज क्राइम की होती है। कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया। मगर मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि इफैक्टिड पार्टी को जस्टिस

मिलना चाहिए और वह सरकार का काम है। अगर सरकार इसमें फेल हो जाती है तो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो जाती है।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मैं जो हाउस में जो डिसकशन देख रहा था। खासकर बाली जी हमारे बड़े सीनियर मंत्री है। बाली जी जिस भी युग में हुए हैं बड़े चर्चित रहे हैं। रामायण युग में बड़े मस्कुलर थे तो सुग्रीव की घरवाली को लेकर गये थे और यहां हमारे बाली जी फाइनैंशीली बड़े स्ट्रोंग है। ये फाइनैंस को इधर-उधर करने में बड़े सक्षम है। मैं ज्यादा पर्सनली व्यंग्य नहीं करना चाहूंगा। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बाली जी इतने होशियार है कि इन्होंने ठेका ले रखा

16.3.2015/1740/ag/av/3

है कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रतिद्वन्दि पैदा नहीं होने देना। मैंने सारे-के-सारे कंडक्टर ही बना देने।

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

16.3.2015/1745/negi/ag/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर ..जारी..

अगर बाली जी बनाना है तो उनको डॉक्टर बनाइये, इंजीनियर बनाइये, एच.ए.एस. बनाइये और अध्यापक बनाइये। क्या आपने सारे कंडक्टर ही बनाने हैं? पहले कंडक्टर्ज़ के इन्टरव्यु हुए, 700 के 700 नगरोटा वाले सारे मैरिट में आ गए। आपने उनको कौन सी ट्रेनिंग दे रखी है जो बाकियों को पता ही नहीं है । कंडक्टर बनने में क्या वहां के लोग सारे एक्सपर्ट हैं? कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही चुनाव क्षेत्र के सारे लोग 80 के 80 नम्बर ले करके कंडक्टर बन जाएं। फिर आपने एक और तरीका निकाल दिया। आप क्या समझते हैं कि जो यह हाऊस बैठी है इसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है ? हम सबको पता है कि आप कर क्या रहे हैं । आप कह रहे हैं कि कंडक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है । कंडक्टर की क्या ट्रेनिंग होती है ? उन्होंने तो पंच लगाना है और पैसे क्लैक्ट करने हैं। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट-ऐड की ट्रेनिंग होती है । आपने जितने कंडक्टर बुलाए हैं जिनके पास फर्स्टएड की ट्रेनिंग है उनको ही बुलाया है, उसके बाद आपने उनको क्या ट्रेनिंग देनी है? ऐसा नहीं है। आपने बैकडोर एन्ट्री का एक मीडिया बनाया। जहां भी इन्टरव्यु हो रहे हैं हर जगह नगरोटा वाले उसमें पहुंच रहे हैं। बाली जी मेरा आपसे यह रिक्वैस्ट है अगर आप पब्लिक को यह इमेज़ दे रहे हैं कि हम इस ढ़ंग से

कंडक्टर भर्ती कर सकते हैं । इस तरह से क्या मैसेज़ जा रहा है? क्या यह करप्शन नहीं है ? लोग क्या सोचेंगे? देश का नौजवान क्या सोचेगा कि कंडक्टर्ज़ की भर्ती हो रही है और नगरोटा वाले सारे भर्ती हो रहे हैं क्या बाकी लोग कैपेबल नहीं हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें पारदर्शिता लाइये। जो आदमी डिज़र्ब करता है, जो आपने इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया है और जो आदमी उसमें फॉल करता है उसको लीजिए। आप जबरदस्ती कंडक्टर बनाने की बात मत करिये। इस तरह से पूरे स्टेट में मैसेज़ बिल्कुल गलत जा रहा है। यह क्लीयर कट क्वैश्चन उठ रहा है और इसमें कोई दोराय नहीं है ।

16.3.2015/1745/negi/ag/2

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि पिछली बारिश से एक पुल गिर गया। लाहौल में 4.5 करोड़ रूपये का पुल बना था । मुख्य मंत्री जी मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा हूं। 4.5 करोड़ रूपये का एक पुल गिर गया। पेपर में आया कि पुल गिरने की वजह रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकार्ड दी है, पुल के ऊपर बर्फ पड़ गई और वह पुल गिर गया। जिस पुल के ऊपर 20-20 टन के ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं और बारिश से पुल गिर जाए यह बात ठीक नहीं है। लेकिन यह पेपर में आया है, पेपर में यह न्यूज़ थी कि बर्फ से पुल गिर गया। इस पुल को बनाने में बड़े लारज़ स्केल में धांधली हुई है । मेरा आपसे निवेदन है, यह छोटा-मोटा एमॉउन्ट नहीं है । जो दोषी हैं उनको इमिडिएटली सस्पैंड किया जाए। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि हम इस प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने देना है तो ऐसे-ऐसे जो इंसिडेन्ट आते हैं आप उनपर स्ट्रिक्टली ऐक्शन लें। जो गलत रिपोर्ट महकमें वाले दे रहें हैं उनके ऊपर भी आप ऐक्शन लीजिए और जिसने भी वह पुल बनाया है उसको भी आप सख्त से सख्त सजा दीजिए। यह केवल एक इंसिडेन्ट नहीं है ऐसे बहुत सारे इंसिडेन्ट्स हैं जिनके बारे में यहां इस मान्य सदन में चर्चा हो चुकी है । आप इनको लाइट्ली मत लीजिए और मज़ाक में मत लीजिए। हाऊस में जो चर्चा हुई है, यहां से भी हंसते हैं और वहां से भी हंसते हैं। यह हाऊस स्टेट को लीड कर रहा है। यह हाऊस स्टेट को एक मैसेज़ दे रहा है । यहां से क्या मैसेज़ जाएगा पब्लिक उसको फोलो करेगी । तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जिन्होंने यह किया है, चाहे वह कोई भी है, चाहे आपका चाचा है और चाहे हमारा भतीज़ा है, सबको इसमें बराबर की सज़ा होनी चाहिए।

तीसरा, सुजानपुर सब-डिवीजन की एक बात है। पीछे मैंने क्वैश्चन भी किया था । क्वैश्चन नम्बर है-679, Dated 11.12.2014 मैंने क्वैश्चन किया था कि ऐसे कितने एग्रीमैन्ट सुजानपुर सब-डिविजन में किए गए जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैटीरियल ठेकेदारों को दिया गया? इसका जवाब आया कि 40 ऐसे एग्रीमैन्ट थे

16.3.2015/1745/negi/ag/3

जहां फ्री ऑफ कॉस्ट मैटीरियल ठेकेदारों को दिए गए और टोटल कॉस्ट बनी 38 लाख रूपये। आगे मेरा प्रश्न यह था कि Whether the Government has authorized PWD sub-division, Sujanpur to issue the PWD material to contractors free of cost, if so, the copy of the same be given to me? इसके जवाब में लिखा है नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ नहीं हैं। Whether such type of practice is applicable in other divisions of the Department in the State? इसके जवाब में भी बोला है- नहीं। सिर्फ एक ऐसा सुजानपुर सब-डिविजन है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैटीरियल दिया जा रहा है। सुजानपुर का जो एस.डी.ओ. है उसको किसने अथोराइज्ड़ किया है और किसके प्रैशर पर आ करके वह दे रहा है? उसके ऊपर न अभी तक कोई इन्क्वायरी हुई है और न उस एस.डी.ओ. को सस्पैंड किया गया है । मुझे तो यह सुनने में आया है कि उसके बाद भी, जब इस मान्य सदन में यह रिप्लाई आया, वही प्रोसीज़र वहां पर फोलो किया जा रहा है । उसमें टैक्स बचाया जा रहा है। मन मर्जी के ठेके दिए जा रहे हैं और वहां पर घोटाला किया जा रहा है । तो मैंने ये 3 इंसिडेन्ट्स आपको स्टेट में करप्शन के बारे में दिए हैं ,

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

16/03.2015.1/750यूके/एजी/1

श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर---जारी----

सरकार कितनी सजग है, ये मैने 3 इन्स्टांस आपको इसके बारे में दिए हैं । इसके बाद शिक्षा के बारे में यहां पर बड़ा लिखा हुआ है । मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा । लेकिन आप जो स्कूल खोल रहे हैं ,उसका बेसिक परपज़ क्या है? आप कितने स्कूल खोल रहे हैं, इतने कॉलेज आप अपग्रेड कर रहे हैं । लेकिन उनमें पढ़ने वालों की संख्या हर बार कम हो रही है । इस सिस्टम को आप अब बदल दो । यह सिस्टम एक ऐप्लीकेबल नहीं है । इसके लिए सरकार को कोई नयी पॉलिसी लानी

पड़ेगी । 10साल पहले प्राईवेट स्कूलों में 16% बच्चे पढ़ते थे, अब वह 34% हो गए हैं । अगले 10 साल में वह 65% हो जाएंगे और सरकारी स्कूलों कोई बच्चा पढ़ने जाएगा ही नहीं । इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? हर साल अरबों-करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जा रहा है । लेकिन हर बार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है । क्या सरकार इसके बारे में चिंतित है? कोई चिंता की है, इसके बारे में? यह जो पैटर्न पीछे से चला हुआ है 50 या 100 और प्राईमरी स्कूल खोल दिए । दो कॉलेज और बढ़ा दिए, 4 को अपग्रेड कर दिया । 4 पैरा-टीचरों को प्रोमोशन दे दी गई । क्या इससे आपका ऐजुकेशन सिस्टम सुधर जायेगा? मुख्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस ऐजुकेशन सिस्टम में हमारा लैवल इतना डाऊन चला गया है कि कोई मजबूर मां-बाप ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं । सिवाय कोई अलटरनेटिव के ,कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है । तो मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ, मैने जो इस अभिभाषण में सरकार का लेखा-जोखा देखा है, सरकार का ऐसा कोई भी कार्य मुझे नहीं लगा है जिसको मैं एपरीशिएट करुं । सरकार अपने दो साल के कार्यकाल में पूरी तरह से टोटली फेल हुई है और मैं इसका समर्थन नहीं करता । धन्यवाद ।

16/03.2015.1/750यूके/एजी/2

अध्यक्षः अब इस सदन में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने दो साल के अरसे के बाद सदन के अन्दर किसी चर्चा में भाग लिया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 25 दिसम्बर 2012 ,को सत्ता संभाली तथा तभी से कड़ी मेहनत कर सरकार ने इन दो वर्षों की अवधि में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं । कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया गया तथा इसमें किए गए अधिकांश वायदों को सरकार ने पहले ही पूरा कर

लिया है । हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारा चुनावी घोषणा-पत्र है, उसको एक या दो साल के अन्दर ही पूरा नहीं करना है । इसको 5 साल की अवधि के अन्दर पूरा करना है । बहुत से काम हो गए हैं, बहुत से काम अभी करने को बाकी हैं और हम चाहते हैं कि इससे पूर्व कि इस विधान सभा की अवधि पूरी हो, उससे पहले हम वह सारी बातें जो हमने घोषण-पत्र में लिखी हैं, उनको पूरा करेंगे और इसके बारे में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए । मैं आलोचना से नहीं डरता हूं । आलोचना से हमको कई जानकारी मिलती हैं, ज्ञानवर्द्धन होता है और बहुत सी बातें जो हमें मालूम नहीं होती हैं, वह भी मालूम हो जाती हैं । लेकिन आलोचना किसी तथ्य के आधार पर होनी चाहिए । Criticism for the sake of criticism. यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । क्योंकि हम विपक्ष में है, इसलिए हमको आलोचना करनी है । अगर तथ्य नहीं हैं तो कोई न कोई नए तथ्य गढ़ने हैं और राई का पहाड़ बनाना है । यह कोई आलोचना नहीं होती । आलोचना तथ्यों पर होनी चाहिए । फैक्ट्स और फिगर्स के साथ होनी चाहिए ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1755/sls-jt-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

और महज कहीं एक घटना घट गई और कहें कि ऐसी घटनाएं सारे प्रदेश में घट रही हैं ,वह बात गलत है। जहां तक कानून-व्यवस्था की बात कही गई है, मुझे यह कहते हुए कोई गुरेज़ नहीं है कि पिछले दो वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। क्राईम ग्राफ नीचे गिरा है, बढ़ा नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात होती है कि कभी-कभी कहीं-कहीं कुछ घटनाएं घट जाती हैं ,चोरी-डकैती भी होती है, रेप भी होते हैं ,मर्डर भी होते हैं ,मगर अगर इक्का-दुक्का ऐसी बातें होती हैं ,उसके आधार पर यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी स्टेट में रेप्स हो रहे हैं ,मर्डर हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है। हमने कभी नहीं कहा कि Himachal Pradesh is a crime free State. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि हमारा जो क्राईम रेट है ,और राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है और पिछले दो वर्षों के अंदर क्राईम रेट घटा है। मेरे पास आंकड़े हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं । Whereas in 2011-2012, 244 murder cases were registered. Only 235 cases have been registered in 2013-2014. यानी इसमें गिरावट आई है। सुनिए। The theft and burglary cases in the same time period have gone down by 444 cases. Vehicles have been sanctioned to the three Women Police Stations.

इसका ज़िक्र किया था। ठीक है कि पुलिस थाने अभी नए-नए बने हैं। पहले हमने उनके आवास का प्रबंध किया और उनके लिए गाड़ियां भी सैंक्शंड हैं, उनकी प्रोक्योरमैंट में थोड़ा समय लगता है। हमने उनको पुरानी गाड़ियां नहीं दी हैं, नई गाड़ियां सैंक्शन की हुई हैं। We have sanctioned new vehicles to them. विशेषकर उनके लिए यह गाड़ियां उपलब्ध होंगी। यहां पर रवि जी ने किन्नौर के रेप केस के बारे में ज़िक्र किया। The Police has filed challan on 10.04.2014. The case has been solved and challan is already in the court of law. इसलिए केवल क्रिटिसिज्म करने के लिए बातों को बढ़ा-चढ़ाकर करना सही नहीं होता। दूसरी बात यहां पर शिक्षा के क्षेत्र के बारे में हुई है कि हमने बहुत स्कूल खोले हैं, आदि-आदि। मुझे खुशी है कि हमने स्कूल खोले हैं। I believe in opening of

16.03.2015/1755/sls-jt-2

educational institutions. और हमारी नीति रही है कि प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, जहां-जहां ज़रूरत है, वहां स्कूल खोले जाएं। हमने दूर-दराज के इलाकों में जहां सड़क नहीं है ,जहां कोई स्कूल नहीं है और जहां पर ग्लेशियर प्वांयट है वहां पर 3-2बच्चों के लिए प्राईमरी स्कूल खोला है। हम चाहते हैं कि क्योंकि हरेक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है ,इसलिए उसको शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। कई आलोचना करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 10-15 बच्चों के लिए स्कूल खोला है। जहां तक मैं समझता हूं, अगर 2 बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी स्कूल खोलेंगे अगर उनके घर के नजदीक कोई ऐसा स्कूल नहीं है। यह हमारी नीति है। हो सकता हैा कि आप इसमें विश्वास न करते हों। हमारी सरकारों द्वारा भारी मात्रा में स्कूल खोले गए हैं। बल्कि जब आपकी सरकार बनी, आप आए तो आपने कई स्कूल बंद कर दिए और सब स्कूलों के अंदर सिंगल अध्यापक की व्यवस्था की। यह ठीक है, प्राईमरी स्कूल का मैन्अल है कि एक प्राईमरी स्कूल के अंदर कितने अध्यापक होने चाहिए। मगर जहां पर दूर-दराज के इलाके हैं और जहां पर किसी वजह से वहां का विद्यार्थी निकटतम स्कूल में नहीं जा सकता..

जारी ..गर्ग जी

16/03/2015/1800/RG/JT/1

मुख्य मंत्री------क्रमागत

एक प्राथमिक पाठशाला में कितने अध्यापक होने चाहिए। मगर जहां दूर-दराज़ के इलाके हैं और किसी कारण से वहां का विद्यार्थी निकटतम स्कूल में नहीं जा सकता, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएं और हमें इस बात का फख्र है कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमारी यह नीति रही है कि हरेक बच्चे के घर के नजदीक स्कूल होना चाहिए और उसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी वजह से आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश जब बना था, तो कहां था? शिक्षा में सबसे पीछे था ,लेकिन आज हमें फख्र है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल आज देश के उन राज्यों की गिनती में है जोकि शिक्षा के क्षेत्र में पहली पंक्ति में है। इस बात की हमें खुशी है। आप भले ही इसको बुरा समझते हों , लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर इनवेस्टमेंट करेंगे। जहां-जहां स्कूल आवश्यक होंगे ,उन्हें खोला जाएगा, जहां स्कूलों को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी , उनको किया जाएगा और जहां कॉलेज की जरूरत होगी, वे खोले जाएंगे। इसमें कोई गलत काम नहीं है। कांग्रेस की शुरू से ही यह नीति रही है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उसी नीति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सर्दियों में जो हमारे यहां त्रासदी हुई है ,अभी हाल में जो बर्फबारी हुई है ,अधिक वर्षा हुई है ,उससे सड़कें टूटी हैं ,बिजली के खम्बे टूटे हैं जिसके कारण जनता को तकलीफ हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर क्षेत्र में कहीं-न-कहीं ऐसी बातें हुई हैं। मगर सरकार ने और विभागों ने जल्दी-से-जल्दी इस स्थिति को रेस्टोर करने की कोशिश की है। कई स्थानों पर देर भी हुई है। पिछले दिनों में चौपाल में बिजली की लाईन टूट गई। वह बीच जंगल में होकर जाती थी। जिसके कारण 10-15 दिन चौपाल के लोगों को बिजली नहीं मिली क्योंकि सारे तार और खंबे टूट गए थे जोकि घने जंगल के बीच से होकर जाते थे। लेकिन वहां के लोगों ने विभाग के लोगों के साथ मिलकर मदद की और लाइन्ज को ऑबस्ट्रक्शन से_ रिमूव करने में मदद की जिसकी वजह से जो काम 30दिन में होना था ,वह 10-15 दिन में हो गया। तो यह ऐसा होता है। बेमौसमी बर्फबारी हुई है ,भारी बर्फबारी हुई है, वर्षा हुई है ,सड़कें अवरूद्ध हुई हैं ,ये सब हुआ है। This is an act of nature. यह किसी के हाथ की बात नहीं है। मगर जब हुआ है, तो हमारी सरकार ने स्थिति को सुधारने में और पूर्व स्थिति को वापस लाने में पूरी कोशिश भी की है और कर रही है।

16/03/2015/1800/RG/JT/2

हो सकता है कि कहीं गफलत भी हुई होगी। जो काम एक दिन में होना चाहिए, उसमें दो दिन लग गए ,कहीं दो दिन में काम होना चाहिए, तो तीन दिन लग गए , ऐसा हो सकता है। मगर जो हमारे विभाग हैं चाहे हमारा बिजली विभाग ,लोक निर्माण विभाग या सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने तुरन्त इस ओर कदम उठाए और यथाशक्ति उन्होंने इस स्थिति का मुकाबला किया और पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की है। हमको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए न कि हम यहां खड़े होकर उनकी आलोचना करें कि कुछ नहीं हुआ, 15 दिन बिजली बंद रही ,पानी बंद रहा या सड़क बंद रही। यह तो उनका पता है कि स्थिति क्या थी? उन्होंने कम-से-कम समय में पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की है। जहां कोताही भी हुई है ,यह भी हमारे ध्यान में है ,उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हम विपक्ष की इस बात को सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भविष्य में वे लोग ऐसी कोताही न करें।---------- जारी

एम.एस. द्वारा जारी

16/3/2015/1805/Ms/JT/1

मुख्य मंत्री जारी----------

अभी अस्पतालों का जिक्र हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अन्दर न केवल अस्पताल और पैरा-मेडिकल सर्विसिज का एक्सपैंशन हुआ है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है। जहां पहले एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज होता था , उसके बाद टांडा में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। वहां सुपर स्पेशियल्टी की व्यवस्था हुई है। इसी तरह से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी सुपर स्पेशियल्टी के लिए लगभग 170 करोड़ रूपया खर्च किया जा रहा है जो भारत सरकार से आया है। अब वहां सुपर स्पेशियल्टी वार्ड बनकर तैयार हुआ है और फंक्शनल भी हो गया है। इसके अलावा तीन और नये मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इन्हें सिर्फ कागज पर ही स्वीकृति नहीं दी है बल्कि प्रति कॉलेज 190 करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ है। इसमें एक कॉलेज चम्बा में, दूसरा हमीरपुर में और तीसरा नाहन में खोला जा रहा है। हमारे लिए सारा हिमाचल एक है। हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, ऊपर का हिमाचल और निचले हिमाचल में विश्वास नहीं करते। हम नया हिमाचल और पुराना हिमाचल में भी विश्वास नहीं करते। हमारे लिए सारा हिमाचल एक है और देश एक है। जो लोग महज अपने राजनीतिक फायदे के

लिए लोगों को भाषा, जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं वे कभी भी देश और प्रदेश के हितैषी नहीं हो सकते। इस बात को हमें याद रखना चाहिए।

अभी रविन्द्र जी ने कोई दस्तावेज दिखाए कि इसमें किसी की एप्लीकेशन है जिसे वीरभद्र सिंह ने स्वीकृति दी है। मैं इतना अनगढ़ आदमी नहीं हूं। हम इसको देखेंगे। इसमें कहीं फॉर्जरी भी हो सकती है। हम इसको देखेंगे कि क्या है और मैंने कभी भी किसी के कहने से कि किसी की सांई विचारधारा है या फलां काम करता है, को कभी तरजीह नहीं दी। हां, किसी के खिलाफ शिकायत है या काम ठीक से नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत सी शिकायतें स्कूल मैनेजमैंट कमेटी से आती हैं। यहां तक कि

16/3/2015/1805/Ms/JT/2

कई विद्यार्थी इसके बारे में पत्र लिखते हैं और ग्राम पंचायतों के लोग भी पत्र लिखते हैं। ऐसे में सरकार का कर्त्तव्य है कि उसके बारे में जांच करे और उसके बारे में आवश्यक कार्रवाई करे। एक गुमनाम पत्र के आधार पर न मैंने कभी काम किए हैं और न कभी करूंगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

इसी तरह से यह कहना कि सब-कुछ बुरा है। इससे लगता है कि बोलने वाले का दिमाग बन्द है। कमियां भी हो सकती हैं और त्रुटियां भी होती हैं, मैं इस बात को मानता हूं। आखिर हम सब इन्सान हैं और काम करने वाले भी इन्सान हैं। अधिकारी भी इन्सान हैं। त्रुटि हो सकती है मगर यह कहना कि सब-कुछ खराब है और अच्छा कुछ नहीं है ,सही नहीं है। इस किस्म का जो दृष्टिकोण है यह प्रजातंत्र में नहीं होता है। जहां तानाशाही होती है, ऐसी हुकूमतों में, ऐसी विचारधाराओं में ऐसी बातें होती हैं। Everything is not black; everything is not white. There are different shades of things. ...(व्यवधान)... आपने काफी बोल दिया। I am not yielding.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, देहरा में मैं जंहा रहता हूं वहां पर मैंने किराये पर मकान लिया हुआ है। (व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं? मुझे इस बात का पता नहीं है। यानी आप मुझे सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान) बताओ?

श्री रविन्द्र सिंहः देहरा से जहां से मैं अभी विधायक हूं। वहां मैंने किराये पर मकान लिया है। मुझे लगभग एक साल का समय इस मकान को लिए हुए हो गया है। जहां मैंने मकान किराये पर लिया तो जिस दिन मैंने वहां पूजा-अर्चना की, वह मकान मालिक आकर मेरे साथ पूजा-अर्चना में बैठ गया।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

16.3.2015/1810/जेके/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंहः---------जारी-------

बेसिकली वह मझीन के रहने वाले हैं। ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र के हैं। श्री संजय रतन जी जानते होंगे वह पहलवान परिवार है और कम से कम 45 वोटे हैं और सारे का सारा कांग्रेसी परिवार है। लेकिन वह मेरे साथ पूजा में बैठा और आपने उसके ऑर्डर दूसरे दिन किन्नौर के लिए कर दिये।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता ही नहीं है कि माननीय सदस्य का मकान कहां पर है और किसके मकान में आप रहते हैं? यह सूचना मुझे आपसे प्राप्त हो रही है। यह ठीक बात नहीं है। आप गलत बात मत कीजिए। ऐसा आप मत बोलिये। आप क्या करते रहे? मगर we have not retaliated. और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यह बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मुझे यह भी पता नहीं है कि आपका मकान कहां पर है और किस आदमी से आपने मकान किराये पर लिया है? इस बात का मुझे बिल्कुल पता भी नहीं है। This House is not meant for such petty scuffles.

अभी श्री जय राम ठाकुर जी ने किसी केस के बारे में यहां पर जिक्र किया।।। am informed that the matter has already been resolved and the matter is in the court. यह बातें होती है। मैं नहीं कहता चाहे कोई भी सोसाईटी हमारे राज्य है और for that matter any State, any country is free of all crimes. क्राईम होते हैं। मगर सवाल यह है कि वह घटने चाहिए बढ़ने नहीं चाहिए। उनकी पूरी तरह से तफ़तीश होनी चाहिए और उसके मुताबिक उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं यह पहले भी कह चुका हूं कि दो वर्षों के अन्दर क्राईम रेट घटा है, बढ़ा नहीं है। चाहे मर्डर है, चाहे रेप है और चाहे दूसरे केसिज हैं उनमें कटौती हुई है बढ़ौत्तरी नहीं हुई है।

अभी यहां पर ई.एस.आई. हॉस्पिटल के बारे में जिक्र हुआ है कि उसमें करोड़ों रूपये खर्च हो गए हैं। ई.एस.आई. हॉस्पिटल हमने तो नहीं बनाया। It is by Labour Ministry. उन्होंने जगह छांटी। उन्होंने नेरचौक में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात

16.3.2015/1810/जेके/एजी/2

की। 600 करोड़ रूपया खर्च करके वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाया। सरकार बदली और जो भाजपा के श्रम मंत्री है, वे कहते हैं कि श्रम मंत्रालय का काम मेडिकल कॉलेज चलाने का नहीं है। जबकि 4-5 मेडिकल कॉलेजिज़ श्रम मंत्रालय द्वारा देश के अन्य भागों में चलाए जा रहे हैं। वे यहां पर एक खड़ा हाथी छोड़ गए हैं। राष्ट्र का कितना धन उस पर लगा है? महज़ सरकार के बदलने से पोलिसीज बदली है, जबकि उनके मंत्रालय ने ई.एस.आई. के अन्तर्गत नेरचौक में हॉस्पिटल बनाया है। वहां पर बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी है। उसमें अभी तक 600 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च हो गया है और आज यह कहे कि we have nothing to do with it. ठीक है, यदि नहीं है तो हमको दे दीजिए। हम कोई और मेडिकल मेडिकल कॉलेज चला देंगे । गवर्नमैंट महज़ सरकार बदलने के बाद यदि इस किस्म की बातें करें तो यह शोभा नहीं देती है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आपमें से किसी ने यहां पर ई.एस.आई. हॉस्पिटल का जिक्र किया था, वरना मैं इसके बारे में कहता भी नहीं।

इसी तरह से जैसे कि कुछ समय पहले रघुनाथ मन्दिर से मूर्ति की चोरी हुई है और वह बरामद भी हो गई है। उसमें भी राजनीति लाने की कोशिश की गई है। यह भी शक किया गया कि शायद चोरी हुई ही नहीं। हरेक चीज को लाईटली लेना यह शोभा नहीं देता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

16.03.2015/1815/SS-JT/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

रघुनाथ मंदिर एक आस्था का केन्द्र है। सारी कुल्लू की जो सभ्यता, संस्कृति है वह रघुनाथ जी के इर्द-गिर्द घूमती है और वहां के लोगों को बड़ा दुख पहुंचा, they were shocked, जब से यह चोरी हुई है। मगर मैं इसके लिए भी हिमाचल पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने फौरन सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी। जिसकी वजह से जिन चोरों ने चोरी की थी, जो मूर्तियों को लेकर जा रहे थे ,वे डर गये। यह खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है। उन्होंने उतर कर वहां पर सड़क के किनारे ही दो-तीन जगह पर मूर्तियां दबा दीं। रघुनाथ जी की मूर्ति एक जगह से मिली और दूसरे बर्तन

या जो अन्य मूर्तियां थीं वे और जगह मिलीं। मगर नज़दीक मिलीं। यह पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया। We were in touch with the Central Government and police agencies there. और उन्होंने भी किया। नेपाल गवर्नमैंट ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। उस मुलजिम को अरैस्ट किया और उसके बयान के आधार पर ही मूर्तियों के स्थान का पता लगा कि मूर्तियां कहां दबा रखी हैं। उसने इंडीकेट किया कि मूर्तियां कहां-कहां दबा रखी हैं उसके मुताबिक ही थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मूर्तियां बरामद हो गईं। इसमें कोई मजाक करने की बात नहीं है और यह कोई राजनीतिक इश्यु नहीं होना चाहिए। यह दुर्घटना की बहुत गलत बात हुई है। और मंदिरों में भी चोरियां हुई हैं, मुझे खुशी है कि पिछले दो-तीन वर्षों के अंदर जितनी चोरियां हुई हैं सब बरामद हुई हैं। मगर मूल प्रश्न यह है कि जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं चाहे वे बड़े मंदिर हैं या छोटे मंदिर हैं जो प्राचीन और ऐतिहासिक हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हर कदम उठाए जाने चाहिएं। जो उनकी मैनेजमैंट करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं उनकी हम हर प्रकार से मदद करेंगे कि वहां पर सी0सी0टी0वी0 कैमराज़ फिट किये जाएं। वहां पर ठीक से कुछ और प्रबन्ध किया जाए ताकि चोरी करना असम्भव हो जाए। अभी ज़िक्र किया है कि क्या सरकार इस मंदिर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहती है अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है मगर यह ज़रूर है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस किस्म की घटनाएं न घटें सरकार उसके लिए वहां पर इंतजाम करेगी। व्यवस्था के अंदर भी परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि फुल एकांउटेबिलिटी मंदिरों की हो। जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं उन सबकी एकांउटेबिलिटी होनी चाहिए। रक्षा होनी चाहिए। सम्वर्द्धन होना चाहिए। इस चीज़

16.03.2015/1815/SS-JT/2

को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ साल पहले ये कानून पास किया था, जिसके अन्तर्गत जितने भी प्राचीन मंदिर थे, उनका सरकार ने राजनीतिकरण नहीं किया, उनको नेशनलाईज़ नहीं किया बल्कि उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने कदम उठाए। एकांउटेबिलिटी के लिए कदम उठाए और उससे अच्छा इंतजाम चल रहा है। आज जितने भी मंदिर हैं चाहे नैना देवी जी का है ,चाहे भीमाकाली जी का है, चाहे वह चिंतपुरनी का है, चाहे बृजेश्वरी माता है, चामुण्डा है, सब के अंदर यह कानून आने के बाद एक व्यवस्था हुई है। एकांउटेबिलिटी हुई है। इन्कम,

एक्सपेंडीचर का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो वहां पर सोना, चांदी या जेवरात हैं उन सब की सूची बनाकर रखी गई है। उनको महफूज रखने का इंतजाम किया गया है। यह बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि आज मूर्ति की चोरी आम बात हो गई है। These are international gangs who are operating all these things. और एक-एक मूर्ति को ले जा कर करोड़ों रुपये में विदेशों में बेचते हैं। यह एक ऑर्गेनाइज़ गैंग है जो इस काम को करता है। इससे हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनको बचाने की आवश्यकता है..

जारी श्रीमती के0एस0

1/16.03.2015820/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी----

अध्यक्ष महोदय, श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने भाषण में स्कूलों से सम्बन्धित कई मामले उठाए। मैं कहना चाहूंगा कि आज कहा जा रहा है कि कई स्कूलों में एक ही अध्यापक है मगर 2012 में 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक ही अध्यापक था। उस समय विपक्ष की सरकार थी। अब स्थिति में सुधार हुआ है और अब ऐसे स्कूलों की संख्या घटकर 943 हो गई है। हमारी कोशिश है कि किसी भी स्कूल में सिंगल टीचर नहीं होगा । हम पूरी कोशिश करेंगें कि इस नए वित्तीय वर्ष के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाएगी की किसी भी प्राईमरी स्कूल में दो से कम अध्यापक न हो। मैं इस बात को मानता हूं कि जहां सिंगल टीचर होगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो सकती और यह तो आपके समय में भी होता था। 1442 स्कूलों में आपके सिंगल टीचर थे। जब आपने सत्ता छोड़ी तो उस वक्त यह हालत थी। अब स्थिति में सुधार हुआ है। आज भी कुछ स्कूल हैं जहां सिंगल टीचर है मगर हमारी कोशिश होगी कि इसको सुधारा जाए और हम नए स्कूल भी खोलेंगें आप चाहें कितनी आलोचना कर लें क्योंकि आज जो दूर-दराज के इलाकों के बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि उनको 10+1 स्कूल मिले, हाई स्कूल व मिडिल स्कूल मिले और वे घर की रोटी खाकर घर के नजदीक अपनी पढ़ाई कर सके और हम यह भी चाहते हैं कि कॉलेजिज़ भी खुले और वह शहरों में न खुले बल्कि दूर-दराज के इलाकों में खुले। हमने पिछले दो वर्षों के अंदर जहां-जहां कॉलेज खोले हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यह हमें अनुभव हुआ है। कई कॉलेजों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है क्योंकि दूर-दराज के क्षेत्रों में अगर कॉलेज न हो तो लड़कियां पढ़ाई से

1/16.03.2015820/केएस/एजी/2

वंचित रह जाती है । लड़कों को माता-पिता दूर भी पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं लेकिन लड़की वहां तक ही पढ़ सकती है जहां तक उसके घर के नज़दीक शिक्षा का प्रावधान है। अगर कॉलेज नजदीक नहीं है तो लोग लड़कियों को पढ़ाई करने से हटा देते हैं। मैंने देखा है कि आज चाहे शिलाई का कॉलेज हो या अन्य दूर-दराज के कॉलेज हो, वहां पर लड़कियों की संख्या बहुत है और एक-दो कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है तो यह अच्छी बात है। लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उनको वह मौका कभी नहीं मिल पाता अगर उनके घर के नज़दीक कॉलेज नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, कई लोगों के भाषण सुनकर आज मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं जानता हूं कि विपक्ष का काम आलोचना करना है मगर आलोचना भी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। राई का पहाड़ बनाना तो बुद्धिमत्ता नहीं है। हम आपसे तारीफ सुनना नहीं चाहते मगर अगर आप राई का पहाड़ बनाएंगें और हर चीज़ को बुरा कहेंगें, अच्छे को भी बुरा कहेंगें तो हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मगर आपकी अपनी विश्वसनीयता इससे खत्म हो जाती है। आप लोगों को भी विधायक बन कर दो साल व्यतीत हो चुके हैं और आपके मन में घुटन थी। पिछले सैशन में तो आप कुछ बोल ही नहीं पाए, हर वक्त वाक-आऊट करते रहे। कभी मुखौटे पहनकर काम करते रहे या हाऊस के अंदर कम और हाऊस के बाहर

1/16.03.2015820/केएस/एजी/3

ज्यादा बैठे। अब आपको बोलने का मौका मिला है तो आप पूरे दो साल की कसर निकाल रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2015/1825/jt/av/1

मुख्य मंत्री क्रमागत ----------

पूरे दो साल की कसर निकाल रहे हैं। आप अपना बैकलॉक क्लीयर कर रहे हैं। (---व्यवधान---) क्योंकि आपका इतना मधुर संगीत था और मेरे सामने धूमल साहब जी खड़े थे। उनके मनमोहक संगीत से मैं प्रभावित हो गया और मैं पहाड़ी आदमी हूं,

खुशी में नाचता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का भी आभारी हूं जिन्होंने यहां पर अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण में सरकार की नीतियां पढ़ी जाती है।

हां, अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि बजट के दौरान बोलूंगा मगर अभी बोल लेता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि we are passing through very difficult financial position in the State. There is no doubt about it. क्यों? एक तो आप देखेंगे 13वें वित्तायोग की बात है। उस वक्त आपकी सरकार थी। 13वें वित्तायोग में आपने कोशिश की होगी मगर उसका नतीजा यह निकला कि 13वें वित्तायोग का अवार्ड आज तक के अवार्ड से सबसे घटिया था। (---व्यवधान---) मैं सब कमीशन जानता हूं। 9वें की बात भी करुंगा, डे की भी करुंगा और नाइट की भी करुंगा; हर चीज की करुंगा। मैं कह रहा था कि उस कमीशन में आपने कोशिश की होगी।। don't doubt it. मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। 13वें वित्तायोग ने हिन्दुस्तान के जितने भी राज्य हैं; यहां तक कि त्रिपुरा से भी कम फाइनैंशियल एलोकेशन हिमाचल प्रदेश को की थी जिसकी वजह से आर्थिक संकट पैदा हुआ। फिर यह हुआ, उस दौरान विधान सभा के चुनाव होने थे और आपने क्या किया? आपने वोट की राजनीति करके और मुलाजिमों को खुश करने के लिए पंजाब की केबिनैट ने अपने मुलाजिमों के लिए जो वेतन वृद्धि की वह आपने भी पूरे हिमाचल में लागू कर दी। हमारी कमिटमैंट क्या है? मुलाजिमों के साथ हमारी कमिटमैंट यह है कि पंजाब के पे कमीशन के मुताबिक उनको सैलरी देनी है। पे कमीशन जो रिकमैंड करता है हम उसको अडोप्ट करते हैं। उस दौरान पंजाब में चुनाव हो रहे थे और वहां की सरकार ने अपने राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक केबिनैट सब कमेटी

16.3.2015/1825/jt/av/2

बनाई। उस केबिनैट सब कमेटी ने और वेजिज दे दिए। हमने भी हिमाचल में चुनाव के वक्त इम्पलॉइज को दे दिए जिसका हिमाचल सरकार पर 1300 करोड़ रुपये का असर पड़ा। Government should never panic. उससे क्या हुआ? सारी व्यवस्था बिगड़ गई। कहां तो हम यह बात करते थे कि एक वक्त ऐसा आयेगा जब हिमाचल प्रदेश का अपना पे कमीशन होगा। मगर यहां हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गई। यहां जैसे ही चुनाव आये भाजपा ने सोचा कि अब उनकी नैया डामा-डोल हो रही है। इन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को खराब किया और

प्रदेश के लोगों पर एक आर्थिक बोझ डाला। अब आगे क्या स्थिति है? आप जानते हैं कि पहले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और प्रदेश में अपना एक प्लानिंग कमीशन था। हमारे प्रदेश को स्पेशल केटेगिरी का दर्जा प्राप्त था। केंद्र से जो विभिन्न योजनाओं के अंदर सहायता आती है उसमें भी 90-10 को अनुपात था।----

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

16.3.2015/1830/negi/ag/1

मा0 मुख्य मंत्री महोदय .जारी..

उसमें भी 90:10 का रेशो था। 90 परसेन्ट केन्द्र का और 10 परसेन्ट हमारा । किसी में बाद में तरमीम भी हुआ और 80:20 भी हो गया और कुछ स्कीमों में 60:40 भी हो गया। मगर वो चीज़ थी । आज नीति आयोग बन गया है । मैं भी उसका सदस्य हूं। As Chief Minister, I am Member of NITI Aayog, but frankly I don't know what NITI AAYOG is. जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, जब तक उसका स्पष्टीकरण न हो, मगर उसके मुताबिक ,हमारा स्पैशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्ज़ा था, वह खत्म हो गया। जिसकी वजह से हिमाचल जैसे राज्य को बहुत आर्थिक क्षति हुई है। हमें आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में विशेष स्थिति है तो वह मिलेगा, क्योंकि वहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है । नार्थ-ईस्ट स्टेट्स को भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां के लिए भारत सरकार का एक अलग मंत्रालय है जो नोर्थ-ईस्ट स्टेट्स को देखती है और उससे भी उनको फंडज मिलते हैं। मगर सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल को हुआ है और उतराखंड को हुआ है । इन दो स्टेट्स को नुकसान हुआ है। आज मैं कह नहीं सकता कि कल क्या होने वाला है । पहले हमें मालूम होता था कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी स्कीम बनेगी उसमें हिमाचल प्रदेश क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, स्पैशल कैटेगरी स्टेट है उसकी वजह से हमें कोई रियायत दे देंगे। मगर जब स्पैशल कैटेगरी का स्टेटस खत्म हो गया तो उस करके जो रियायतें मिलती थी वो खत्म हो गई । तो अब हमारे लिए बहुत कठिन समस्या पैदा हो गई है । जिसके बारे में हमें ही नहीं, आपको भी सोचना चाहिए। वरना आज की तारीख में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान होने वाला है । भगवान करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं। । hope it doesn't happen. मगर आज इतना समय हो गया है ,केन्द्र सरकार का नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट भी पेश हो गया है । मगर उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि स्पैशल कैटेगरी स्टेट्स के अन्तर्गत जो अभी तक उनको रियायतें दी जा रही हैं, वे कायम रहेंगी या नहीं। ये रियायतें घटेंगी

या बढ़ेंगी, इसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है । इसलिए एक बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है । निसंदेह इसका असर हमारे बजट पर भी

16.3.2015/1830/negi/ag/2

पड़ेगा। मगर आज मैं यह कहना चाहूंगा इस मान्य सदन को, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, हम सब हिमाचली हैं, हमको हिमाचल के हितों की रक्षा करनी है। जो पिछली कांग्रेस सरकार ने हम जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए, पिछड़े राज्यों के लिए विशेष दर्जा प्रदान किया और जिससे हमें आर्थिक लाभ पहुंचा, वह कायम रहे। चाहे परिवर्तन कुछ भी हो, वो व्यवस्था कायम रहे। चाहे नाम उसका कुछ भी दिया जाए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। We should get together and plead with the Central Government to restore our financial status.

16.3.2015/1830/negi/ag/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 14वें वित्तायोग की चर्चा की है, जब बजट आएगा तो उसमें हम यह चर्चा करेंगे ही । आपने कहा कि यह सारे प्रदेश का मामला है और इसमें हम सबको मिल करके करना चाहिए। आज आप पहली बार यह अपील कर रहे हैं। हमने बार-बार कहा, मीडिया में भी कहा कि प्रदेश हित में हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सहयोग करेंगे, जो भी करने का होगा, भारत सरकार से बात उठाने की होगी ,हम करेंग । पर आप तीनों सीनियर लीडर यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं । रोहतांग टनल के शिलान्यास के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी आईं। मैंने उन्हें वहां भी कहा कि इंडस्ट्रीयल पैकेज़ जो खत्म कर दिया है उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1835/16.03.2015यूके/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल---जारी----

इंडस्ट्रियल पैकेज को खत्म कर दिया है । हमें बड़ा नुकसान हो रहा है । आज उद्योग मंत्री महोदय ने भी कहा कि इसके कारण जो फैसेलिटी मिलती थी वह बन्द हुई तो नुकसान हुआ । उन्होंने कहा । will speak to the Prime Minister. मैं दिल्ली

गया, मैने उनको फोन भी किया, उन्होंने कहा कि मैने कहा है । प्रधान मंत्री, डा0 मनमोहन सिंह जी से समय लिया । आदरणीय आडवाणी जी ने कहा मैं आपके साथ चलता हूं, मिलना चाहिए । उत्तराखंड के मुख्य मंत्री, हिमाचल से मैं और हमारे उद्योग मंत्री, श्री किशन चन्द कपूर जी, श्रीमती सुषमा स्वराज, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं, वे, श्री अरुण जेतली, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, वे, उन्होंने साथ चलने की बात कही । मैने आपको फोन किया, आप केन्द्रीय मंत्री थे । आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश इन्दौर, वहां आपका कोई कायक्रम था, जा रहा हूं, मैं नहीं आ सकूंगा । मैने श्रीमती विद्या स्टोक्स जी को फोन किया । ये नेता प्रतिपक्ष थे, इन्होंने इन्कार किया । इन्होंने कहा कि मैं भी नहीं आ सकती, मैं भी व्यस्त हूं । मैने ठाकुर कौल सिंह जी को फोन किया । ये सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, मैडम । इन्होंने भी कहा कि आनन्द शर्मा जी आ रहे हैं, हम उस दिन व्यस्त हैं, उस दिन नहीं आ सकते । बद्दी में कोई कार्यक्रम रखा हुआ था । लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमसे अपील होती है तो अपना किरदार भी याद करिए । हमने तो आपके कहे बगैर बार-बार कहा है कि प्रदेश हित में केन्द्र से जो भी बात करने की होगी, हम करेंगे क्योंकि यह सवाल कांग्रेस और बी0जे0पी0 का नहीं है, या किसी और पार्टी का नहीं है । सवाल प्रदेश का है । प्रदेश के लिए कुछ भी मिले, हमारा सहयोग हमेशा रहेगा । यह मैं कहना चाहता हूं ।

मुख्य मंत्रीः अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत । लेकिन कोई बात नहीं I take your words. I am sure you are sincere in what you are saying.

श्री प्रेम कुमार धूमलः खेत में भरपूर फसल है उसको संभालने की व्यवस्था करनी है।

/1835/16.03.2015यूके/एजी/2

मुख्य मंत्री : हां करेंगे । एक होता है राजनीति । वह अपने दायरे में रहती है । एक होता है प्रदेश का हित जहां सब मतभेदों को भुला कर in the larger interest of the State we should get together and plead to them. जो धूमल साहब जी ने खड़े हो कर के कहा कि he wants to say something which out of courtesy I allowed. I want to conclude my speech now.

अध्यक्ष महोदय, कहना तो बहुत कुछ था । बाकी बातें मैं बजट पर बोलूंगा । श्री महेन्द्र सिंह जी ने बहुत बातें कही हैं । ये बातों के धनी हैं । बातें करने में धनी है और जो कुछ खुद बड़े पैमाने पर करते रहे हैं उनका आरोप दूसरों पर डालते हैं । मैं इतना कहना चाहता हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं । मैं माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन में जो अभिभाषण दिया है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई है, हम उसको सर्वसम्मति से पास करें।

श्री रविन्द्र सिंहः सर, हम इसमें क्लैरिफिकेशन चाहेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्षः इस पर कोई चर्चा नहीं होती । इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती । गर्वनर एड्रेस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती ।(व्यवधान) No. There is no clarification on the Governor's Address. ...(Interruption)... गर्वनर एड्रेस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती There is no clarification. Kindly sit down. प्लीज़ ऐसा मत कीजिए । Please don't change the texture of the rules. ...(Interruption)... It is nowhere written in the rule book.

/1835/16.03.2015यूके/एजी/3

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसमें क्लैरिफिकेशन हो सकती है । जब पार्लियामैंट में हो सकती है । तो यहां पर भी हो सकती है ।
अध्यक्षः नहीं इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होगी । थोड़ा-बहुत कमैंट हो सकती है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

16.03.2015/1840/sls-jt-1
अध्यक्ष ...जारी
क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। कमैंट की बात ठीक है, थोड़ा-बहुत होते हैं । But there is no clarification.

मुख्य मंत्री : मैं यह कहना चाहता हूं, जब भी ये मेरे पास आते हैं तो मिश्री का गोला बनकर आते हैं मगर जब सदन में मिलते हैं तो इनका रूप कुछ और ही होता है।

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री महोदय, आपने हमें पहचानने में देरी कर दी। ...(व्यवधान) ...अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक तो हमने अपने वक्ता कम किए थे , इसलिए जो-जो विषय श्री महेन्द्र सिंह जी ने, मैंने, श्री जय राम ठाकुर जी ने,

श्री गोविन्द ठाकुर जी ने और श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने उठाये; यह विषय पहले भी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाए हैं और हमारे अन्य वक्ता भी इन पर बोले। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे आज कानून-व्यवस्था के ऊपर कहा ,यह इस प्रदेश का सबसे गंभीर विषय है। आपने एक रामपुर की घटना का उल्लेख करके बाकी सारी फाईल बंद कर दी। कांगड़ा में आप डेढ़ महीना रहे। डेढ़ महीने में 15 हत्याएं हुई हैं और रेप भी हुए हैं। उनका आपने कोई ज़िक्र नहीं किया।

Speaker: I will not allow this. This is wrong. No recording. This is wrong. एक बार आप बोल चुके हैं, अब भाषण देने की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

मुख्य मंत्री : मैंने कानून-व्यवस्था में रामपुर की घटना को लेकर जो कार्रवाई की बात कही है, उसी तरह की कार्रवाई सब केसिज में होती है और इसी में सारी बात आ गई है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सदन से वॉक आऊट करते हैं।

(विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

16.03.2015/1840/sls-jt-2

अध्यक्ष : मैं अब इस प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 2015 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, ह्दय से आभार प्रकट करते हैं

तो प्रश्न यह है कि इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 2015 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, ह्दय से आभार प्रकट करते हैं?

(प्रस्ताव स्वीकार)

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार 17 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांक :16.3.2015 **सचिव**